वर्ष 19
अंक 158
12 पृष्ठ
मूल्य 5 रुपये

गुरुवार, 20 अगस्त 2026

कोलकाता, चंडीगढ़, जयपुर, नई दिल्ली, भोपाल, **मुंबई** और लखनऊ से प्रकाशित।

डॉलर रु. 95.80 ▲ 0.1 रु.
यूरो रु. 111.10 ▲ 0.3 रु.
सोना (10 ग्राम) रु. 1,53,252 ▼ 211 रु.
सेंसेक्स 76909.70 ▼ 325.80
निफ्टी 24078.30 ▼ 76.60
निफ्टी फ्यूचर्स 24117.60 ▲ 39.30
ब्रेंट क्रूड 90.0 ▼ 0.1 डॉलर

भारत का पहला संपूर्ण हिंदी आर्थिक अखबार www.bshindi.com

बिज़नेस स्टैंडर्ड

वर्षों बाद चीनी आयात करेगा भारत!

सीएएस में हेरफेर के आरोप में दो संस्थानों पर सेबी की कार्रवाई

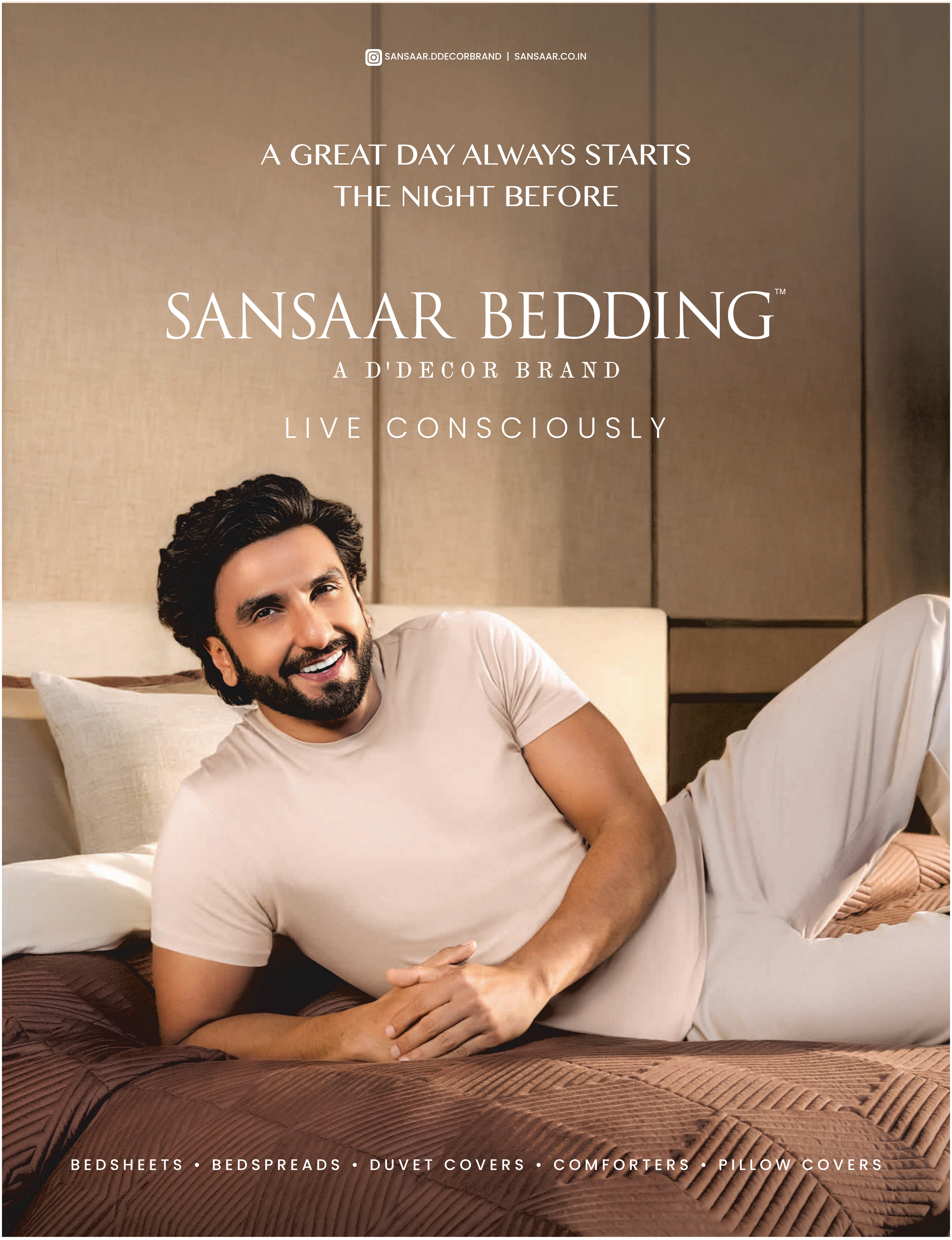

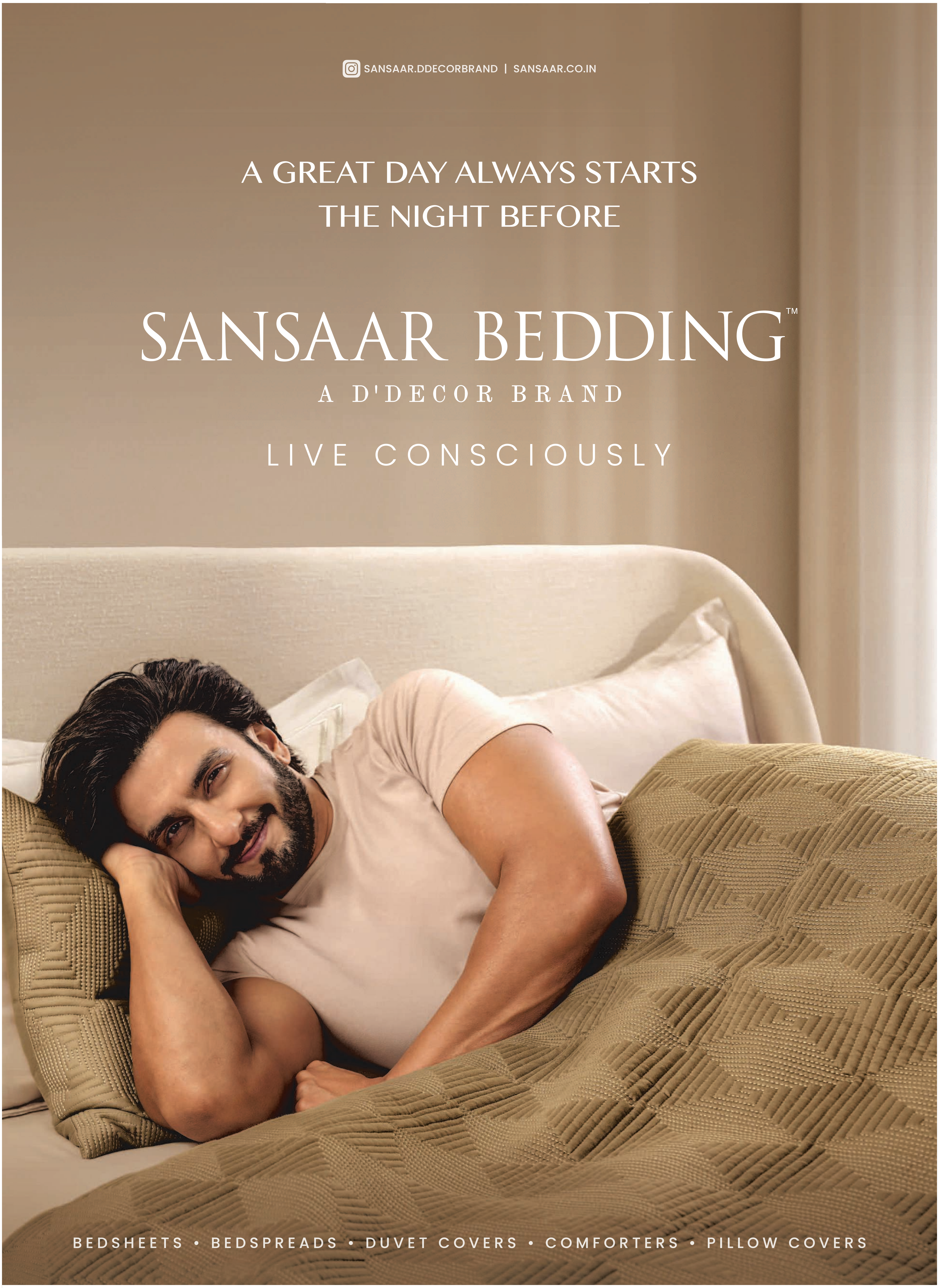

SANSAAR DEALERS: MUMBAI: The D'decor Store, Notan Heights, Near PWC Building, Station Road, Bandra (W): 022-61152530 | A to Z Bed N Bath, Dadar: 9920041219 | A To Z Life Style, Kalbadevi: 9322439452 | Akesha Furnishing, Mulund: 9821137053 | Arc One, Andheri: 9820291907 | Bharat Furnishings, Vile Parle: 9867330009 | Bichhavat, Juhu: 8291740401 | Crown Textiles, Kalbadevi: 9819630963 | Drapes and Tassels, Borivali: 9372474796 | Drapes and Tassels, Dadar, Hind Mata: 7808084747 | Girisons, Colaba: 9820064606 | Handloom Emporium, Goregaon: 9324433943 | J C Furnishing, Crawford Market: 9324869925 | Mahavir The Home Store, Santacruz (W): 9323125467 | Novelty, Bandra: 9820021657 | Otoba Furnishing, Chembur: 9820141705 | SJ Enterprises, Dadar: 7021415353 | Shiv Shakti Furnishings, Malad: 9321106533 | Vishal Furnishings, Chembur: 9769033508 | Zee Novelties, Vile Parle: 9029141494 | **NAVI MUMBAI (VASHI):** Draper, Sector 19/D: 7666287787 | Novelty Furnishings, Sector 1: 9820101076 | **THANE:** Akesha Furnishing, Ganeshwadi: 9699908999 | Anubhai Amarshi & Bros., Gokhale Road: 9821757576 | Decotex, Manpada: 9222004564 | Hargundas Tanumal, Ulhasnagar: 9822371730.

SCAN TO ENTER
THE WORLD OF SANSAAR

वर्ष 19
अंक 158
12 पृष्ठ
मूल्य 5 रुपये

गुरुवार, 20 अगस्त 2026

कोलकाता, चंडीगढ़, जयपुर, नई दिल्ली, भोपाल, **मुंबई** और लखनऊ से प्रकाशित।

भारत का पहला संपूर्ण हिंदी आर्थिक अखबार www.bshindi.com

बिज़नेस स्टैंडर्ड

पृष्ठ 2

प्रतिस्पर्धा आयोग ने प्रतिबद्धता नियमों में किया संशोधन

प्रह्लाद जोशी पृष्ठ 10

मुफ्त कोचिंग के लिए बन रहा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म

डॉलर रु. 95.80 ▲ 0.1 रु. | यूरो रु. 111.10 ▲ 0.3 रु. | सोना (10 ग्राम) रु. 1,53,252 ▼ 211 रु. | सेंसेक्स 76909.70 ▼ 325.80 | निफ्टी 24078.30 ▼ 76.60 | निफ्टी फ्यूचर्स 24117.60 ▲ 39.30 | ब्रेंट क्रूड 90.0 ▼ 0.1 डॉलर

कम रकम के एसआईपी खाते घटे

वर्षों की तेजी के बाद, कम रकम वाले एसआईपी में पहली बार दिखी गिरावट

अभिषेक कुमार
मुंबई, 19 अगस्त

कोविड के बाद म्युचुअल फंड में खुदरा निवेशकों की आमद बढ़ाने वाले छोटी रकम के सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान (एसआईपी) खातों की रफ्तार पिछले साल धीमी पड़ गई। वित्त वर्ष 2025-26 में 1,000 रुपये या उससे कम मासिक किस्त वाले एसआईपी खातों की संख्या 14 लाख कम हो गई, जबकि अधिक राशि वाले खातों की संख्या में इजाफा हुआ।

कम रकम वाली एसआईपी श्रेणी में कम से कम दो साल की जबरदस्त वृद्धि के बाद यह गिरावट आई है। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) के आंकड़ों से पता चलता है कि पिछले दो वर्षों में इस श्रेणी में 37 फीसदी और 16 फीसदी वृद्धि हुई थी।

जानकारों के मुताबिक 1,000 रुपये से कम मासिक किस्त वाले एसआईपी खातों में कमी की मुख्य वजह शेयर बाजार में उतार-चढ़ाव और सीधे निवेश वाले माध्यमों से निवेशकों का किनारा करना हो सकता है।

एक बड़ी फंड कंपनी के मुख्य कार्याधिकारी ने कहा, 'यह अनुमान के हिसाब से ही है। 2023 और 2024 में बाजार में आए बहुत से निवेशकों ने पिछला रिटर्न देखकर खूब पैसा लगाया। उनमें से कई ने सीधे ऐप के जरिये निवेशक किया और जब बाजार में उतार-चढ़ाव आया तो उन्हें रास्ता दिखाने वाला कोई नहीं था। कम आय वाले वर्ग में निवेशक जागरूकता कम है और इसीलिए ज्यादा असर उसी वर्ग पर दिख रहा है।'

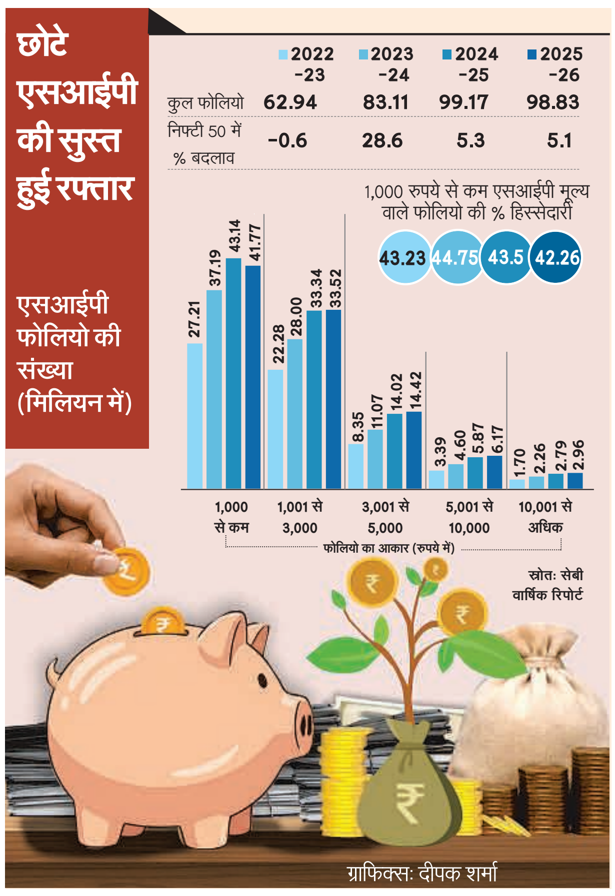

ग्राफिक्स: दीपक शर्मा

सेंट्रिसिटी के सह-संस्थापक पुष्पेंद्र सिंह ने कहा कि इस श्रेणी में आम तौर पर निवेशकों का आना-जाना ज्यादा होता है। उन्होंने कहा, 'इस श्रेणी के निवेशक अक्सर जल्दबाजी में फैसले लेते हैं। बाजार चढ़ता है तो इस श्रेणी के नए निवेश आ जाते हैं और गिरावट आते ही गायब हो जाते हैं। इस जमात के ज्यादातर निवेशक सीधे निवेश करते हैं और उन्हें रास्ता दिखाने वाला कोई नहीं होता। वितरक भी उन पर कम ध्यान देते हैं क्योंकि छोटी रकम के निवेश से उन्हें ज्यादा कमाई नहीं होती।'

शेयर बाजार में 2023 और 2024 में तेजी देखकर बड़ी संख्या में नए निवेशक आए थे, लेकिन पिछले दो साल उतार-चढ़ाव भरे रहे। निफ्टी 50 अब भी सितंबर 2024 के अपने उच्चतम स्तर से नीचे है, जबकि स्मॉलकैप और मिडकैप सूचकांक हाल ही में नई ऊंचाई पर पहुंचे हैं। इस बीच ज्यादा रकम वाले एसआईपी खातों की संख्या हर स्लैब में धीमी रफ्तार से ही सही, बढ़ती गई। (शेष पृष्ठ 3 पर)

एमपीसी सदस्यों ने दिए दर बढ़ाने के संकेत

मनोजित साहा
मुंबई, 19 अगस्त

- एमपीसी सदस्यों ने कहा कि आने वाले महीनों में महंगाई बढ़ने की आशंका है जिससे दर बढ़ाने की जरूरत हो सकती है
- खाद्य पदार्थों, ईंधन और अन्य कच्चे माल की ऊंची कीमतों का असर व्यापक महंगाई में बदलने का जोखिम है

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) की दर निर्धारण समिति के सदस्यों ने संकेत दिया है कि ब्याज दर में जल्द बढ़ोतरी हो सकती है क्योंकि आने वाले महीनों में महंगाई बढ़ने की आशंका है। यह बात मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की अगस्त में हुई बैठक के ब्योरे से पता चला है।

इसका सबसे स्पष्ट संकेत संभवतः आरबीआई की डिप्टी गवर्नर और मौद्रिक नीति विभाग की प्रभारी पूनम गुप्ता ने दिया। उन्होंने कहा, 'हेडलाइन मुद्रास्फीति के 2026-27 की तीसरी तिमाही में 5.9 फीसदी तक पहुंचने का अनुमान है, इसलिए साल के दौरान ब्याज दर बढ़ाना पड़ सकता है।' उन्होंने यह भी कहा कि मौजूदा परिस्थितियों में रीपो दर में और कटौती की गुंजाइश नहीं है।

छह सदस्यीय मौद्रिक नीति समिति ने अगस्त की बैठक में लगातार चौथी बार नीतिगत दर में कोई बदलाव नहीं करने का फैसला किया था।

आरबीआई के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने कहा कि समिति को सतर्क रहने की जरूरत है क्योंकि खाद्य पदार्थों, ईंधन और अन्य कच्चे माल की ऊंची कीमतों का असर व्यापक महंगाई में बदलने और मुद्रास्फीति के बढ़ने का जोखिम बना हुआ है। उन्होंने कहा, 'इन जोखिमों के किसी भी संकेत पर मौद्रिक नीति को सख्त करने की जरूरत पड़ सकती है।'

उन्होंने कहा कि पिछले साल औसत महंगाई दर केवल 2 फीसदी थी, जब रीपो दर को घटाकर 5.25 फीसदी कर दिया गया था। लेकिन इस साल हेडलाइन (समग्र) मुद्रास्फीति दर औसतन 3.93 फीसदी रही है। इसके अलावा कीमती धातुओं को छोड़कर कोर (मुख्य) महंगाई के इस वित्त वर्ष की अंतिम तिमाही में सामान्य कोर महंगाई के करीब पहुंचने का अनुमान है। 2026-27 में कोर महंगाई के औसतन 4.3 फीसदी रहने का अनुमान है। मल्होत्रा ने कहा, 'इससे दर में बदलाव की जरूरत हो सकती है।' एमपीसी ने फरवरी से दिसंबर 2025 के बीच रीपो दर में 125 आधार अंक की कटौती कर उसे 5.25 फीसदी कर दिया है। (शेष पृष्ठ 4 पर)

एक नज़र

चार रेल परियोजनाओं को हरी झंडी

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को रेल मंत्रालय की चार परियोजनाओं को मंजूरी दी। इन परियोजनाओं पर करीब 9,450 करोड़ रुपये की लागत आएगी। इनमें पश्चिम बंगाल के खड़गपुर से ओडिशा के भद्रक (रानिताल) के बीच 173 किलोमीटर लंबी चौथी रेल लाइन का निर्माण और ओडिशा में भद्रक से हरिदासपुर के बीच 75 किलोमीटर लंबी चौथी लाइन का निर्माण शामिल है। आंध्र प्रदेश के गुम्मिडीपुंडी से तमिलनाडु के गुडूर के बीच 90 किलोमीटर लंबी तीसरी और चौथी रेल लाइन बिछाने तथा ओडिशा में कटक से पारादीप (बदबांधा) के बीच 72 किलोमीटर लंबी तीसरी और चौथी लाइन बिछाने की परियोजना को भी मंजूरी दी गई है। मंत्रिमंडल ने 3,590.73 करोड़ रुपये की लागत से बिहार में मुजफ्फरपुर-सीतामढ़ी-सोनबरसा खंड के राष्ट्रीय राजमार्ग-22 को चार लेन के मानक के अनुरूप उन्नत करने की मंजूरी दे दी। इसे हाइब्रिड एन्यूटी मॉडल के तहत विकसित किया जाएगा।

ट्रक के लिए ईंधन दक्षता टूल दिसंबर तक

मझोले व भारी वाणिज्यिक वाहनों की ईंधन दक्षता और कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन को मापने के लिए भारत का पहला प्रमाणन टूल दिसंबर तक तैयार हो सकता है। ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एआरएआई) इसे 4 से 9 फरवरी, 2027 को होने वाले 'भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो' में लॉन्च करने का लक्ष्य बना रही है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी ने एआरएआई को सुझाव दिया है कि भारी वाहनों के लिए इस टूल का काम बीएस-VII के साथ जोड़ा जा सकता है। अधिकारियों ने बताया कि इसके दूसरे चरण में इलेक्ट्रिक वाणिज्यिक गाड़ियों की रेंज की गणना भी शामिल होगी। इससे सरकार को यह पता लगाने का एक स्टैंडर्ड तरीका मिल सकता है कि अलग-अलग स्थितियों में इलेक्ट्रिक ट्रक और बसें एक बार चार्ज करने पर कितनी दूर तक चल सकती हैं। पृष्ठ 4

आज का सवाल

क्या आयात से घटेंगे चीनी के दाम ?
www.bshindi.com पर राय भेजें।
आप अपना जवाब एसएमएस भी कर सकते हैं। यदि आपका जवाब हां है तो **Y** और यदि न है तो **N** लिखकर **57007** पर भेजें।

पिछले सवाल का नतीजा
क्या बैंक नोट के जरिये लेनदेन में तेजी से मुद्रा प्रबंधन पर बढ़ेगा दबाव?

हां	नहीं
85%	15%

व्यापार गोष्ठी

प्रधानमंत्री के स्वतंत्रता दिवस संबोधन पर आपकी राय?

अपनी राय पूरे पते के साथ हमें इस पते पर भेजें :
बिज़नेस स्टैंडर्ड, नेहरू हाऊस, 4 बहादुरशाह ज़फर मार्ग, नई दिल्ली-110002 फैक्स नंबर - 011-23720201 या फिर ई-मेल करें **goshthi@bsmail.in**

अपने विचार आप हमें **www.bshindi.com पर भी भेज सकते हैं**

सीएएस में हेरफेर के आरोप में दो संस्थानों पर कार्रवाई

खुशबू तिवारी
मुंबई, 19 अगस्त

- सेबी ने कॉपटॉल मॉरीशस इन्वेस्टमेंट और मानसी शेयर ऐंड स्टॉक ब्रोकिंग को प्रतिभूति बाजार में काम करने से रोक दिया
- इससे पहले सेबी प्रमुख ने कहा था कि सीएएस में हेरफेर करने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने तेजी से कार्रवाई करते हुए कॉपटॉल मॉरीशस इन्वेस्टमेंट और मानसी शेयर ऐंड स्टॉक ब्रोकिंग के प्रतिभूति बाजार में काम करने पर आज पाबंदी लगा दी। उन पर क्लोजिंग ऑक्शन सेशन (सीएएस) के दौरान हेरफेर वाले ट्रेड करने का आरोप था।

यह मामला 13 अगस्त को बंबई स्टॉक एक्सचेंज (बीएसई) पर सेंसेक्स अनुबंध के निपटान के दिन सीएएस के दौरान किए गए कथित हेरफेर वाले कारोबार से जुड़ा है। नियामक ने यह कार्रवाई कथित हेरफेर के महज छह दिनों के भीतर की है।

सेबी ने दोनों संस्थाओं द्वारा कमाए गए 3.67 करोड़ रुपये के कथित अनुचित लाभ को जब्त करने का भी निर्देश दिया है। इसमें कॉपटॉल मॉरीशस इन्वेस्टमेंट की कथित कमाई 2.96 करोड़ रुपये और मानसी शेयर ऐंड स्टॉक ब्रोकिंग की 71.64 लाख रुपये है।

नियामक ने दोनों संस्थाओं को आगे के आदेश तक इक्विटी सेगमेंट के सीएएस में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से भाग लेने तथा सीएएस के दौरान ऑर्डर देने, उनमें बदलाव करने या उन्हें रद्द करने से भी रोक दिया है। हालांकि मानसी शेयर ऐंड स्टॉक ब्रोकिंग के मामले में यह रोक केवल उसके प्रोपराइटरी ट्रेडिंग अकाउंट पर लागू होगी। इससे चंद घंटे पहले एक कार्यक्रम में सेबी के चेयरमैन तुहिन कांत पांडेय ने कहा कि हाल में शुरू किए गए सीएएस ढांचे में हेरफेर वाली किसी भी गतिविधि में शामिल प्रतिभागी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। (शेष पृष्ठ 3 पर)

वर्षों बाद चीनी आयात करेगा भारत!

संजीव मुखर्जी
नई दिल्ली, 19 अगस्त

चीनी में तेजी

- खपत उत्पादन से अधिक रहने से चीनी कीमतों में देखी जा रही है तेजी
- लगभग 10 लाख टन कच्ची चीनी का आयात करने की मिल सकती है अनुमति
- महाराष्ट्र में चीनी का भाव 5,400 से 5,560 रुपये प्रति क्विंटल के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है
- नवंबर 2025 में 15 लाख टन और बाद में अतिरिक्त 5 लाख टन चीनी के निर्यात की अनुमति देने के निर्णय पर उठ रहे सवाल

तकरीबन 10 साल के अंतराल के बाद भारत घरेलू बाजार में चीनी की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए लगभग 10 लाख टन कच्ची चीनी का आयात करने की तैयारी में है। महाराष्ट्र में चीनी की मिल स्तर पर कीमतें 5,400 से 5,560 रुपये प्रति क्विंटल के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई हैं।

मार्च 2026 से कीमतों में आई तेज बढ़ोतरी ऐसे समय हुई है जब देश में त्योहारों का मौसम शुरू होने वाला है और उस दौरान चीनी की खपत काफी बढ़ जाती है।

कीमतों में तेजी का मुख्य कारण यह बताया जा रहा है कि 1 अक्टूबर, 2025 से शुरू हुए 2025-26 सीजन में खपत उत्पादन से अधिक रही, जिसके चलते मिलों के पास उपलब्ध भंडार लगभग खत्म हो गया है।

कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि इस स्थिति के लिए 15 से 20 लाख टन चीनी के निर्यात की अनुमति देने का गलत फैसला भी जिम्मेदार है। उत्पादन के गलत अनुमान के आधार पर देश में चीनी की कमी की आशंका के बावजूद निर्यात की अनुमति दी गई।

नवंबर 2025 में सरकार ने पहले 15 लाख टन चीनी के निर्यात की अनुमति दी थी, जिसे बाद में अतिरिक्त 5 लाख टन बढ़ाकर 20 लाख टन कर दिया गया था।

उद्योग के अनुमान के मुताबिक इससे करीब 8 लाख टन चीनी देश से बाहर भेजी जा चुकी है। यह लगभग उतनी ही मात्रा है, जितनी मात्रा में भारत अब मिलों को कच्ची चीनी आयात करने की अनुमति देने की योजना बना रहा है।

उद्योग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, 'यह साफ तौर पर पता चलता है कि कोई न कोई तंत्र को गुमराह कर यह यकीन दिला रहा था कि देश में चीनी की पर्याप्त उपलब्धता है जबकि वास्तविकता यह थी कि उत्पादन खपत की भरपाई नहीं कर पा रहा था।'

उन्होंने कहा कि इसकी वजह यह है कि फरवरी 2026 तक जब पेराई का सीजन शुरू हुए लगभग 4 से 5 महीने हो चुके थे, तब भी पहले से मंजूर 15 लाख टन के अतिरिक्त 5 लाख टन के निर्यात कोटा की अनुमति दे दी गई।

उक्त अधिकारी ने आगे बताया, 'हमें जानकारी है कि आपूर्ति का संकट मार्च से ही शुरू हो गया था और मिलों को अपने मासिक घरेलू बिक्री कोटे को पूरा करने में मुश्किल हो रही थी। जब कीमतें लगातार बढ़ रही थीं, तभी सतर्क हो जाना चाहिए था।'

उद्योग सूत्रों के अनुसार भारत ने इससे पहले 2016-17 सीजन में कच्ची चीनी के आयात की अनुमति दी थी। (शेष पृष्ठ 4 पर)

kotak
Kotak Mahindra Bank

EUROMONEY AWARDS FOR EXCELLENCE 2026
INDIA
BEST BANK FOR LARGE CORPORATES

Things that surprise no one.

- Another Indian becomes global CEO
- AI dominates boardroom discussions
- Kotak Mahindra Bank wins again

Kotak Mahindra Bank has been named **Best Bank for Large Corporates** at the prestigious **Euromoney* Awards For Excellence 2026**. For the third time in a row. Not just that, Kotak has also been named **India's Best for Securities Services**. Thank you Euromoney. And thank you clients for choosing us as your banking partner. We're truly honoured by these awards, but we're even more honoured by your continued trust in us.

*Euromoney is a leading provider of competitive intelligence and certification for the global banking and finance industry.

खबरों में रहे स्टॉक

एलऐंडटी टेक्नॉलजीज सर्विसेज

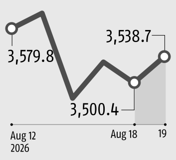

इंजीनियरिंग इंटेलिजेंस क्षमताओं की तैनाती के लिए 7.5 करोड़ डॉलर का ठेका मिला
₹ 3,500.4 पिछला बंद भाव
₹ 3,538.7 आज का बंद भाव
1.1 % ▲

क्रॉम्पटन ग्रीव्स कंज्यूमर

अपनी नई मास्टर ब्रांड पहचान पेश की और ब्रांडेड प्लेटफॉर्म का विस्तार किया
₹ 244.9 पिछला बंद भाव
₹ 245.1 आज का बंद भाव
0.1 % ▲

एस्कॉर्ट्स कुबोटा

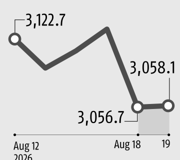

यूपी में नए विनिर्माण संयंत्र के लिए करेगी 2,000 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश
₹ 3,056.7 पिछला बंद भाव
₹ 3,058.1 आज का बंद भाव
0.0 % ▲

टाटा कम्युनिकेशंस

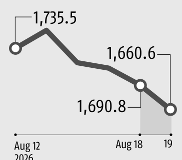

250 करोड़ रुपये के वाणिज्यिक पत्र जारी और आवंटित किए
₹ 1,690.8 पिछला बंद भाव
₹ 1,660.6 आज का बंद भाव
-1.8 % ▼

एक्सीकॉम टेली-सिस्टम्स

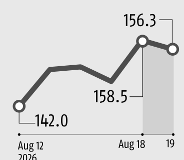

ईवी चार्जर के लिए लिक्विड कूल्ड पावर मॉड्यूल की शुरुआत की
₹ 158.5 पिछला बंद भाव
₹ 156.3 आज का बंद भाव
-1.4 % ▼

संक्षेप में

कंट्रोलएस ने 250 करोड़ रुपये की रकम जुटाई

इन्वेस्टर और जीरोधा के सह-संस्थापक निखिल कामत ने देश के सबसे बड़े हाइपरस्केल डेटा सेंटर परिचालकों में शामिल कंट्रोलएस में लगभग 200 करोड़ रुपये का निवेश किया है। उनके अलावा उद्यमी श्रीराम रेड्डी वंगा ने भी 50 करोड़ रुपये का निवेश किया है। यह रकम कंट्रोलएस के बुनियादी ढांचे को बढ़ाने और क्षमता विकसित करने में मदद करेगी, ताकि देश भर में उद्यमों और हाइपरस्केलर की बढ़ती मांग पूरी की जा सके, खासकर ऐसे समय में जब एआई, क्लाउड और डिजिटल वर्कलोड तेजी से बढ़ रहे हैं। श्रीधर पिन्नापुरेडी द्वारा स्थापित कंट्रोलएस देश के डेटा सेंटर उद्योग में अहम कंपनी बनकर उभरी है। यह देश की कुछ सबसे आधुनिक हाइपरस्केल इकाइयां निर्मित और संचालित कर रही है। *बीएस*

फिनटेक फर्म नवी ने जुटाए 10 करोड़ डॉलर

अपनी तरह के पहले संस्थागत पूंजी जुटाने के प्रयास में फिनटेक फर्म नवी ने डच प्रौद्योगिकी निवेशक प्रोसस से 10 करोड़ डॉलर जुटाए हैं। सचिन बंसल के नेतृत्त्व वाली कंपनी ने कहा कि यह लेनदेन भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) सहित नियामकीय स्वीकृतियों के अधीन है। यह पूंजी ऐसे समय में जुटाई गई है जब बेंगलुरु स्थित यह फिनटेक कंपनी भारतीय शेयर बाजार में सूचीबद्ध होने की तैयारी कर रही है और उसने लगभग 30 करोड़ डॉलर जुटाने का लक्ष्य रखा है। आईपीओ की तैयारी के तहत, कंपनी ने संभावित निर्गम के लिए सलाहकारों के तौर पर बैंकरों की नियुक्ति की है। प्रोसस का नवी में यह निवेश ऐसे समय में किया गया है जब यह निवेशक पहले से ही भारत में एक अन्य भुगतान और ऋण प्रदाता पेयू का समर्थन कर रहा है। बीएस

एलटीटीएस को वैश्विक प्रौद्योगिकी फर्म से ठेका

लार्सन ऐंड टूब्रो टेक्नॉलजी सर्विसेज (एलटीटीएस) को एक वैश्विक प्रौद्योगिकी कंपनी से 7.5 करोड़ डॉलर (करीब 718 करोड़ रुपये) से अधिक का 5 साल का ठेका मिला है। एलटीटीएस ने ठेका देने वाली कंपनी के नाम का खुलासा नहीं किया है। शेयर बाजार को बुधवार को दी गई जानकारी के अनुसार, समझौते की शर्तों के तहत ठेका देने वाली कंपनी की पहचान उजागर नहीं की जा सकती। एलटीटीएस समझौते के तहत कंपनी के वैश्विक खंड के लिए अगली पीढ़ी के समाधान के विकास में तेजी लाने के लिए अपनी इंजीनियरिंग इंटेलिजेंस (ईआई) क्षमताओं को इस्तेमाल करेगी। इस अनुबंध में उत्पाद इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर विकास, परीक्षण और सत्यापन आदि शामिल हैं। एलटीटीएस, लार्सन ऐंड टुब्रो की अनुषंगी कंपनी है। यह इंजीनियरिंग तथा अनुसंधान एवं विकास सेवाओं में विशेषज्ञता रखती है। *भाषा*

इन्वेस्टकॉर्प ने किया 20क्यूब का अधिग्रहण

वैश्विक वैकल्पिक निवेश कंपनी इन्वेस्टकॉर्प ने डिजिटल अनुबंध लॉजिस्टिक मंच '20क्यूब 3पीएल सॉल्यूशंस' का करीब 500 करोड़ रुपये में अधिग्रहण कर लिया है। इन्वेस्टकॉर्प ने बुधवार को जारी बयान में कहा कि इस निवेश से 20क्यूब को अपनी प्रौद्योगिकी क्षमताओं को मजबूत करने और देशभर में नेटवर्क का विस्तार करने में मदद मिलेगी। कंपनी ने कहा कि इन्वेस्टकॉर्प और 20क्यूब मिलकर अनुबंध लॉजिस्टिक क्षेत्र में तालमेल वाली अन्य कंपनियों के अधिग्रहण के लिए अगले चरण में 500-750 करोड़ रुपये का अतिरिक्त निवेश भी करेंगी। यह अधिग्रहण सौदा सिंगापुर मुख्यालय वाली 20क्यूब लॉजिस्टिक्स के भारत के अनुबंध लॉजिस्टिक कारोबार को अलग करके किया गया है। 20क्यूब लॉजिस्टिक्स अपने मुख्य अंतरराष्ट्रीय माल ढुलाई कारोबार पर ध्यान देती रहेगी। *भाषा*

आर्केड डेवलपर्स मुंबई में करेगी पुनर्विकास

रियल एस्टेट कंपनी आर्केड डेवलपर्स लिमिटेड मुंबई में चार आवासीय परियोजनाओं का पुनर्विकास करेगी। इन परियोजनाओं से कंपनी को करीब 5,000 करोड़ रुपये का राजस्व मिलने की उम्मीद है। कंपनी ने बुधवार को शेयर बाजार को दी सूचना में बताया कि उसने मुंबई के पश्चिमी उपनगरों के प्रमुख इलाकों में चार नई पुनर्विकास परियोजनाएं जोड़ी हैं। आर्केड डेवलपर्स के अनुसार, ये चारों परियोजनाएं मलाड पश्चिम, कांदिवली पश्चिम, कांदिवली पूर्व और बोरीवली पश्चिम में स्थित हैं। इनमें कुल 45,204 वर्ग मीटर (11.17 एकड़) भूमि का विकास किया जाएगा। कंपनी ने कहा, 'इन परियोजनाओं में कुल मिलाकर करीब 15 लाख वर्ग फुट बिक्री योग्य क्षेत्र का विकास होने की संभावना है और इनसे लगभग 5,000 करोड़ का राजस्व मिलने का अनुमान है।' *भाषा*

प्रतिस्पर्धा आयोग ने प्रतिबद्धता नियमों में किया संशोधन

रुचिका चित्रवंशी
पणजी, 19 अगस्त

भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) ने प्रतिबद्धता के नए नियमों को अधिसूचित किया है। इसमें ऐसे आवेदन दाखिल करने की समय-सीमा 45 दिन से बढ़ाकर 60 दिन कर दी गई है। 18 अगस्त की एक अधिसूचना में सीसीआई ने प्रतिबद्धता के आवेदनों पर अपने आरंभिक विचार-विमर्श के लिए उपलब्ध अवधि को 7 कार्य दिवस से बढ़ाकर 15 और कुल समय-सीमा को 130 दिन से बढ़ाकर 180 कर दिया है।

समय-सीमा में हुआ इजाफा

- आवेदन दाखिल करने की समय सीमा 45 दिन से बढ़ाकर 60 दिन की गई
- सीसीआई ने प्रतिबद्धता के आवेदनों पर आरंभिक विचार-विमर्श के लिए उपलब्ध अवधि 7 कार्य दिवस से बढ़ाकर 15 और कुल समय-सीमा को 130 दिन से बढ़ाकर 180 कर दिया
- यह प्रावधान लागू होने के बाद से भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने अभी तक किसी भी प्रतिबद्धता प्रस्ताव को मंजूरी नहीं दी है
- वर्तमान में इंडिगो विमानन कंपनी का संचालन करने वाली इंटरग्लोब एविएशन और गूगल के दो प्रस्ताव विचाराधीन हैं

प्रतिस्पर्धा (संशोधन) अधिनियम, 2023 के तहत अधिनियम की धारा 48ए और 48बी पेश की गई। इसका मकसद निपटान और प्रतिबद्धता का ऐसा तंत्र बनाना है, जिससे एकाधिकार विरोधी जांच का सामना कर रही कंपनियां लंबे कानूनी विवाद के बिना मामलों को सुलझाने के लिए अपनी मर्जी से सुधार के या कुछ शर्तों को मानने के प्रस्ताव दे सकें।

यह प्रावधान लागू होने के बाद से सीसीआई ने अभी तक किसी भी प्रतिबद्धता प्रस्ताव को मंजूरी नहीं दी है। वर्तमान में इंडिगो विमानन कंपनी का संचालन करने वाली इंटरग्लोब एविएशन और गूगल के दो प्रस्ताव विचाराधीन हैं।

गूगल का आवेदन प्ले स्टोर पर रियल मनी गेमिंग ऐप सूचीबद्ध करने के संबंध में कथित अनुचित कारोबारी कार्यप्रणाली के आरोपों की जांच से जुड़ा है। इंटरग्लोब की प्रतिबद्धता दिसंबर 2025 में बड़े स्तर पर उड़ानों में रुकावटों के कारण शुरू हुई दबदबे के दुरुपयोग की जांच से जुड़ी है। दोनों आवेदनों के लिए सार्वजनिक राय मांगी जा चुकी है और आयोग को इस मामले पर अंतिम निर्णय लेना है।

सीसीआई ने कहा कि प्रतिबद्धता नियमों में बदलाव ढांचे को लागू करने से मिले अनुभवों पर आधारित थे। इस दौरान कुछ प्रशासनिक और प्रक्रिया संबंधी मसले भी सामने आए। ये मसले निर्धारित समय-सीमा, आवेदनों की खामियों के सुधार और शुल्क के समायोजन तथा अवैध आवेदनों के नतीजों पर स्पष्टता की कमी से जुड़े थे।

सीसीआई ने हितधारकों से इन प्रस्तावित परिवर्तनों पर टिप्पणियां आमंत्रित की थीं। कुछ ने सुझाव दिया कि महानिदेशक की जांच रिपोर्ट जमा करने से पहले किसी भी चरण में प्रतिबद्धता आवेदन की अनुमति दी जानी चाहिए।

हालांकि सीसीआई ने कहा कि जांच रिपोर्ट जमा करने तक प्रतिबद्धता आवेदनों की अनुमति देने से प्रक्रिया संबंधी निश्चितता कम हो जाएगी, यह जल्द हस्तक्षेप के उद्देश्य को कमजोर कर देगी और इससे जांच प्रक्रिया में देरी होगी।

बुकमाईशो में हिस्सा खरीदेगी केकेआर

शार्लीन डिसूजा
मुंबई, 19 अगस्त

निवेश फर्म केकेआर ने बुकमाईशो में अल्पांश हिस्सेदारी खरीदने के लिए समझौता किया है। दोनों कंपनियों ने एक साझा बयान में कहा कि बुकमाईशो इस निवेश का इस्तेमाल वृद्धि के अपने अगले चरण को आगे बढ़ाने के लिए करेगी। कंपनी अपने लाइव एंटरटेनमेंट बिजनेस को बढ़ा रही है और पूरे भारत में अपनी फुल-स्टैक सर्विस और मजबूत कर रही है।

बुकमाईशो को वर्ष 2007 में शुरू किया गया था। इसका मालिकाना हक और संचालन 1999 स्थापित बिगट्री एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड के पास है। यह भारत के प्रमुख एंटरटेनमेंट डेस्टिनेशंस में से एक है, जिसका कामकाज दुनिया भर में फैला हुआ है और एंटरटेनमेंट से जुड़ी हर जरूरत के लिए एक प्रमुख वन-स्टॉप शॉप है। इसकी मौजूदगी देश के 700 से ज्यादा कस्बों और शहरों में है। कंपनी उद्योग के कई साझेदारों के साथ मिलकर काम करती है। मीडिया रिपोर्टों के अनुसार केकेआर 4-5 करोड़ डॉलर में 6 फीसदी हिस्सेदारी खरीदेगी। बुकमाईशो के लिए एवेंडस कैपिटल ने विशेष वित्तीय सलाहकार के तौर पर काम किया, जबकि ट्राइलीगल ने कानूनी सलाहकार की भूमिका निभाई।

विज्ञप्ति में कहा गया है, 'केकेआर का निवेश भारत के एंटरटेनमेंट सेक्टर और बुकमाईशो की उस क्षमता पर उनके भरोसे को दिखाता है, जिससे वे अपनी वृद्धि के अगले चरण को आगे बढ़ा सकते हैं। इस वृद्धि को लोगों के खर्च करने की बढ़ती क्षमता, व्यापक और युवा उपभोक्ता आधार तथा विश्वस्तरीय लाइव एक्सपीरियंस की बढ़ती मांग से प्रोत्साहन मिल रहा है। उपभोक्ता तक पहुंच, टेक्नॉलजी और एंटरटेनमेंट क्षमताओं के साथ कंपनी तेजी से विकसित हो रहे बाजार में अपनी वृद्धि की रफ्तार बनाए रखने की स्थिति में है।'

केकेआर में पार्टनर और इंडिया प्राइवेट इक्विटी के प्रमुख अक्षय तन्ना ने कहा, 'बुकमाईशो भारत में बेहतरीन एंटरटेनमेंट अनुभव देने में सबसे आगे रही है। हमें खुशी है कि हम बुकमाईशो का सहयोग कर रहे हैं, क्योंकि यह भारत के 'आउट-ऑफ-होम' एंटरटेनमेंट सेक्टर में वृद्धि के नए दौर को आगे बढ़ा रही है। हमारा मानना है कि बुकमाईशो भारत के उस लक्ष्य को पूरा करने में अहम भूमिका निभाएगी।'

स्पाइसजेट को विमान देने वाली कंपनी को याचिका वापस लेने की इजाजत

भाविनी मिश्रा
नई दिल्ली, 19 अगस्त

राष्ट्रीय कंपनी कानून पंचाट (एनसीएलटी) के दिल्ली पीठ ने विमान लीज पर देने वाली कंपनी एविएटर एमएल 29641 लिमिटेड को स्पाइसजेट के खिलाफ अपनी दिवाला याचिका वापस लेने की इजाजत दे दी। दोनों पक्षों के अपने विवाद का निपटारा करने के बाद यह इजाजत दी गई। साथ ही पंचाट ने मामले को आदेश के लिए सुरक्षित रखे जाने के बाद समझौता करने पर उन्हें संयुक्त रूप से 15 लाख रुपये का खर्च भरने का निर्देश भी दिया।

एनसीएलटी के दिल्ली पीठ का फैसला

- एविएटर एमएल 29641 लिमिटेड और स्पाइसजेट ने किया समझौता
- दोनों पक्षों को 15 लाख रुपये का खर्च भरने का भी दिया निर्देश

न्यायिक सदस्य महेंद्र खंडेलवाल और तकनीकी सदस्य अनु जगमोहन सिंह के विशेष पीठ ने दोनों पक्षों को 7 दिन के भीतर प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष में 7.5 लाख रुपये जमा करने का आदेश दिया। ट्रिब्यूनल रजिस्ट्री के समक्ष भुगतान का प्रमाण प्रस्तुत करने के बाद ही याचिका वापस ली जा सकेगी। ऐसा न करने पर मामला दोबारा सूचीबद्ध कर दिया जाएगा।

पंचाट ने स्पाइसजेट के खिलाफ 7 अन्य दिवाला याचिकाओं पर अपने सुरक्षित आदेशों को भी वापस ले लिया और निर्देश दिया कि उन्हें नए सिरे से विचार के लिए नियमित पीठ के समक्ष रखा जाए।

विमान किराये पर देने वाली कंपनी ने साल 2024 में दिवालियापन और ऋणशोधन अक्षमता संहिता की धारा 9 के तहत कार्रवाई शुरू की थी। इसमें 58.64 करोड़ रुपये के भुगतान में चूक का आरोप लगाया गया था। विमानन कंपनी के खिलाफ इसी तरह की 7 अन्य याचिकाओं के साथ इस मामले की सुनवाई की गई थी और इस पर मूल रूप से 17 अगस्त को फैसला सुनाया जाना था।

आदेश सुनाए जाने से पहले ही दोनों पक्षों ने पंचाट को बताया कि उन्होंने रातोरात एक निपटान समझौता कर लिया है। इसके तहत स्पाइसजेट ने 5,00,000 डॉलर का शुरुआती भुगतान किया है। इसके बाद विमान किराये पर देने वाली कंपनी को औपचारिक रूप से याचिका वापस लेने की अनुमति देने के लिए मामला स्थगित कर दिया गया था।

दोपहिया वाहनों के निर्यात में 20 प्रतिशत वृद्धि के आसार

सोहिनी दास
मुंबई, 19 अगस्त

देश के दोपहिया निर्यात में वित्त वर्ष 27 के दौरान सालाना आधार पर 15 से 20 प्रतिशत की बढ़ोतरी के आसार हैं। यह लगातार तीसरा ऐसा साल होगा जब निर्यात में बढ़ोतरी होगी। इंडिया रेटिंग्स ऐंड रिसर्च (इंड-रा) के अनुसार अफ्रीकी मांग में सुधार और लैटिन अमेरिका तथा दक्षिण पूर्व एशिया में विस्तार से इसमें इजाफा होगा। वित्त वर्ष 26 में निर्यात सालाना आधार पर 23 प्रतिशत बढ़कर 51.8 लाख वाहनों के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया। इसने वित्त वर्ष 22 में दर्ज 44.4 लाख के पिछले रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया। यह रफ्तार वित्त वर्ष 27 की पहली तिमाही में भी जारी रही, जब निर्यात में 37 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई।

इंडिया रेटिंग्स ऐंड रिसर्च के अनुसार अफ्रीकी मांग में सुधार, लैटिन अमेरिका तथा दक्षिण पूर्व एशिया में विस्तार से बढ़ेगा निर्यात

रेटिंग एजेंसी ने एक रिपोर्ट में कहा कि निर्यात में तेजी का यह चक्र केवल कुछ समय के लिए नहीं, बल्कि लंबे समय तक चलने वाला दिखता है। भारतीय निर्माताओं ने अपनी भौगोलिक मौजूदगी बढ़ाई है, वितरण नेटवर्क मजबूत किया है और बाजार की जरूरत के हिसाब से वाहनों को पेश किया है। विशेष रूप से कोलंबिया, मेक्सिको और ब्राजील भारत के शीर्ष 10 निर्यात बाजारों में शामिल हो गए हैं। इससे उद्योग की अफ्रीका पर चली आ रही निर्भरता कम हुई है।

महंगाई कम होने और विदेशी मुद्रा की उपलब्धता बेहतर होने से अफ्रीका के मुख्य बाजारों में भी मांग बढ़ रही है। नाइजीरिया वित्त वर्ष 24 तक भारत के दोपहिया निर्यात का सबसे बड़ा बाजार रहा है। वित्त वर्ष 26 में नाइजीरिया में भेजी गई खेपों में सुधार होने लगा। हालांकि यह अब भी वित्त वर्ष 22 के स्तर का लगभग 39 प्रतिशत ही है। इससे वहां वृद्धि की काफी गुंजाइश बनी हुई है। इस बीच श्रीलंका द्वारा गाड़ियों के आयात पर लगी पाबंदियों में धीरे-धीरे ढील देने से भी अतिरिक्त बढ़ावा मिला है।

ह्युंडै मोटर कर रही सितंबर से दाम बढ़ाने की तैयारी

ह्युंडै मोटर इंडिया लिमिटेड लागत संबंधी दबाव को कम करने के लिए सितंबर से अपने वाहनों की कीमतों में 1 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी करने की योजना बना रही है। कंपनी ने बुधवार को शेयर बाजार को दी सूचना में कहा कि कीमतों में बढ़ोतरी की मात्रा मॉडल और संस्करण के हिसाब से अलग-अलग होगी।

ह्युंडै मोटर ने कहा कि कच्चे माल और जिंस की बढ़ती लागत, परिचालन खर्च में वृद्धि तथा लगातार बनी हुई भू-राजनीतिक और व्यापक आर्थिक अनिश्चितताओं समेत कई कारणों से उसके कीमतों में संशोधन करना पड़ रहा है। कंपनी ने कहा कि वह बढ़ी हुई लागत का बोझ खुद वहन करने के लिए हरसंभव प्रयास कर रही है, ताकि ग्राहकों पर इसका असर कम से कम हो। फिलहाल कंपनी की वाहन श्रृंखला में शुरुआती मॉडल ग्रैंड आई10 निओस से लेकर इलेक्ट्रिक एसयूवी आयोनिक 5 तक शामिल हैं। इनकी कीमतें करीब 5.6 लाख से 55.7 लाख रुपये के बीच हैं। *भाषा*

कार्बन उत्सर्जन: वेदांत ने लगाए 1 अरब डॉलर

भाषा
नई दिल्ली, 19 अगस्त

खनन क्षेत्र की प्रमुख कंपनी वेदांत लिमिटेड ने बुधवार को कहा कि उसने पिछले 5 वित्त वर्षों में शुद्ध रूप से शून्य कार्बन उत्सर्जन की दिशा में विभिन्न उपायों पर 1 अरब डॉलर से अधिक का निवेश किया। कंपनी ने कार्बन उत्सर्जन में कमी लाने के मकसद से पिछले 5 वित्त वर्षों (2021-22 से 2025-26) में यह निवेश नवीकरणीय ऊर्जा, कम कार्बन वाले ईंधन, ऊर्जा दक्षता और प्रौद्योगिकी आधारित उपायों में किया।

कंपनी के अनुसार, इस बदलाव के तहत 2025-26 में समूह द्वारा नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग सालाना आधार पर 52 प्रतिशत बढ़कर 400 करोड़ यूनिट हो गया। यह करीब तीन करोड़ भारतीय परिवारों की सालाना बिजली खपत के बराबर है। वेदांत के पास अब करीब 2,000 मेगावॉट की स्थापित और अनुबंधित नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता है। कंपनी का लक्ष्य 2030 तक 24 घंटे उपलब्ध 2.5 गीगावॉट नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता हासिल करना है। कंपनी ने बयान में कहा कि इन उपायों और कार्बन उत्सर्जन कम करने के अन्य कदमों से 2020-21 से करीब 3.6 करोड़ टन कार्बन डाईऑक्साइड समतुल्य उत्सर्जन को रोका गया। वहीं, समूह के धातु और खनन उत्पादन में हरित गृह गैस उत्सर्जन की तीव्रता 2020-21 के आधार वर्ष की तुलना में करीब 14 प्रतिशत कम हुई है। भारत ने 2030 तक स्वच्छ ईंधन आधारित बिजली उत्पादन क्षमता को 500 गीगावॉट तक बढ़ाने का महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखा है। इसके साथ ही देश का लक्ष्य अपनी ऊर्जा जरूरतों का 50 प्रतिशत नवीकरणीय स्रोतों से पूरा करना और 2070 तक शुद्ध रूप से शून्य उत्सर्जन हासिल करना है।

1,166 करोड़ रु का निवेश करेगी स्पार्क मिंडा

वाहन कलपुर्जा विनिर्माता कंपनी स्पार्क मिंडा ने बुधवार को कहा कि वह यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यीडा) क्षेत्र में अपनी दो नई विनिर्माण इकाइयों के जरिये करीब 6,440 रोजगार सृजित करने की उम्मीद कर रही है। इन दोनों इकाइयों में कुल मिलाकर 1,166 करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा।

कंपनी ने बयान में कहा कि यीडा के सेक्टर-10 और सेक्टर-24 में स्थापित होने वाली दोनों इकाइयों का भूमि पूजन समारोह बुधवार को राजधानी में आयोजित यूपी-जापान इन्वेस्टमेंट मीट 2026 से इतर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में डिजिटल माध्यम से हुआ। स्पार्क मिंडा ने कहा कि नोएडा और ग्रेटर नोएडा में उसके मौजूदा सुरक्षा प्रणाली, डाई-कास्टिंग और वायरिंग हार्नेस संयंत्र पहले से ही भारत में उसके विनिर्माण नेटवर्क का महत्त्वपूर्ण हिस्सा हैं। *बीएस*

चार्ल्स श्वाब ने हैदराबाद में खोला जीसीसी

शिवानी शिंदे
मुंबई, 19 अगस्त

अमेरिका की वित्तीय सेवा कंपनी चार्ल्स श्वाब ने हैदराबाद में 3,45,000 वर्ग फुट का टेक्नॉलजीज क्षमता केंद्र श्वाब इंडिया की खोलकर भारत में अपनी शुरुआत की।

यह केंद्र तकनीक विकास, इंजीनियरिंग प्रतिभा और परिचालन क्षमताओं के जरिये चार्ल्स श्वाब के अमेरिकी कारोबार की मदद करेगा। कंपनी की योजना साल 2027 के अंत तक हैदराबाद में अपने कर्मचारियों की संख्या को लगभग 2,000 तक बढ़ाने की है। चार्ल्स श्वाब की यह शुरुआत शहर के उस पारिस्थितिकी तंत्र में उस एक और महत्त्वपूर्ण कड़ी को जोड़ती है जो पारंपरिक बीएफएसआई जीसीसी क्लस्टर से आगे विकसित हो रहा है।

सरकारी अधिकारियों के अनुसार हैदराबाद का दायरा अब ब्रोकरेज और ट्रेडिंग, निवेश और धन प्रबंधन, बाजार अवसंरचना, जोखिम, एनालिटिक्स और साइबर सुरक्षा तक फैला हुआ है। इसमें चार्ल्स श्वाब, डॉयचे बोर्स, वैनगार्ड, जेपी मॉर्गन चेज, बैंक ऑफ अमेरिका, गोल्डमैन सैक्स, स्टेट स्ट्रीट, वेल्स फारगो, यूबीएस और इनवेस्को जैसी कंपनियां शामिल हैं।

तेलंगाना सरकार में सूचना प्रौद्योगिकी, इलेक्ट्रॉनिकी और संचार, उद्योग और वाणिज्य तथा विधायी मामलों के मंत्री डी श्रीधर बाबू ने कहा, 'हैदराबाद दुनिया की शीर्ष 10 ब्रोकरेज और ट्रेडिंग संस्थाओं में से 9 का केंद्र है। ये संस्थाएं पूंजी बाजार की सभी तरह की क्षमताएं रखती हैं और लगभग 40 लाख करोड़ डॉलर की प्रबंधनाधीन परिसंपत्तियों का प्रतिनिधित्व करती हैं।'

मुंबई संस्करण : बिजनेस स्टैंडर्ड प्राइवेट लिमिटेड के लिए प्रकाशक एवं मुद्रक संगीता अश्विन ठाकुर खेओरा द्वारा मै. दांगट मीडिया प्राइवेट लिमिटेड, 22, दीघा एमआईडीसी, टीटीसी इंडस्ट्रियल एरिया, विष्णु नगर, दीघा, नवी मुंबई-400708 से मुद्रित एवं बिजनेस स्टैंडर्ड प्राइवेट लिमिटेड, एच/4, बिल्डिंग एच, पैरागन सेंटर, बिड़ला सेंचुरियन के सामने, पी बी मार्ग, वर्ली, मुंबई-400013 से प्रकाशित
संपादक : कैलाश नौटियाल, पीआरजीआई रजिस्ट्रेशन नं. MAHHIN/2008/24325 पाठक संपादक को lettershindi@bsmail.in पर संदेश भेज सकते हैं। टेलीफोन - 022-40275300/40275400
सबस्क्रिप्शन और सर्कुलेशन के लिए संपर्क करें... सुश्री मानसी सिंह हेड, कस्टमर रिलेशन्स बिजनेस स्टैंडर्ड प्राइवेट लिमिटेड, एच/4, बिल्डिंग एच, पैरागन सेंटर, बिड़ला सेंचुरियन के सामने, पी बी मार्ग, वर्ली, मुंबई-400013 ईमेल.. subs_bs@bsmail.in या 57575 पर एसएमएस करें REACHBS कोई हवाई अधिभार नहीं

तेल में बढ़त, बाजार में गिरावट जारी

बीएस संवाददाता
मुंबई, 19 अगस्त

बाजार में गिरावट बरकरार

- इस साल एचडीएफसी बैंक के शेयर में 27 फीसदी की गिरावट दर्ज
- विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक 408 करोड़ रुपये के शुद्ध खरीदार रहे
- जबकि देसी संस्थागत निवेशकों ने 3,974 करोड़ रुपये की शुद्ध खरीद की। फिर भी बाजारों में फिसलन बनी रही

कच्चे तेल की ऊंची कीमतों और बॉन्ड यील्ड में बढ़ोतरी के कारण बेंचमार्क निफ्टी लगातार सातवें कारोबारी सत्र में गिरावट के साथ बंद हुआ। यह सितंबर 2025 के बाद से गिरावट का इसका सबसे लंबा दौर है। बुधवार को बेंचमार्क निफ्टी 77 अंक यानी 0.3 फीसदी गिरकर 24,078 पर आ गया। सेंसेक्स 326 अंक यानी 0.4 फीसदी की फिसलन के साथ 76,910 पर बंद हुआ। इंडेक्स की तीन बड़ी कंपनियों एचडीएफसी बैंक, आईटीसी और एचयूएल, जिनका निफ्टी 50 के कुल बाजार पूंजीकरण में करीब 10 फीसदी हिस्सा है, में कमजोर वैश्विक सेंटिमेंट के बीच कारोबारी सत्र के दौरान करीब 1 फीसदी की गिरावट आई। लेकिन, निचले स्तरों पर खरीदारी के बाद एचयूएल और एचडीएफसी बैंक ने अपनी गिरावट को कम किया और 1 फीसदी से कम की गिरावट के साथ बंद हुए।

इन शेयरों के लिए अगस्त में एक्सपायरी वाले अनुबंधों के 'पुट ऑप्शन प्रीमियम' में लगभग 50 फीसदी की बढ़ोतरी हुई, क्योंकि निवेशकों ने दिन के दौरान गिरती कीमतों को देखते हुए यह कदम उठाया। बाजार के प्रतिभागी एचडीएफसी बैंक को लेकर खास तौर पर सतर्क रहे। निफ्टी बैंक इंडेक्स में 4 फीसदी की गिरावट के मुकाबले इस साल एचडीएफसी बैंक के शेयर में अब तक 27 फीसदी की गिरावट आ चुकी है। 720 रुपये के स्ट्राइक प्राइस वाले एचडीएफसी बैंक के पुट ऑप्शंस में लगभग 50 फीसदी की उछाल आई। ये 6 रुपये पर खुले, 8.8 रुपये के उच्चस्तर तक पहुंचे और 5 रुपये पर बंद हुए। इसी स्ट्राइक प्राइस के लिए कॉल ऑप्शंस 11 रुपये पर खुले और 7.05 रुपये पर बंद हुए। पिछले पांच सालों में, इस शेयर में 4 फीसदी की गिरावट आई है जबकि इसी दौरान निफ्टी 50 में 45 फीसदी और निफ्टी बैंक में 61 फीसदी की बढ़त दर्ज की गई है।

एचयूएल के शेयर 2,035 रुपये पर खुले और इंट्राडे में 2,008 रुपये (1.3 फीसदी की गिरावट) के निचले स्तर तक गए, लेकिन अंत में 2,021 रुपये यानी 0.7 फीसदी की गिरावट के साथ बंद हुए। जून तिमाही के दौरान एचयूएल में विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों (एफपीआई) की हिस्सेदारी 10.1 फीसदी से घटकर 9.5 फीसदी रह गई, जबकि घरेलू म्युचुअल फंडों की हिस्सेदारी बढ़कर 7.15 फीसदी हो गई। रेड लायंस कैपिटल के सैकत कुमार ने कहा, एचयूएल की कहानी असल में क्वॉलिटी और कमाई की स्पष्टता के बारे में है, खासकर ऐसे बाजार में जहां निवेशक बहुत सोच-समझकर निवेश कर रहे हैं।

ऊर्जा की कीमतों और वैश्विक यील्ड में बढ़ोतरी से जोखिम से बचने का माहौल बना हुआ है। ब्रेंट क्रूड की हाजिर कीमत 89.98 डॉलर प्रति बैरल के आसपास रही, जो पिछले आठ सत्रों में लगभग 10 फीसदी बढ़ी है। मंगलवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप के यह कहने के बाद कि ईरान के साथ कोई राजनयिक बातचीत नहीं हो रही है, भूराजनीतिक कनाव बना हुआ है। उन्होंने कहा कि होर्मुज स्ट्रेट खुला है, जबकि तेहरान का दावा था कि यह अहम समुद्री रास्ता बंद है। क्रूड की ऊंची कीमतें भारत के लिए चुनौती हैं, क्योंकि भारत अपनी क्रूड की जरूरतों का करीब 85 फीसदी आयात करता है।

जियोजित फाइनैंशियल सर्विसेज के शोध प्रमुख विनोद नायर ने कहा, अमेरिका-ईरान के बीच युद्धविराम खत्म होने के बाद कोई कूटनीतिक समाधान न निकलने से कच्चे तेल की कीमतें और बॉन्ड यील्ड ऊंची बनी रही, जिससे जोखिम से बचने का रुझान मजबूत हुआ। जैसे-जैसे वित्त वर्ष 2027 की पहली तिमाही के नतीजे आने का दौर खत्म हो रहा है, कंपनियों के परिणाम अमूमन उम्मीद से बेहतर रहे हैं, जिससे कमाई की मजबूती पर भरोसा बढ़ा है। लेकिन चूंकि बाजार को मिल रहा अस्थायी समर्थन हलका पड़ रहा है, ऐसे में बाजार के प्रदर्शन का अगला दौर काफी हद तक कच्चे तेल की आपूर्ति श्रृंखला की स्थिरता पर निर्भर करेगा।

बाजार में चढ़ने-गिरने वाले शेयरों का अनुपात कमजोर रहा, जहां 2,572 शेयर टूटे जबकि 1,728 में बढ़ोतरी हुई। एफपीआई 408 करोड़ रुपये के शुद्ध खरीदार रहे जबकि देसी संस्थागत निवेशकों ने 3,974 करोड़ रुपये की शुद्ध खरीद की।

भारतीय पोर्टफोलियो में बर्नस्टीन ने किया बदलाव

पुनीत वाधवा
नई दिल्ली, 19 अगस्त

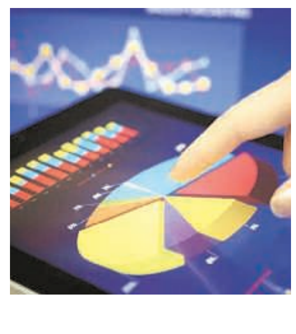

जून तिमाही के नतीजों का दौर खत्म होने के साथ ही बर्नस्टीन ने अपने इंडिया पोर्टफोलियो में बदलाव किया है। इस वैश्विक रिसर्च और ब्रोकिंग हाउस ने इटर्नल को अपने पोर्टफोलियो में शामिल किया है। उसका मानना है कि ऐसे सेक्टर में भी यह कंपनी अपनी प्रतिस्पर्धी ताकत दिखा रही है, जहां पूंजी जुटाना मुश्किल होता जा रहा है। एमडीआर से जुड़े संभावित कारणों को देखते हुए पेटीएम को भी शामिल किया गया है। बर्नस्टीन के इंडिया मॉडल पोर्टफोलियो में अदाणी पोर्ट्स को भी जगह मिली है।

शेयर बाजार में हालिया शानदार प्रदर्शन और क्विक कॉमर्स से शहरी वृद्धि पर बढ़ते जोखिमों के कारण उसने एवेन्यू सुपरमार्ट्स को पोर्टफोलियो से हटा दिया। बर्नस्टीन ने कहा कि पोर्टफोलियो में वित्तीय क्षेत्र का हिस्सा कुछ ज्यादा है। ऐसा जान-बूझकर नहीं किया गया बल्कि यह उनके कवरेज दायरे और शेयर कीमत के निचले स्तर को लेकर भरोसे का नतीजा है।

बर्नस्टीन के प्रबंध निदेशक वेणुगोपाल गैरे की अगुआई में विश्लेषकों ने हाल में एक संयुक्त नोट में लिखा, हम अपने पोर्टफोलियो से डीमार्ट को हटा रहे हैं क्योंकि अभी हमें इसमें कोई स्पष्ट दिशा नहीं दिख रही है। सीपीआई महंगाई अब तक काबू में रही है, लेकिन बुआई कमजोर रही है और थोक महंगाई लगातार 4 महीनों से 8 फीसदी से ऊपर बनी हुई है। इसके अलावा, क्विक-कॉमर्स से भी हमेशा खतरा बरकरार है।

इसके बावजूद, बर्नस्टीन ने अपनी पिछली फोकस लिस्ट के कुछ शेयरों को बनाए रखा है। इनमें लार्सन ऐंड टुब्रो, एनटीपीसी, ऐक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, नुवामा और होमफर्स्ट शामिल हैं। गैरे ने लिखा, ऑटो सेक्टर में महिंद्रा ऐंड महिंद्रा हमारी पसंद बनी हुई है। वित्त वर्ष 27 की पहली तिमाही में इसके नतीजे अच्छे रहे हैं और कुल मांग नरम रहने के बावजूद इसके बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद है। स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में जायडस हमारी पसंद बनी हुई है, जिसकी वजह है इसका नवोन्मेष आधारित पोर्टफोलियो, खासकर अमेरिकी कारोबार में और भारत में इसके अलग तरह के उत्पाद।

कंपनियों की आय

बर्नस्टीन का कहना है कि व्यापक बाजार की कंपनियों के मुनाफे में अभी कोई बढ़ोतरी नहीं दिख रही है क्योंकि आधार प्रभाव कम अनुकूल हो रहा है और आर्थिक माहौल में उतार-चढ़ाव बना हुआ है। नोट में कहा गया है कि कुल मिलाकर स्थिति बहुत आकर्षक न होने के बावजूद बाजार के अंदरूनी हालात दिलचस्प बने हुए हैं। ऐसे माहौल में जहां रिटर्न कम रहने की उम्मीद है, खास शेयरों में निवेश के मौके ही बेहतर प्रदर्शन का सबसे अच्छा जरिया बने हुए हैं। बर्नस्टीन ने निफ्टी के लिए 26,000 का लक्ष्य तय किया है, जो मौजूदा स्तर से करीब 8 फीसदी ज्यादा है।

बर्नस्टीन के अनुसार एनएसई 200 की वित्त वर्ष 27 की पहली तिमाही की कमाई में तेजी की रफ्तार धीमी हुई है। मार्च तिमाही में जो वृद्धि 12.5 फीसदी थी, वह घटकर 8 फीसदी रह गई है। लेकिन, मुख्य आंकड़ों के पीछे की तस्वीर काफी मिली-जुली रही।

होर्मुज पर अनिश्चितता से उच्चस्तर पर कच्चा तेल

रॉयटर्स

कच्चे तेल की कीमतें बुधवार को तीन हफ्ते के उच्चस्तर पर पहुंच गईं। इसकी वजह होर्मुज स्ट्रेट से शिपिंग को लेकर अनिश्चितता और आपूर्ति में लगातार आ रही रुकावटें रहीं जिससे बाजार को सहारा मिला। ब्रेंट क्रूड फ्यूचर्स 54 सेंट यानी 0.59 फीसदी बढ़कर 91.56 डॉलर पर पहुंच गया जबकि अमेरिकी वेस्ट टेक्सस इंटरमीडिएट क्रूड फ्यूचर्स 59 सेंट यानी 0.69 फीसदी बढ़कर 85.53 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंच गया।

ब्रेंट क्रूड 30 जुलाई के बाद से अपने सबसे ऊंचे स्तर पर जबकि डब्ल्यूटीआई 31 जुलाई के बाद से अपने सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गया है। केसीएम के मुख्य बाजार विश्लेषक टिम वॉटरर ने कहा, सुरक्षित आवाजाही को लेकर भरोसा कम बना हुआ है। शिपिंग वॉल्यूम अभी भी सामान्य स्तर से काफी नीचे है। इस लगातार बनी अनिश्चितता के कारण तेल की कीमतों में भूराजनीतिक जोखिम प्रीमियम शामिल हो गया है।

मंगलवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ कोई बातचीत नहीं हो रही है और होर्मुज स्ट्रेट खुला है। यह ईरान के उस दावे के उलट है, जिसमें उसने कहा था कि जलमार्ग बंद है। सोमवार को अस्थायी युद्धविराम समझौता खत्म हो गया। ईरान के एक वरिष्ठ अधिकारी ने रॉयटर्स को बताया कि राजनयिक गतिरोध के कारण उनका देश पूरी तरह से आक्रामक सैन्य रुख अपना रहा है। हालांकि मंगलवार को किसी भी पक्ष की ओर से हमले की कोई खबर नहीं मिली।

ब्रोकरेज फर्म पेपरस्टोन के शोध रणनीतिकार अहमद असिरी ने कहा, होर्मुज में वाणिज्यिक शिपिंग लगभग पूरी तरह ठप है।

सीएएस में हेरफेर के आरोप में दो संस्थानों पर कार्रवाई

पृष्ठ 1 का शेष

फिक्की कैपिटल मार्केट्स कॉन्फ्रेंस (सीएपीएएम) को संबोधित करते हुए सेबी के चेयरमैन ने कहा, 'अगर लोग सीएएस में हेरफेर करते हैं तो हम सख्त कार्रवाई करेंगे और तुरंत करेंगे। अगर किसी को लगता है कि वह सीएएस को बदनाम करने के लिए उसमें हेरफेर कर लेंगे तो वह गलतफहमी में है।' सेबी के चेयरमैन ने कहा कि पहले की वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस (वीडब्ल्यूएपी) प्रणाली के मुकाबले सीएएस हेरफेर वाली किसी भी गतिविधि की पहचान करने में ज्यादा असरदार है। पांडेय ने कहा, 'सीएएस प्रणाली में हेरफेर को पकड़ने की अधिक क्षमता है। पुरानी वीडब्ल्यूएपी के मुकाबले सीएएस प्रणाली में हम हेरफेर को अपेक्षाकृत आसानी से पकड़ सकते हैं।'

सेबी ने इन दोनों संस्थानों के खिलाफ जारी अंतरिम आदेश में उनके बैंक खातों से नियामक की मंजूरी के बिना पैसे निकालने पर भी रोक लगाने का निर्देश दिया गया है।

ऑर्डर में यह भी कहा गया है कि सीएएस के लागू होने से अस्थिरता और हेरफेर कम होने की उम्मीद है क्योंकि यह प्रणाली ज्यादा कुशल और पारदर्शी बन जाएगा, जिससे सेबी को पुरानी प्रणाली की तुलना में हेरफेर का पता लगाने में आसानी होगी।

आदेश में सेबी के पूर्णकालिक सदस्य कमलेश चंद्र वार्ष्णेय ने कहा, 'यह ध्यान रखना जरूरी है कि हेरफेर करने वाले ऐसे तौर-तरीकों का वायदा एवं विकल्प सेगमेंट में कारोबार करने वाले लोगों पर बहुत बुरा असर पड़ता है।'

एसएमई के लिस्टिंग ढांचे में होंगे बड़े बदलाव

खुशबू तिवारी
मुंबई, 19 अगस्त

- बाजार नियामक सेबी एआई और मशीन लर्निंग टूल्स के लिए जवाबदेही बढ़ाएगा
- प्रतिभूति बाजार में इसके लिए दिशा निर्देश बना रहा है सेबी

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) छोटे और मझोले उद्यमों (एसएमई) के लिस्टिंग ढांचे में व्यापक बदलाव करने जा रहा है। साथ ही, वह वित्तीय बाजार में आर्टिफिशल इंटेलिजेंस (एआई) और मशीन लर्निंग (एमएल) के इस्तेमाल को लेकर जवाबदेही भी बढ़ाएगा।

बुधवार को मुंबई में फिक्की की सालाना कैपिटल मार्केट्स कॉन्फ्रेंस के दौरान सेबी के चेयरमैन तुहिन कांत पांडेय ने कहा कि नियामक एसएमई फ्रेमवर्क में कई कमियों की जांच कर रहा है। इनमें ट्रेडिंग, मार्केट मेकिंग, अंडरराइटिंग और मेन बोर्ड में जाने से जुड़ी दिक्कतें शामिल हैं।

बाजार नियामक का मानना है कि एसएमई प्लेटफॉर्म पर 'ऑड लॉट' बन रहे हैं, जिससे निवेशकों के लिए ट्रेड करना मुश्किल हो रहा है। पांडे ने कहा कि रिटेल भागीदारी को नियंत्रित करने के लिए उठाए गए कदमों, जैसे ट्रेडिंग लॉट और आवेदन आकार बढ़ाने से भी उम्मीद के मुताबिक नतीजे नहीं मिले हैं।

चिंता का एक और विषय मार्केट-मेकिंग फ्रेमवर्क है। चेयरमैन का कहना था कि यह ठीक से काम नहीं कर रहा और इससे एसएमई की लागत बढ़ा रहा है। अंडरराइटिंग सिस्टम पर भी फिर से सोचने की जरूरत है, साथ ही माइग्रेशन और चुकता पूंजी से जुड़ी जरूरतों पर भी दोबारा विचार करने की आवश्यकता है। पांडेय ने कहा, 'हम सुधार के व्यापक प्रस्ताव लाएंगे। इसके लिए परामर्श पत्र जारी किया जाएगा।'

सेबी, प्रतिभूति बाजार में एआई और एमएल टेक्नॉलजी के जिम्मेदार इस्तेमाल के लिए गाइडलाइंस तैयार कर रहा है। पांडे ने कहा कि एआई पर पहले हुई बातचीत अभी पूरी नहीं हुई है, लेकिन उसके बाद हुए घटनाक्रम की वजह से नियामक को प्रस्तावित फ्रेमवर्क में नए मसलों को शामिल करना पड़ा है।

उन्होंने कहा कि एआई के इस्तेमाल को आसान बनाने पर फोकस होगा। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि जिम्मेदारी और जवाबदेही साफ तौर पर तय हों। पांडेय ने कहा, 'टेक्नॉलजी मौजूद हैं और हम निश्चित रूप से एआई टेक्नॉलजी को बढ़ावा देने में मदद करेंगे। लेकिन इसके साथ ही हमें जिम्मेदारी और जवाबदेही को और ज्यादा स्पष्ट तौर पर तय करना होगा।'

पांडेय ने अपने भाषण में कहा कि सेबी के दायरे में आने वाली हर संस्था अपने लिए जिस भी एआई या एमएल टूल का इस्तेमाल करेगी, उसके लिए वह पूरी तरह जिम्मेदार होगी, चाहे वह टूल उन्होंने खुद बनाया हो या किसी थर्ड पार्टी से लिया हो। यह जिम्मेदारी निवेशकों के डेटा की निजता, सुरक्षा और अखंडता के साथ-साथ ऐसे सिस्टम से मिलने वाले नतीजों पर भी लागू होगी।

सेबी के प्रस्तावित दिशानिर्देश चरणबद्ध तरीके से आंगे। इनमें स्पष्ट जवाबदेही और प्रशासनिक नियंत्रण शामिल होंगे। इनमें तकनीकी नवाचार और निवेशकों की सुरक्षा के बीच संतुलन बनाने के लिए डेटा कंट्रोल के साथ-साथ 'किल स्विच' और 'ह्यूमन्स इन द लूप' जैसे सुरक्षा उपाय जरूरी होंगे।

कम रकम के एसआईपी खाते घटे

पृष्ठ 1 का शेष

1,001 से 3,000 रुपये किस्त वाले खातों की संख्या वित्त वर्ष 2026 में 0.5 फीसदी बढ़कर 3.35 करोड़ हो गई। 3,001 से 5,000 रुपये वाले खातों की संख्या 2.8 फीसदी बढ़कर 1.44 करोड़ हो गई। 5,001 से 10,000 रुपये की श्रेणी में संख्या 5 फीसदी बढ़कर 62 लाख रही। 10,000 रुपये से ज्यादा मासिक किस्त वाले एसआईपी खातों की संख्या 5.9 फीसदी बढ़कर 30 लाख रही।

बैंक ऑफ बड़ौदा के मुख्य अर्थशास्त्री मदन सबनवीस ने कहा कि अलग-अलग श्रेणी में दिख रहे अलग-अलग रुझान की कई वजहें हो सकती हैं। उन्होंने कहा, 'कोई एक वजह बताना मुश्किल है। शेयर बाजार में उतार-चढ़ाव निश्चित रूप से एक वजह हो सकती है क्योंकि हो सकता है कि कुछ निवेशकों को उम्मीद के मुताबिक रिटर्न न मिला हो। साथ ही एसआईपी का आधार भी बदला हो सकता है, जिसमें कम रकम वाले एसआईपी से निकलकर निवेशक ज्यादा रकम के एसआईपी में चले गए हों।'

वैल्यू रिसर्च के सीईओ धीरेंद्र कुमार ने कहा कि छोटी रकम वाले एसआईपी में गिरावट का मतलब यह नहीं है कि निवेशक म्युचुअल फंड से बाहर निकल ही रहे हैं। लेकिन कुछ कमी जरूर आ सकती है।

वेल्दीडॉटइन के सह संस्थापक आदित्य अग्रवाल ने कहा, 'हो सकता है कि आय बढ़ने और वित्तीय समझ बेहतर होने के साथ मौजूदा निवेशक एसआईपी किस्त की रकम बढ़ा रहे हों और छोटे-छोटे एसआईपी को मिलाकर बेहतर निवेश वाले विकल्पों में पैसा डाल रहे हों।'

इंडेक्स डेरिवेटिव के लिए एमएससीआई संग बीएसई की साझेदारी

स्टॉक एक्सचेंज बीएसई ने बुधवार को ऐलान किया कि उसने भारत में अपने इंडेक्स डेरिवेटिव अनुबंध लॉन्च करने के लिए वैश्विक सूचकांक प्रदाता एमएससीआई के साथ समझौता किया है। एक्सचेंज ने एक बयान में कहा, बीएसई नियामकीय मंजूरी मिलने पर इन इंडेक्स से जुड़े वायदा एवं विकल्प अनुबंध भारत में लॉन्च करने की संभावना तलाशेगा। यह रणनीतिक कदम भारतीय पूंजी बाजार को और विकसित करने में बीएसई की भूमिका मजबूत करता है।

31 दिसंबर, 2025 तक एमएससीआई इंडेक्स सबसे ज्यादा ट्रैक किए जाने वाले बेंचमार्क में से एक रहे हैं जो 21 लाख करोड़ डॉलर से ज्यादा की प्रबंधनाधीन परिसंपत्तियों (एयूएम) से जुड़े हैं। बीएसई ने बताया कि इंडेक्स से जुड़े डेरिवेटिव फंड फ्लो को आसान बनाने और इक्विटी निवेश के प्रबंधन में मैनेजरों की मदद कर सकते हैं। इसलिए कि इंडेक्स के आधार पर निर्धारित की गई पूंजी की मात्रा और एक्सचेंज-ट्रेडेड फंडों (ईटीएफ) के जरिये इंडेक्स आधारित प्रोडक्ट्स की ट्रेडेबिलिटी के कारण वायदा एवं विकल्प की जरूरत बढ़ गई है। बीएसई के प्रबंध निदेशक और सीईओ सुंदररामन राममूर्ति ने कहा, हमें गर्व है कि हम निवेशकों को भारतीय बगाजार में अपनी हिस्सेदारी तक पहुंचने और उसे हेज करने का एक और जरिया दे रहे हैं और भारत के बाजार तक पहुंच को और बेहतर बनाने की दिशा में आगे का कदम उठा रहे हैं। *बीएस*

— प्रायोजित परिशिष्ट

लॉर्ड्स मार्क इंडस्ट्रीज ने वैश्विक स्वास्थ्य सेवा, उन्नत डायग्नोस्टिक्स और ऑन्कोलॉजी में रणनीतिक विस्तार की रूपरेखा पेश की, वित्त वर्ष 2027 में ₹1,550 करोड़ राजस्व का लक्ष्य

विविधीकृत स्वास्थ्य सेवा और प्रौद्योगिकी क्षेत्र की प्रमुख कंपनी लॉर्ड्स मार्क इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने आज कई महत्वपूर्ण रणनीतिक और कारोबारी घोषणाएं कीं। इन घोषणाओं के तहत कंपनी अपने वैश्विक स्वास्थ्य सेवा प्लेटफॉर्म का विस्तार करेगी और साथ ही अपने नवीकरणीय ऊर्जा कारोबार के प्रस्तावित पुनर्गठन की दिशा में आगे बढ़ेगी।

Lord's hamesha aapke saath!™

वित्त वर्ष 2027 के लिए कंपनी को कम से कम ₹1,550 करोड़ के समेकित राजस्व की उम्मीद है, जो वित्त वर्ष 2026 की तुलना में 20% से अधिक की वृद्धि होगी। कंपनी को कम से कम ₹178 करोड़ के कर पश्चात लाभ (PAT) की भी उम्मीद है, जो 11.4% के मार्जिन को दर्शाता है। यह मार्जिन 200 बेसिस प्वाइंट से अधिक के विस्तार को दर्शाता है। वित्त वर्ष 2027 की वृद्धि का अधिकांश हिस्सा इन–विट्रो डायग्नोस्टिक्स और नवीकरणीय ऊर्जा के मुख्य कारोबार से आएगा। वित्त वर्ष 2028 से सिकल सेल टेस्टिंग कारोबार और मेडिकल डिवाइस प्लेटफॉर्म – ऑन्को स्पेक्ट्रा और टीबी ट्रुथ के व्यावसायीकरण से परिचालन में और गति आने की उम्मीद है।

पूंजी के बेहतर आवंटन और स्वतंत्र रूप से स्वास्थ्य सेवा कारोबार का मूल्यांकन करने के लिए निदेशक मंडल ने मार्च 2027 तक अपने नवीकरणीय ऊर्जा और एलईडी कारोबार को अलग इकाई लॉर्ड्स शक्ति पावर लिमिटेड में डीमर्ज करने का प्रस्ताव रखा है। लॉर्ड्स मार्क इंडस्ट्रीज नई बनने वाली कंपनी में 60% हिस्सेदारी रखेगी, जबकि मौजूदा शेयरधारकों को समान अनुपात में इक्विटी मिलेगी। डीमर्ज किया गया ऊर्जा कारोबार ट्रांसफॉर्मर निर्माण के माध्यम से पावर ट्रांसमिशन क्षेत्र में भी विस्तार करेगा।

स्वास्थ्य सेवा और साझेदारी के क्षेत्र में लॉर्ड्स मार्क भारत में CAR-T सेल थेरेपी लाने के लिए एक प्रमुख वैश्विक निर्माता के साथ विशेष समझौते में प्रवेश कर रही है। यह थेरेपी पांच विशेष केंद्रों के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएगी, जिसकी शुरुआत मार्च 2027 तक मुंबई और बेंगलुरु से होगी। इससे इलाज की लागत में उल्लेखनीय कमी आने और अधिक मरीजों तक उपचार की पहुंच बढ़ने की उम्मीद है। अपनी नई सहायक कंपनी लॉर्ड्स मार्क मेडिक्योर लिमिटेड के माध्यम से कंपनी टियर–2 शहरों में ऑन्कोलॉजी अस्पतालों का नेटवर्क शुरू कर रही है, ताकि गंभीर स्वास्थ्य सेवाओं की कमी को दूर किया जा सके। इसकी शुरुआत वापी और सोलापुर में 70–70 बिस्तरों वाले दो पायलट अस्पतालों से होगी।

इसके लिए दिसंबर 2026 में ₹200 करोड़ का ऋण जुटाने की योजना है। इसके अलावा, कंपनी मार्च 2027 तक पूरे भारत में 50 कंपनी–संचालित डायलिसिस केंद्र स्थापित करने की योजना बना रही है। इन केंद्रों में कंपनी की अपनी RENALOS मशीनें लगाई जाएंगी, जिससे नियमित सेवा से होने वाली आय की दिशा में कारोबार को आगे बढ़ाया जा सके।

अपने अंतरराष्ट्रीय विस्तार को बढ़ाते हुए कंपनी ने लॉर्ड्स मार्क इंडस्ट्रीज यूके लिमिटेड की स्थापना की है, जो भारत–यूके मुक्त व्यापार समझौते के तहत पंजीकृत होने वाली पहली भारतीय कंपनी है। इसके साथ ही लॉर्ड्स मार्क इंडस्ट्रीज स्विस लिमिटेड की स्थापना की जा रही है। दोनों इकाइयां भारत में स्थित विनिर्माण संयंत्रों से पूरी तरह आपूर्ति प्राप्त करने वाली पैथोलॉजी प्रयोगशालाओं का संचालन करेंगी और यूरोपीय बाजारों में डायग्नोस्टिक उत्पादों का वितरण करेंगी। NHS की मंजूरी के लिए आवेदन जमा किया जा चुका है। यह सहायक कंपनी कंपनी के IVD विनिर्माण कारोबार को विकसित बाजारों तक पहुंच उपलब्ध कराएगी और अंतरराष्ट्रीय कीमतों पर कारोबार का अवसर प्रदान करेगी।

नवाचार के क्षेत्र में ICMR की मंजूरी के बाद OneDNA जीनोमिक टेस्टिंग प्लेटफॉर्म के मरीजों पर परीक्षण पूरे हो चुके हैं। वहीं, Biomescan Analytics Platform भारत में मेडिकल डिवाइस नियम, 2017 के तहत विनिर्माण लाइसेंस प्राप्त करने वाला पहला सॉफ्टवेयर–एज–ए–मेडिकल–डिवाइस (SaMD) बन गया है।

इन घटनाक्रमों पर टिप्पणी करते हुए **लॉर्ड्स मार्क इंडस्ट्रीज लिमिटेड के प्रबंध निदेशक श्री सचिदानंद उपाध्याय** ने कहा, '"लॉर्ड्स मार्क आज अपने इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव पर खड़ी है। पिछले एक दशक में हमने डायग्नोस्टिक्स और नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में लाभदायक और बड़े स्तर पर संचालित कारोबार खड़े किए हैं, जिनकी नींव अब हमारे अगले चरण के विकास को वित्त प्रदान कर रही है। हमने जो अनुमान जारी किए हैं, वे हमारे मौजूदा कारोबार की मजबूती को दर्शाते हैं, जिसमें राजस्व में कम से कम 20% और PAT में कम से कम 50% की वृद्धि शामिल है। इसके बाद की घोषणाएं उसी आधार पर हमारे अगले विस्तार को दर्शाती हैं – भारत के ग्रामीण जिलों तक कैंसर उपचार पहुंचाना, भारतीय मरीजों के लिए किफायती कीमत पर उन्नत CAR-T थेरेपी उपलब्ध कराना और भारत में निर्मित डायग्नोस्टिक उत्पादों के माध्यम से ब्रिटेन से लेकर स्विट्जरलैंड तक की प्रयोगशालाओं की जरूरतें पूरी करना। भारत में स्वास्थ्य सेवा अब कमी से पहुंच की ओर बढ़ रही है और लॉर्ड्स मार्क उन कंपनियों में शामिल होना चाहती है जो इस बदलाव को संभव बनाएं।"

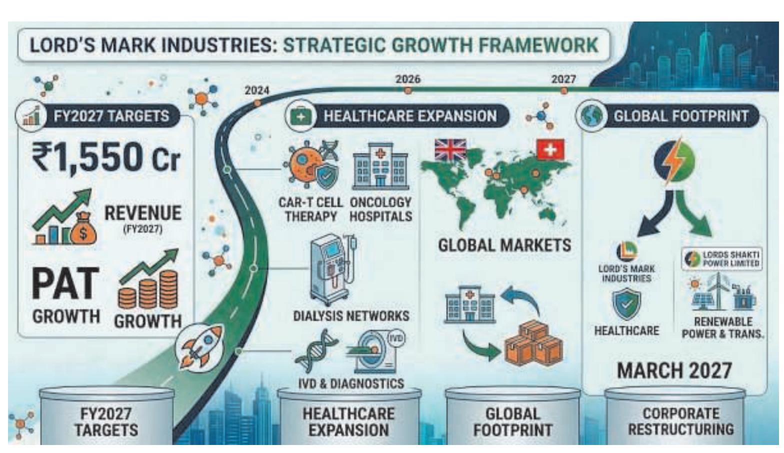

सरकारी बैंकों का 2% हो जलवायु-परिवर्तन लक्ष्य

कृति अंबे
नई दिल्ली, 19 अगस्त

वित्त मंत्री के समक्ष रखे प्रस्ताव

- ऋणदाताओं ने 'पीएसबी कॉन्फ्लुएंस' में वित्त मंत्री के समक्ष प्रस्ताव रखा
- अभी पीएसएल के तहत कोई अलग जलवायु या ट्रांजिशन उप-लक्ष्य नहीं है
- उप लक्ष्य भारत को शुद्ध-शून्य कार्बन उत्सर्जन लक्ष्य की ओर मदद करेगा
- इसमें वैश्विक संपत्ति प्रबंधकों को भारतीय बाजारों की ओर आकर्षित करने की भी क्षमता

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने अधिसूचित वाणिज्यिक बैंकों के लिए 40 प्रतिशत समायोजित शुद्ध बैंक ऋण (एएनबीसी) के मौजूदा प्राथमिकता-क्षेत्र ऋण (पीएसएल) की जरूरतों में जलवायु व परिवर्तन (क्लाइमेट व ट्रांजिशन) के वित्त के लिए 2 प्रतिशत उप-लक्ष्य निर्धारित करने का प्रस्ताव दिया है। उन्होंने पीएसएल के तहत नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र को ऋण देने के लिए उच्च ऋण सीमा और ढांचे के तहत इलेक्ट्रिक वाहन वित्त को शामिल करने की भी मांग की है।

ऋणदाताओं ने ये प्रस्ताव वित्तीय सेवा विभाग के दो दिवसीय विचार-मंथन सत्र 'पीएसबी कॉन्फ्लुएंस' के समापन दिवस पर मंगलवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के समक्ष रखे थे। अभी पीएसएल के तहत कोई अलग जलवायु या ट्रांजिशन उप-लक्ष्य नहीं है। पीएसएल ढांचे के अनुसार 40 प्रतिशत एएनबीसी लक्ष्य के उप-लक्ष्यों में कृषि ऋण (18 प्रतिशत); लघु उद्यम (7.5 प्रतिशत); अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अल्पसंख्यक समुदायों व स्वयं सहायता समूहों जैसे कमजोर वर्ग (12 प्रतिशत) और अन्य क्षेत्रों जैसे आवास, शिक्षा, नवीकरणीय ऊर्जा, सामाजिक अवसंरचना और निर्यात ऋण के लिए शेष राशि शामिल है।

इस बीच, विशेषज्ञों ने पीएसएल में जलवायु या परिवर्तनकाल उप-लक्ष्य की शुरुआत के लिए भारत में जलवायु वित्त के नामकरण व वर्गीकरण (क्लाइमेट फाइनैंस टैक्सानमी) की जरूरत पर प्रकाश डाला है। ईवाई इंडिया में वित्तीय सेवा जोखिम परामर्श के प्रमुख अजय सिरिकोंडा ने कहा, 'पीएसएल में जलवायु व ट्रांजिशन वित्त पर उप-लक्ष्य होना निश्चित रूप से मदद करेगा। यह भारत को शुद्ध-शून्य कार्बन उत्सर्जन लक्ष्य की ओर मदद करेगा और बाजार को आगे बढ़ने में मदद करेगा। हालांकि परिवर्तनकाल (ट्रांजिशन) वित्त क्या है, यह अभी भी भारत में मसौदा दिशानिर्देश है। इसे अंतिम रूप देने की आवश्यकता है। इसमें वैश्विक संपत्ति प्रबंधकों को भारतीय बाजारों में आकर्षित करने की भी क्षमता है।'

वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग (डीईए) ने पिछले साल क्लाइमेट फाइनैंस टैक्सानमी पर मसौदा ढांचा जारी किया था और सीतारमण ने 2024-25 (वित्त वर्ष 25) के बजट में इसकी घोषणा के बाद जून 2025 तक सार्वजनिक टिप्पणियां आमंत्रित की थीं। हालांकि अभी तक ढांचे को अंतिम रूप नहीं दिया गया है। वित्त मंत्रालय से क्लाइमेट फाइनैंस टैक्सानमी के अंतिम ढांचे पर नवीनतम जानकारी मांगी गई थी लेकिन खबर लिखे जाने तक तत्काल जवाब नहीं मिला।

इसके अलावा बैंकों को पीएसएल के तहत अनिवार्य होने से पहले ट्रांजिशन वित्त में अपनी विशेषज्ञता बढ़ाने की जरूरत होगी। पीडब्ल्यूसी इंडिया में वित्तीय सेवा और ट्रेजरी सलाहकार के पार्टनर कुंतल सुर ने कहा, 'ट्रांजिशन ऋण विशेषीकृ क्षेत्र है। इसमें लौह व इस्पात, रसायन व उर्वरक, और निर्माण जैसे उच्च-कार्बन-उत्सर्जक उद्योगों के लिए धन मुहैया कराना शामिल है। ऐसे ऋणों का आकलन करने के लिए बैंकों को प्रासंगिक प्रौद्योगिकियों, उत्सर्जन-कमी के रास्तों और उद्योग मानकों की मजबूत समझ होनी चाहिए। इसलिए कई बैंकों को ऐसी उप-लक्ष्य लागू करने से पहले विशेषज्ञता बनाने और प्रशिक्षण से गुजरने की जरूरत होगी।'

पीएसबी ने पवन व लघु जलविद्युत परियोजनाओं के लिए सीमा को 75 करोड़ रुपये तक बढ़ाने का भी प्रस्ताव दिया है। हालांकि सौर फोटोवोल्टिक परियोजनाओं के लिए मौजूदा 35 करोड़ रुपये की सीमा बनाए रखी है जबकि बैंकिंग प्रणाली से प्रति उधारकर्ता कुल सीमा 100 करोड़ रुपये बनी हुई है। नवीकरणीय ऊर्जा को धन मुहैया करने के लिए एकल उधारकर्ता को ऋण जोखिम सीमा 35 करोड़ रुपये है जिसमें सौर फोटोवोल्टिक, पवन और लघु जलविद्युत परियोजनाओं के लिए ऋण शामिल हैं।

बैंकों ने व्यक्तिगत उपयोग के लिए इलेक्ट्रिक दो-पहिया वाहनों के लिए 2 लाख रुपये तक के ऋण और इलेक्ट्रिक चार-पहिया वाहनों के लिए 20 लाख रुपये तक के ऋणों के लिए पीएसएल ट्रीटमेंट का प्रस्ताव दिया है। उन्होंने बैटरी-स्वैपिंग और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 25 लाख रुपये तक की ऋण सीमा और वाणिज्यिक बेड़े ऑपरेटरों के लिए 50 करोड़ रुपये तक की सीमा के पीएसएल ट्रीटमेंट का भी प्रस्ताव दिया है।

ट्रक का ईंधन दक्षता टूल दिसंबर तक आने की उम्मीद

दीपक पटेल
नई दिल्ली, 19 अगस्त

दूसरे चरण में इलेक्ट्रिक वाणिज्यिक गाड़ियों की रेंज की गणना भी शामिल होगी। इससे सरकार को यह पता लगाने का एक मानक तरीका मिल सकता है कि अलग-अलग स्थितियों में इलेक्ट्रिक ट्रक और बसें एक बार चार्ज करने पर कितनी दूर तक चल सकती हैं

मध्यम व भारी वाणिज्यिक गाड़ियों की वाहन दक्षता और कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन को मापने के लिए भारत का पहला प्रमाणन टूल दिसंबर तक तैयार हो सकता है। ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एआरएआई) इसे 4-9 फरवरी, 2027 को होने वाले 'भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो' में लॉन्च करने का लक्ष्य बना रही है।

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी ने एआरएआई को सुझाव दिया है कि भारी गाड़ियों के लिए इस टूल को लागू करने का काम बीएस-VII के साथ जोड़ा जा सकता है। बीएस-VII भारत के गाड़ी उत्सर्जन नियमों का अगला चरण है। बीएस-VII नियमों को 2027 के मध्य से लागू किए जाने की उम्मीद है। भारी उद्योग मंत्रालय के तहत एआरएआई काम करती है।

इस टूल का दायरा आगे डीजल ट्रकों से आगे बढ़ेगा। इसके दूसरे चरण में इलेक्ट्रिक वाणिज्यिक गाड़ियों की रेंज की गणना भी शामिल होगी। इससे सरकार को यह पता लगाने का एक स्टैंडर्ड तरीका मिल सकता है कि अलग-अलग स्थितियों में इलेक्ट्रिक ट्रक और बसें एक बार चार्ज करने पर कितनी दूर तक चल सकती हैं। दरअसल, वाणिज्यिक गाड़ियों के खंड में इलेक्ट्रिक गाड़ियों का चलन तेज़ी से बढ़ रहा है।

अधिकारियों ने बताया कि एआरएआई ने इस परियोजना के तहत परीक्षण की जा रही सभी 16 डीजल गाड़ियों के प्रायोगिक परीक्षण पूरे कर लिए हैं और उनसे डेटा इकट्ठा कर लिया है। साथ ही चार 'प्रूफ़-ऑफ-कॉन्सेप्ट' (पीओसी) गाड़ियों के लिए इनपुट तैयार करने का काम भी पूरा हो गया है। पीओसी शुरुआती प्रक्रिया है। इसमें यह दिखाया जाता है कि कोई सिस्टम उम्मीद के मुताबिक काम करता है। अधिकारियों ने बताया कि 'भारत वीईसीटीओ' नाम के इस टूल का बीटा वर्शन, मूल्यांकन और फीडबैक के लिए जुलाई तक वाहन निर्माताओं को जारी करने का लक्ष्य रखा गया था।

इसके अलावा, एआरएआई ने आठ 'मिशन प्रोफाइल' भी तैयार कर रहा था। ये भारत में ट्रकों और बसों के इस्तेमाल के अलग-अलग तरीकों को दिखाने के मानक संचालन पैटर्न हैं। इनमें विभिन्न कारक शामिल हैं। इन कारकों में गति, वाहन में लदा भार, रूट और ड्राइविंग की स्थितियां हैं। इससे यह टूल असल कामकाज की परिस्थितियों में गाड़ी के प्रदर्शन का आकलन कर पाएगा। इन प्रोफाइलों को जुलाई तक पूरा करने का लक्ष्य भी रखा गया था।

यह साफ नहीं है कि इन प्रोफाइलों और टूल के बीटा वर्शन को मूल्यांकन और फीडबैक के लिए गाड़ी बनाने वाली कंपनियों के साथ साझा किया गया है या नहीं।

बिज़नेस स्टैंडर्ड ने भारत वीईसीटीओ कार्यक्रम के बारे में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, एआरएआई और सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स (सायम) को ईमेल करके सवाल पूछे थे लेकिन खबर लिखे जाने तक कोई जवाब नहीं मिला।

यह टूल वाणिज्यिक गाड़ी बनाने वाले उद्योग के लिए ट्रकों के डिजाइन और ऑप्टिमाइज़ेशन के तरीके को बदल सकता है। इसमें ईंधन दक्षता और कार्बन डाइआक्साइड के प्रदर्शन को किसी एक तय रफ्तार के बजाये अलग-अलग ऑपरेटिंग स्थितियों में आंका जाएगा। इससे विनिर्माताओं को पूरी गाड़ी की क्षमता को बेहतर बनाने के लिए बढ़ावा मिल सकता है, साथ ही फ्लीट ऑपरेटर्स को गाड़ियों की तुलना करने के लिए एक ज्यादा मानक आधार भी मिल सकता है।

विदेशी पूंजी आकर्षित करने के लिए काम कर रही सरकार

खुशबू तिवारी
मुंबई, 19 अगस्त

आर्थिक मामलों के विभाग (डीईए) के संयुक्त सचिव आलोक तिवारी ने बुधवार को कहा कि भारत को अपनी विकास से जुड़ी महत्त्वाकांक्षाओं का समर्थन करने और एक महत्त्वपूर्ण वित्तीय केंद्र के रूप में अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए अधिक विदेशी पूंजी को आकर्षित करने और कॉर्पोरेट बॉन्ड बाजार को गहरा करने की जरूरत है।

फिक्की कैपिटल मार्केट कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए तिवारी ने कहा, 'विदेशी पूंजी का स्वागत किया जाना चाहिए। विदेशी पूंजी को आकर्षित किया जाना चाहिए।' उन्होंने कहा, 'अभी कुछ चिंता है। हाल के दिनों में विदेशी पूंजी कम आई है। हालांकि जुलाई में यह चक्र बदलता नजर आ रहा है।' सरकार इस पर काम कर रही है।

उन्होंने कहा कि विदेशी पूंजी आकर्षित करने की जरूरत को लेकर सरकार, नियामकों और बाजार सहभागियों के बीच व्यापक सहमति की जरूरत है और इस दिशा में किए जा रहे प्रयास प्रगति पर हैं।

विदेशी निवेश को लेकर उन्होंने कहा कि सरकार वैधानिक ढांचे को सुव्यवस्थित करने के लिए भी काम कर रही है। उन्होंने कहा, 'विदेशी मुद्रा प्रबंधन (एफईएम) और संबंधित नियमों को फिर से तैयार किया जा रहा है और भारतीय रिजर्व बैंक इस समय इस मसले पर सार्वजनिक परामर्श ले रहा है। इसका उद्देश्य ढांचे को अधिक सिद्धांत आधारित, पालन करने में आसान और इससे निकलने में आसान बनाना है।'

अनिश्चितता घटाने पर काम जारी

मोनिका यादव
नई दिल्ली, 19 अगस्त

आयकर विभाग उन क्षेत्रों की जांच कर रहा है जहां अस्पष्टता अनिश्चितता और बनी हुई है।

आयकर विभाग अंतरराष्ट्रीय मामलों में स्पष्टता लाने और विसंगतियों को दूर करने के लिए काम कर रहा है। वरिष्ठ कर अधिकारी ने बुधवार को बताया कि सीमा पार लेन-देन और व्यावसायिक संरचनाएं कर प्रशासन को जटिल बनाती हैं।

आयकर (अंतरराष्ट्रीय कर) की प्रधान मुख्य आयुक्त मोनिका भाटिया ने कहा कि विभाग आम लोगों तक अपने कार्यक्रमों का विस्तार करके करदाताओं और अन्य हितधारकों के साथ नए आयकर अधिनियम पर काम कर रहा है। इससे उन क्षेत्रों की पहचान की जा सकेगी जहां स्पष्टता और मार्गदर्शन की जरूरत है। भाटिया ने उद्योग निकाय एसोचैम के अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में कहा, 'यह यात्रा है जिसे हम एक साथ तय करने की कोशिश कर रहे हैं।'

उन्होंने कहा कि टाइगर ग्लोबल मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले, नया आयकर अधिनियम, विवाद-समाधान तंत्र और प्रौद्योगिकी अंतरराष्ट्रीय कर परिदृश्य को नया आकार दे रहे थे। निवेशक के विश्वास के लिए सार, वाणिज्यिक औचित्य, नीति स्थिरता और अधिक निश्चितता महत्त्वपूर्ण बने हुए हैं।

उन्होंने कहा, 'नीति स्थिरता निवेशक के विश्वास की नींव है।' उन्होंने कहा कि सरकार ने टाइगर ग्लोबल फैसले के बाद पुरानी निवेशों को अधिक निश्चितता प्रदान करने के लिए उपाय किए हैं। उन्होंने भारत के 220 से अधिक हस्ताक्षरित समझौतों सहित हस्ताक्षरित 1,000 से अधिक अग्रिम मूल्य निर्धारण समझौतों (एपीए) का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि करदाताओं, पेशेवरों और कर प्रशासन के बीच सहयोग कर विवादों को कम करने में महत्त्वपूर्ण होगा। विभाग उन क्षेत्रों की जांच कर रहा है जहां अनिश्चितता और अस्पष्टता बनी हुई है। विभाग अंतरराष्ट्रीय कर प्रावधानों की व्याख्या और प्रशासन में अधिक स्पष्टता प्रदान करने की दिशा में काम कर रहा है। इसका ध्यान इस बात को तय करने पर है कि कर अधिकारी अंतरराष्ट्रीय कर मामलों को किस तरह से संभालते हैं, खासकर जब सीमा पार लेनदेन और बहुराष्ट्रीय व्यवसायों से जुड़े मामले अधिक जटिल हो जाते हैं। समान मामलों में अलग-अलग तरीके करदाताओं के लिए अनिश्चितता पैदा कर सकते हैं और संभावित रूप से लंबे विवादों का कारण बन सकते हैं।

एमपीसी सदस्यों ने दिए दर बढ़ाने के संकेत

पृष्ठ 1 का शेष...

समिति में बाहरी सदस्य सौगत भट्टाचार्य ने हेडलाइन महंगाई के निचले स्तर से धीरे-धीरे सामान्य होने की बात कही।

भट्टाचार्य ने कहा, 'पहले के सामान्य स्तरों से अंतर्निहित महंगाई के अनुमानित सामान्य होने की स्थिति में, नीतिगत दर को फिर से तय करने के सही समय के लिए वृद्धि और महंगाई के बीच के तालमेल पर बारीकी से नज़र रखने की ज़रूरत होगी।' आंतरिक सदस्य इंद्रनील भट्टाचार्य ने कहा कि हेडलाइन महंगाई दर में साफ तौर पर बढ़ोतरी का रुझान दिख रहा है और अगले 9 महीनों में यह औसतन 5.6 फीसदी रहेगी।

उन्होंने कहा, 'आगे मॉनसून और विकसित हो रही अल नीनो परिस्थितियां बारिश के वितरण और कृषि उत्पादन के लिए सीधा खतरा पैदा करती हैं। इसके अलावा समय-समय पर होने वाले भू-राजनीतिक झटकों से वैश्विक तेल कीमतों में तेज लेकिन अस्थिर उतार-चढ़ाव हो रहा है जिससे निकट अवधि का परिदृश्य अस्पष्ट बना हुआ है।'

आरबीआई ने वित्त वर्ष 2026 के लिए हेडलाइन खुदरा मुद्रास्फीति दर 5 फीसदी और वित्त वर्ष 2028 की पहली तिमाही के लिए 5.3 फीसदी रहने का अनुमान लगाया है। 2026-27 के लिए कोर महंगाई दर 4.3 फीसदी रहने का अनुमान है।

आरबीआई के एंटरप्राइज सर्वे का हवाला देते हुए बाहरी सदस्य राम सिंह ने कहा कि कच्चे माल की लागत का दबाव बढ़ गया है और इसका असर हेडलाइन खुदरा मुद्रास्फीति के आंकड़ों पर दिखने लगा है। उन्होंने कहा, 'अनुमानित आंकड़े सहज दायरे में हैं लेकिन 4 फीसदी के लक्ष्य से ऊपर की ओर का अंतर काफी अधिक रहने और कई तिमाहियों तक बने रहने के आसार हैं।' उन्होंने कहा कि वृद्धि के मोर्चे पर अर्थव्यवस्था ने उल्लेखनीय मजबूती दिखाई है।

एक और बाहरी सदस्य नागेश कुमार ने बहुत ज्यादा अनिश्चित आर्थिक माहौल में 'बेहद सतर्क' रहने की जरूरत पर जोर दिया।

कुमार ने कहा, 'भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि और महंगाई के नजरिये में थोड़ी बेहतरी से निश्चिंत नहीं हो जाना चाहिए।' उन्होंने कहा कि अल नीनो की वजह से कृषि में अनिश्चितता बनी हुई है। हालांकि जुलाई में देश के कई हिस्सों में मॉनसूनी बारिश में सुधार हुआ है। अब सभी की नजरें 5 से 7 अक्टूबर को होने वाली एमपीसी की अगली बैठक पर हैं।

वर्षों बाद चीनी आयात करेगा भारत!

पृष्ठ 1 का शेष...

अनुमान के अनुसार 2025-26 सीजन में भारत का शुद्ध चीनी उत्पादन, 24 लाख टन चीनी को एथनॉल बनाने में इस्तेमाल करने के बाद, करीब 2.79 करोड़ टन रहा है। 2025-26 सीजन की शुरुआत में भंडार करीब 47 लाख टन था।

इसका मतलब है कि कुल उपलब्धता करीब 3.26 करोड़ टन थी। इस साल चीनी की खपत लगभग 2.8 करोड़ टन रहने का अनुमान है। इससे करीब 47 लाख टन का क्लोजिंग स्टॉक बचना चाहिए था। लेकिन जैसे ही निर्यात के आंकड़े को इसमें शामिल किया जाता है और 8 लाख टन अतिरिक्त चीनी की खपत को जोड़ा जाता है तो क्लोजिंग स्टॉक घटकर करीब 35 से 39 लाख टन रह जाता है। इससे देश को चीनी की संभावित कमी का सामना करना पड़ रहा है।

एक अन्य अधिकारी ने कहा, 'आदर्श स्थिति में भारत के पास 60 लाख टन का सामान्य क्लोजिंग स्टॉक होना चाहिए जो तीन महीने की खपत के बराबर है। लेकिन मौजूदा स्थिति से संकेत मिलता है कि 1 अक्टूबर, 2026 से शुरू होने वाले 2026-27 सीजन की शुरुआत में भंडार जरूरी स्तर से कम हो सकता है।' यही वजह है कि अब चीनी के आयात की जरूरत पैदा हो रही है। सरकार ने मिलों को पेराई का काम जल्द शुरू करने की सलाह दी है ताकि बाजार में चीनी की उपलब्धता बनाए रखी जा सके। हालांकि शायद यह कदम संभावित कमी को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं हो और आयात की जरूरत पड़े। बड़ा सवाल यह है कि क्या 10 लाख टन चीनी के संभावित आयात से मिल स्तर पर और थोक कीमतों में बड़ी गिरावट आएगी? सूत्रों का कहना है कि ऐसा शायद नहीं होगा। उनके मुताबिक मौजूदा कीमतों में अधिकतम करीब 500 रुपये प्रति क्विंटल की कमी आ सकती है।

उद्योग के एक अधिकारी ने कहा, 'मिलों के लिए स्थिति इतनी खराब नहीं है क्योंकि कीमतों में 500 रुपये प्रति क्विंटल की कमी के बाद भी कीमतें 4,200 से 4,300 रुपये प्रति क्विंटल की उत्पादन लागत से ऊपर रहेंगी। इससे मिलों को किसानों के गन्ने का बकाया तेजी से चुकाने में मदद मिल सकती है।'

इस बीच लगभग एक दशक के अंतराल के बाद भारत द्वारा आयात की योजना बनाने की खबर से कुछ दिन पहले न्यूयॉर्क (बेंचमार्क इंडेक्स) में कच्ची चीनी की कीमतें 14 महीने के उच्चतम स्तर 17.47 सेंट प्रति पाउंड पर पहुंच गईं।

भूमि बैंक और नीतियों से आकर्षित कर रहे हैं योगी

वीरेंद्र सिंह रावत
लखनऊ, 19 अगस्त

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज राज्य की विकास को समर्थन करने वाली नीतियों और 75,000 एकड़ के एक मजबूत औद्योगिक भूमि बैंक का प्रदर्शन करके जापानी निवेशकों को लुभाने की कोशिश की।

नई दिल्ली में यूपी-जापान निवेश सम्मेलन 2026 को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने इस बात पर प्रकाश डाला कि उत्तर प्रदेश में 17 हवाई अड्डे परिचालन में हैं। साथ ही 2 समर्पित माल ढुलाई गलियारे और 7 शहरों में मेट्रो हैं।

उत्तर प्रदेश और जापान के बीच व्यावसायिक तालमेल की संभावना पर उन्होंने कहा, 'यह साझेदारी अब कारखानों से आगे बढ़कर प्रौद्योगिकी केंद्रों, अनुसंधान एवं विकास सुविधाओं, कौशल केंद्रों और वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं तक फैलनी चाहिए।' मुख्यमंत्री ने जापान की सटीकता, गुणवत्ता, अनुसंधान और विनिर्माण में ताकत को उत्तर प्रदेश के विशाल कार्यबल, बुनियादी ढांचे, बाजार और नीतिगत पारिस्थितिकी तंत्र के साथ जोड़ने का सुझाव दिया।

निवेशकों और व्यावसायिक दिग्गजों का 200 सदस्यीय जापानी प्रतिनिधिमंडल उत्तर प्रदेश और जापान के बीच पारस्परिक निवेश के अवसरों का पता लगाने के लिए 5 दिवसीय विचार-विमर्श में भाग ले रहा है। यह कार्यक्रम नई दिल्ली, लखनऊ, आगरा, ग्रेटर नोएडा और वाराणसी सहित 5 शहरों में आयोजित किया जाएगा।

यामानाशी प्रांत के गवर्नर कोतारो नागासाकी ने कहा कि 200 से अधिक जापानी प्रतिनिधियों की भागीदारी जापान-यूपी संबंधों में बढ़ते विश्वास को दर्शाती है।

बीएस सूडोकू 5671

2	1				6			9
		6			8			
		5						
				2	3	6		4
				7		5		
							9	2
		4					5	6
				4	9			8
6		8				2		3

परिणाम संख्या 5670

3	4	6	5	2	7	1	9	8
8	5	1	3	4	9	7	2	6
2	7	9	1	6	8	4	3	5
4	9	2	7	8	5	6	1	3
7	6	3	2	1	4	5	8	9
5	1	8	6	9	3	2	7	4
1	8	4	9	7	6	3	5	2
9	3	7	4	5	2	8	6	1
6	2	5	8	3	1	9	4	7

कैसे खेलें?

हर रो, कॉलम और 3 के बाई 3 के बॉक्स में 1 से लेकर 9 तक की संख्या भरें।

मुश्किल

★★★★☆

महिलाओं को समान अवसर तो बढ़ेगा कृषि उत्पादन

हेमलता सामंत
नई दिल्ली, 19 अगस्त

भारतीय कृषि में महिलाओं को पुरुषों की तुलना में समान काम करने पर भी 20 से 30 प्रतिशत कम कमाई होती है। पुरुष श्रमिक को अगर 100 रुपये मिलते हैं तो महिला श्रमिक को केवल 82 रुपये दिए जाते हैं। यह बात अनाज के कारोबार से जुड़े एकीकृत प्लेटफॉर्म आर्या डॉट एजी की रिपोर्ट 'हर हार्वेस्ट' में कही गई है।

रिपोर्ट के अनुसार मजदूरी, भू-स्वामित्व और संसाधनों की उपलब्धता में असमानता के कारण भारत को कृषि उत्पादन में हर साल 1.2 लाख करोड़ से 2 लाख करोड़ रुपये तक का नुकसान झेलना पड़ता है। यह आर्थिक नुकसान गांवों में बुनियादी असंतुलन के कारण हो रहा है।

इस समय लगभग 77 प्रतिशत कामकाजी ग्रामीण महिलाएं कृषि में लगी हुई हैं। वित्त वर्ष 2017-18 में कृषि श्रमबल में उनकी हिस्सेदारी 57 प्रतिशत थी, जो 2023-24 में बढ़कर 64 प्रतिशत से अधिक हो गई।

आधे से ज्यादा कृषि कार्य करने के बावजूद महिलाओं के पास कुल कृषि क्षेत्र का केवल 11.72 प्रतिशत हिस्सा है। इससे पता चलता है कि महिलाएं अपने नियंत्रण वाली कृषि भूमि के मुकाबले पांच गुना ज्यादा श्रम करती हैं। जो खेत महिलाएं चला रहे हैं, उनकी पैदावार 24 प्रतिशत कम है, जिससे भारत की 48.7 लाख करोड़ रुपये की कृषि अर्थव्यवस्था में उत्पादन 2.5 से 4 प्रतिशत कम रह जाता है।

भूमि का मालिकाना हक ही बताता है कि किसान कौन है, ऋण कसे मिलेगा, सहायता किसे मिलेगी और खरीद किसके लिए होगी। पुरुष तेजी से शहरों में जाकर गैर कृषि कार्यों में लग रहे हैं, इसलिए महिलाएं खेत संभाल रही हैं।

फिर भी कृषि क्षेत्र में काम करने वाली करीब 47.7 प्रतिशत महिलाएं परिवार के खेतों में बिना मजदूरी के काम कर रही हैं, जबकि ऐसे पुरुष केवल 20.2 प्रतिशत हैं।

इसकी शुरुआत तब होती है, जब महिलाओं को किसान नहीं माना जाता, जिससे उन्हें बैंकों से कर्ज नहीं मिलता, खाद-बीज आदि खरीदने में दिक्कत आती है और भंडारण की सुविधा भी नहीं मिलती। इसकी वजह से घबराहट में उन्हें अपनी उपज सस्ते में बेचनी पड़ती है, जिससे उनकी आमदनी कम रह जाती है और वे संपत्ति नहीं इकट्ठी कर पातीं। इस अंतर को पाटने का उपाय संसाधन, मान्यता और रिटर्न में निहित है।

समान संसाधन उपलब्ध कराने से महिलाओं द्वारा संचालित खेतों की उपज 20-30 प्रतिशत बढ़ जाएगी, जबकि महिला किसानों की आय में वृद्धि से समग्र घरेलू आय 20-30 प्रतिशत बढ़ जाएगी। रिपोर्ट में कहा गया है, 'एक महिला किसान द्वारा कमाया गया एक रुपया दोहरा काम करता है। शुरुआत में इससे उत्पादन बढ़ता है और बाद में लचीलापन आता है।'

नमो ड्रोन दीदी योजना के तहत महिलाओं के नेतृत्व वाले लगभग 15,000 स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) को कृषि ड्रोन से लैस किया जा रहा है, जिससे प्रशिक्षित ऑपरेटरों को प्रति माह 60,000 से 80,000 रुपये तक की कमाई करने में मदद मिलेगी।

डिस्क्लेमर.. बिज़नेस स्टैंडर्ड में प्रकाशित समाचार रिपोर्ट और फीचर लेखों के माध्यम से बाजारों, कॉरपोरेट जगत और सरकार से जुड़ी घटनाओं की निष्पक्ष तस्वीर पेश करने का प्रयास किया जाता है। बिज़नेस स्टैंडर्ड के नियंत्रण एवं जानकारी से परे परिस्थितियों के कारण वास्तविक घटनाक्रम भिन्न हो सकते हैं। समाचार पत्र में प्रकाशित रिपोर्टों के आधार पर पाठकों द्वारा किए जाने वाले निवेश और लिए जाने वाले कारोबारी निर्णयों के लिए बिज़नेस स्टैंडर्ड कोई जिम्मेदारी नहीं लेता है। पाठकों से स्वयं निर्णय लेने की अपेक्षा की जाती है। बिज़नेस स्टैंडर्ड के सभी विज्ञापन सद्भाव में स्वीकार किए जाते हैं। इनके साथ बिज़नेस स्टैंडर्ड न तो जुड़ा हुआ है और न ही उनका समर्थन करता है। विज्ञापनों से संबंधित किसी भी प्रकार का दावा संबंधित विज्ञापनदाता से ही किया जाना चाहिए। मै. बिज़नेस स्टैंडर्ड प्रा. लि. का सर्वाधिकार सुरक्षित है बिज़नेस स्टैंडर्ड प्रा. लि. से लिखित अनुमति लिए बगैर समाचार पत्र में प्रकाशित किसी भी सामग्री का किसी भी तरह प्रकाशन या प्रसारण निषिद्ध है। किसी भी व्यक्ति या वैधानिक निकाय द्वारा इस प्रकार का निषिद्ध कार्य किए जाने पर दीवानी और फौजदारी कार्यवाही शुरू की जाएगी।

बिज़नेस स्टैंडर्ड
वर्ष 19 अंक 158

नकदी का विरोधाभास

नकद लेनदेन के कई फायदे हैं। एक तो निपटान तुरंत हो जाता है और दूसरा लेनदेन की कोई लागत नहीं होती। इसके अलावा नकद लेनदेन गोपनीय भी बने रहते हैं। डिजिटल लेनदेन अपने पीछे एक निशान छोड़ते हैं और आवश्यकता पड़ने पर उनका पता लगाया जा सकता है। ऐसी तमाम वजह हैं जिनके चलते लोग नकदी का उपयोग करना पसंद करते हैं भले ही डिजिटल लेनदेन के माध्यमों का उल्लेखनीय विस्तार हो गया हो।

यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) की असाधारण सफलता के कारण डिजिटल लेनदेन का तेज विस्तार सहज ही यह संकेत देता है कि अर्थव्यवस्था में नकदी का उपयोग घटा है, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के डिप्टी गवर्नर शिरीष चंद्र मुर्मू ने जकार्ता, इंडोनेशिया में दिए गए एक संबोधन में इस पहलू को उजागर किया। उन्होंने कहा कि डिजिटल भुगतान अपनाए जाने के बावजूद नकद का प्रचलन कम नहीं हुआ है। विशेष रूप से ग्रामीण और कस्बाई क्षेत्रों, निम्न आय समूहों और छोटे व्यवसायों में इसका उपयोग हो रहा है।

बैंक नोट जारी करने का नियमन 1935 में रिजर्व बैंक की स्थापना के मुख्य कारणों में से एक था। केंद्रीय बैंक यह कार्य बैंकिंग प्रणाली और अन्य संस्थानों के सहयोग से करता रहा है। वर्तमान में लगभग संख्या के हिसाब से रुपये के 176 अरब नोट प्रचलन में हैं जो अमेरिकी डॉलर या यूरो नोटों की तुलना में कहीं अधिक हैं। इसकी मुख्य वजह यह है कि निम्न मूल्यवर्ग के नोटों की संख्या ज्यादा है। इससे प्रणाली में नए नोटों की बड़ी मात्रा में आपूर्ति और क्षतिग्रस्त नोटों को वापस लेना होता है। हर साल लगभग 28-30 अरब नए नोट छापे जाते हैं और लगभग 21 अरब नोट नष्ट कर दिए जाते हैं। यह हमेशा महत्त्वपूर्ण है कि नोट अच्छी गुणवत्ता के हों और उनमें आवश्यक सुरक्षा विशेषताएं मौजूद हों। मुद्रा प्रणाली को प्रभावी ढंग से चलाना मौद्रिक संप्रभुता बनाए रखने के लिए अत्यंत आवश्यक है। रिजर्व बैंक अब परीक्षण के आधार पर पॉलिमर नोट जारी करने की योजना बना रहा है। इससे नोट अधिक टिकाऊ होंगे और दीर्घकाल में यह किफायती होगा।

जैसा कि मुर्मू ने उल्लेख किया प्रचलन में मुद्रा दो अंकों की दर से बढ़ रही है भले ही व्यक्तिगत लेनदेन में नकद का हिस्सा घट रहा है। इससे रिजर्व बैंक के लिए भविष्य की मांग का अनुमान लगाना कठिन हो जाता है और उत्पादन व वितरण के लिहाज से जटिलताएं पैदा होती हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था में नकद की सतत मांग पर बहस होनी चाहिए। यह याद रखना महत्त्वपूर्ण है कि भारत ने 2016 में उच्च-मूल्य वाले नोटों को वापस ले लिया था जो मूल्य के हिसाब से प्रचलन में मौजूद मुद्रा का लगभग 86 फीसदी था। तब से डिजिटल माध्यमों का उपयोग बढ़ा है लेकिन नकद की मांग में उल्लेखनीय कमी नहीं आई है। नकदी और जीडीपी का अनुपात 2015-16 में 11.9 फीसदी था। यह 2020-21 में 14 फीसदी से अधिक हो गया और 2025-26 में यह 11 फीसदी पर था। बैंक फॉर इंटरनैशनल सेटलमेंट्स द्वारा संकलित आंकड़ों के अनुसार 2024 में यह अनुपात अमेरिका में 7.9 फीसदी और ब्रिटेन तथा ब्राजील में लगभग 3 फीसदी था।

भारतीय अर्थव्यवस्था में नकद की सतत मांग के कई कारण हो सकते हैं। उदाहरण के लिए यह एक बड़े अनौपचारिक क्षेत्र का प्रतिबिंब हो सकता है जो डिजिटल माध्यमों से बचकर अनौपचारिक प्रणाली में बना रहना चाहता है। कुछ लोग करों से बचने के लिए नकद का उपयोग कर सकते हैं। प्रमाण बताते हैं कि निर्माण और रियल एस्टेट क्षेत्रों में करों से बचने के लिए नकदी का भारी उपयोग होता है। इस प्रकार केंद्र और राज्य सरकारें इस क्षेत्र से कर राजस्व खो रही होंगी। हालांकि यह ध्यान रखना चाहिए कि नकद का प्रचलन अपने आप में काले धन का संकेत नहीं है। इसके अन्य कारण भी हो सकते हैं। उदाहरण के लिए जैसे सुविधा या नकद रखने की कम अवसर लागत। उदाहरण के लिए जापान में कई वर्षों से ब्याज दरें कम रही हैं और वहां नकदी और जीडीपी का अनुपात 20 फीसदी से अधिक है। तमाम हालात को देखते हुए भारत में नकद की मांग ऊंची प्रतीत होती है और इसकी गहन पड़ताल आवश्यक है।

छोटे अनौपचारिक कारोबार पर ध्यान देने की जरूरत

अब वक्त आ गया है कि भारत अपने अनौपचारिक छोटे व्यवसायों को कानूनी मान्यता दे और उनके लिए निर्धारित जगह बनाए। विस्तार से बता रहे हैं लवीश भंडारी

भारत के डीएनए में मैकाले अलग-अलग तरह से नजर आते हैं। वह केवल भाषा में ही नहीं दिखते बल्कि भारत जिस तरह खुद के लिए 'आधुनिक' दृष्टि की रचना करना चाह रहा है, उसमें भी इसे देखा जा सकता है। औपनिवेशिक भारत में जब ब्रिटिशों ने शहरों को डिजाइन किया तो उनका प्राथमिक लक्ष्य था अपनी छावनियों और प्रशासनिक क्षेत्रों के लिए जगह बनाना। वे भारत की भीड़भाड़ से दूर वहीं पर अपने और अपने परिवारों के लिए व्यवस्थित जगह बना सकते थे। उन्होंने अल्प आय वाले लोगों के लिए बाजारों, छोटी दुकानों या खानपान के ठिकानों का निर्माण नहीं किया। न ही उन्होंने छोटी आर्थिक गतिविधियां तैयार कीं जो भारत में कारगर साबित होतीं। वैसी जगहें पुराने शहरों या आसपास के इलाकों के लिए छोड़ दी गईं। कई बार उन्हें झुग्गियों का नाम दिया गया तो अक्सर उनकी अनदेखी कर दी गई।

बदकिस्मती से जिन्होंने जिम्मेदारी संभाली उन्होंने भी लगभग पूरी तरह पश्चिमी शहरों की छवि में ही शहर बनाने पर ध्यान केंद्रित किया। इसके बाद जो भयावह स्थिति पैदा हुई, उसका कोई दस्तावेज़ नहीं है; लेकिन शायद ऐसी चीज को दर्ज करने की ज़रूरत भी नहीं है जो इतनी साफ़ तौर पर दिखाई दे रही हो। भारत की जनसंख्या कई गुना बढ़ी और शहरी जनसंख्या उससे भी अधिक फिर भी कम लागत वाले आवासीय स्थान बहुत कम बनाए गए। और इससे भी बुरा यह कि कम आय वाले आर्थिक कार्यों के लिए कोई जगह ही नहीं बनाई गई।

अगर केवल दुकानों पर ध्यान दें तो यह बात चकित करती है कि भारत ने चायवाले, पानवाले, जूसवाले, रेहड़ीवाले, मैकेनिक, सब्जीवाले या फिर साप्ताहिक हाट के लिए कोई जगह नहीं बनाई। इनके लिए शहरी भारत में लगभग कोई स्थान आवंटन नहीं है। लेकिन यह केवल दुकानों तक सीमित नहीं है। कचरा संग्रहण, निर्माण ठेकेदारी, सूक्ष्म स्तर पर वस्त्र निर्माण जैसी गतिविधियों को भी अनदेखा किया गया और आज भी किया जा रहा है। भारतीय शहरों में जहां जगह आवंटित की गई जैसे सब्जी मंडियों आदि में, वहां भी स्थिति बेहद दयनीय है।

पूर्ववर्ती योजना आयोग के दस्तावेजों या उन अनेक समितियों को देखें जिनका उद्देश्य नीतियों को दिशा देना था। वहां केवल गरीबों के लिए कम लागत वाले आवास का उल्लेख मिलता है सूक्ष्म आर्थिक गतिविधियों का नहीं। लेकिन ये गतिविधियां अत्यंत महत्त्वपूर्ण हैं। शहरी भारत इनके बिना न तो आर्थिक रूप से उत्पादक हो सकता है और न ही सामाजिक रूप से समावेशी। इनकी तादाद बहुत अधिक है। शहरी भारत में कार्यरत लगभग 19 करोड़ लोगों में से 80 फीसदी से अधिक अनौपचारिक क्षेत्र में हैं। और यह कहना सुरक्षित होगा कि इनमें से अधिकांश बहुत छोटे कारोबार हैं।

इसीलिए, वैध स्थान की कमी भारत के बड़े शहरी अनौपचारिक क्षेत्र को बनाए रखने वाला एक प्रमुख कारक है क्योंकि हम अपने शहरों में ऐसी गतिविधियों के लिए जगह आवंटित नहीं करते, ये इकाइयां प्रभावी रूप से वैध नहीं होतीं। और चूंकि वे वैध नहीं हैं इसलिए उन्हें अनौपचारिक या असंगठित कहा जाता है और अधिकांशतः अनदेखा कर दिया जाता है।

केवल सरकार की बात नहीं, हम शायद ही कभी देखते हैं कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) से जुड़ी पहलें इस क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करती हों। स्टार्टअप्स भी इस क्षेत्र की इकाइयों की सेवा को लगभग नजरअंदाज करते हैं। कौशल विकास से जुड़ी पहलें चाहे निजी हों या सार्वजनिक, वे इस खंड को अधिकतम सतही रूप से ही छूती हैं। शैक्षणिक शोधकर्ता, थिंक टैंक और यहां तक कि पीएचडी छात्र भी शायद ही कभी इन पर अध्ययन करते हैं।

इस अज्ञानता और कानूनी मान्यता की कमी ने कई प्रकार के अवांछित परिणामों को जन्म दिया है। पहली बात तो यह कि ऐसी इकाइयां स्थानीय दबंगों और सरकारी कर्मचारियों के लिए नाजुक हो जाती हैं। उदाहरण के लिए 'हफ्ता' शहरी भारत में एक सार्वभौमिक घटना है। यह सांस्कृतिक नहीं बल्कि इस कानूनी अस्पष्टता का परिणाम है। दूसरा, ऐसे व्यवसायों में निवेश की प्रेरणा काफी कम हो जाती है क्योंकि उस स्थान पर स्थायित्व की कोई निश्चितता नहीं होती। तीसरा, औपचारिक रूप लेने की क्षमता लगभग समाप्त हो जाती है क्योंकि योजनाकारों ने भारतीय शहरों में मांग केंद्रों के पास छोटे स्थान नहीं बनाए।

अनौपचारिक क्षेत्र पर होने वाली बहस और नीतिगत प्रवृत्ति अक्सर इसे अधिक औपचारिक बनाने और आर्थिक मुख्यधारा में लाने पर केंद्रित रहती है। लेकिन हमारा तर्क यह है कि रोजगार के लिहाज से यह खंड ही मुख्यधारा है। जिस तरह हम संगठित क्षेत्र के लिए व्यवसाय करने में आसानी पर ध्यान देते हैं उसी तरह यदि हमारे पास अनौपचारिक क्षेत्र के लिए भी समान नीति उद्देश्य हों तो यह अत्यंत सहायक होगा।

यह सही है कि अनौपचारिक क्षेत्र को बढ़ावा देने के खिलाफ कई तर्क दिए जाते हैं। जैसे कि वे श्रम सुरक्षा कानूनों का पालन नहीं करते, कर नहीं देते, या स्वच्छता और कार्यस्थल सुरक्षा जैसे नियमों का पालन नहीं करते। लेकिन इनमें से प्रत्येक तर्क सही नहीं है। पहला, यहां बात यह नहीं है कि ऐसी इकाइयों को बढ़ावा दिया जाए, बल्कि यह है कि उन्हें कानूनी रूप से अस्तित्व में रहने दिया जाए। इसके लिए स्थान आवंटित किया जाए। दूसरा, वे अपने उत्पाद खंडों पर लागू अप्रत्यक्ष करों में योगदान करते हैं और वे इतने छोटे होते हैं कि प्रत्यक्ष कर के दायरे में नहीं आते। तीसरा, सुरक्षा, स्वच्छता और कार्यस्थल नियमों को लागू करना तब आसान होगा जब उनके पास निर्धारित स्थान हो।

उनके खिलाफ एक और तर्क उनकी कम उत्पादकता, कौशल की कमी और तकनीक के कमजोर उपयोग से जुड़ा है। लेकिन ये तर्क भी त्रुटिपूर्ण हैं। उदाहरण के लिए, यूपीआई और डिजिटल भुगतान को भारत भर में ऐसी इकाइयों ने पूरे उत्साह से अपनाया है। ये उपयोग में आसान हैं, इनके लिए बहुत कम प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है। ये भुगतान को सरल बनाते हैं, तरलता प्रबंधन में मदद करते हैं और चोरी व नकद उगाही के जोखिम को कम करते हैं।

मुख्य बात यह है कि यह खंड सकारात्मक समर्थन के प्रति अत्यधिक जवाबदेह हो सकता है। इसके अलावा, लगभग सार्वभौमिक साक्षरता, बड़ी संख्या में शिक्षित लोग, डिजिटल अधोसंरचना के प्रसार से सूचना तक बेहतर पहुंच, आर्टिफिशल इंटेलिजेंस समाधानों की वृद्धि और एक गतिशील स्टार्टअप इकोसिस्टम के साथ, ऐसे सूक्ष्म व्यवसायों की उत्पादकता सीढ़ी पर ऊपर चढ़ने की क्षमता अत्यधिक बढ़ गई है।

ऐसे में भारत को क्या करना चाहिए? इसका उत्तर इस स्वीकार्यता में है कि भारत की अर्थव्यवस्था का समस्त औपचारिकीकरण अभी दशकों दूर है। इसलिए जबकि भारत को व्यवसाय करने में आसानी और निर्माण बढ़ाने जैसे प्रयास जारी रखने की आवश्यकता है, सूक्ष्म व्यवसायों के लिए उनके मांग केंद्रों के पास स्थान उपलब्ध कराना होगा। इसके लिए शहर प्रशासन को प्रमुख बाजारों, आवासीय क्षेत्रों और परिवहन केंद्रों के पास जगह आवंटित करनी होगी। ऐसी पहल के सहायक लाभ देखें तो कम लागत वाले किराए से नगर निगम की आय में सुधार और हफ्ता अर्थव्यवस्था पर चोट इसमें शामिल हो सकता है।

निस्संदेह, भारत की संघीय संरचना के कारण यह प्रशासनिक रूप से बहुत बड़ी मांग है। इसके अलावा, कई स्थानीय राजनेता, राज्य सरकारें और यहां तक कि शहर प्रशासन भी इसका विरोध कर सकते हैं क्योंकि उन्हें इससे बहुत कुछ खोना पड़ेगा। लेकिन केंद्र सरकार एक सक्षम भूमिका निभा सकती है। उदाहरण के लिए वर्तमान में 90 से अधिक शहर प्रशासन सीधे उसके नियंत्रण में हैं। सरकार ने हाल ही में कई नए शहरों के निर्माण की घोषणा भी की है। केंद्र सरकार का समर्थन राज्य और शहर सरकारों को इस शर्त पर दिया जा सकता है कि वे ऐसी गतिविधियों के लिए स्थान आवंटित करें। और भी कई संभावनाएं हैं जिनके लिए अतिरिक्त वित्तीय आवंटन की आवश्यकता नहीं होगी।

केंद्र सरकार ने राज्यों और शहरों में इससे कहीं अधिक कठिन कार्यक्रमों को सफलतापूर्वक लागू किया है। इसलिए उसे नेतृत्व करना होगा तथा राज्यों के लिए अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत करने होंगे।

(लेखक सेंटर फॉर सोशल ऐंड इकनॉमिक प्रोग्रेस के प्रमुख हैं। ये उनके निजी विचार हैं)

नीतियों से नहीं, सक्षम नेतृत्व से आएगी आर्थिक समृद्धि

अतार्किक विकल्प

देवाशिष बसु

आर्थिक समृद्धि का रास्ता क्या है? इसके आदर्श जवाब में विभिन्न मॉडल, नीतियां और योजनाएं आदि शामिल होती हैं। परंतु यह निष्कर्ष निकालना कि सही नीतियां और मॉडल खुदबखुद समृद्धि ले आएंगे, ऐसा ही है जैसे 'यह मानना कि अगर अंडों, चीनी और आटे को रात भर मिलाकर छोड़ दिया जाए तो वह खुद केक में बदल जाएगा।' सिंगापुर की राजनीति विज्ञानी और 'हाउ चाइना एस्केप्ड द पॉवर्टी ट्रैप' की लेखिका यूएन यूएन आंग का यह कथन एकदम सटीक है।

समृद्धि की कामना करनी होती है और उसका निर्माण करना होता है। यहां एक और बुनियादी प्रश्न उत्पन्न होता है? इसे कौन करेगा, और क्यों? दिलचस्प बात यह है कि विकास अर्थशास्त्र ने कभी भी समृद्धि की व्याख्या के केंद्र में नेतृत्व को नहीं रखा जबकि नेतृत्व यह तय कर सकता है कि कोई देश सही समय पर सही आर्थिक और सामाजिक निर्णय लेता है या नहीं।

विचारकों ने लंबे समय से यह समझाने की कोशिश की है कि कुछ राष्ट्र अमीर क्यों बनते हैं जबकि अन्य गरीब ही रहते हैं। डेविड ह्यूम, एडम स्मिथ और डेविड रिकार्डो ने आर्थिक वृद्धि को राजनीतिक अर्थशास्त्र का केंद्र माना लेकिन आधुनिक वृद्धि सिद्धांत केवल 1940 के दशक में हैरोड-डोमर मॉडल और बाद में सोलो-स्वान ढांचे के साथ उभरा। सोलो ने स्थापित किया कि दीर्घकालिक वृद्धि पूंजी संचय, श्रम और तकनीकी प्रगति पर निर्भर करती है। 1980 के दशक से पॉल रोमर और रॉबर्ट लुकास ने मॉडल में तकनीक और ज्ञान सृजन को शामिल किया और नवाचार, अनुसंधान एवं विकास, मानव पूंजी और 'सीखते हुए करने' को सतत वृद्धि के स्रोत के रूप में महत्त्व दिया।

संस्थागत अर्थशास्त्रियों जैसे डगलस नॉर्थ और बाद में डैरन एसेमोगलू तथा जेम्स रॉबिन्सन ने ध्यान को वृद्धि के गहरे निर्धारकों की ओर मोड़ा यानी संपत्ति अधिकार, शासन, कानून का शासन और राजनीतिक संस्थाएं। इन सिद्धांतों के साथ-साथ संरचनावादी स्कूल भी चला, जो पॉल रोसेनस्टीन-रोडान से जुड़ा था। उन्होंने तर्क दिया कि केवल बाजार गरीब देशों में समन्वय विफलताओं, पैमाने की अर्थव्यवस्थाओं और संरचनात्मक कठोरताओं को दूर नहीं कर सकते। उन्होंने औद्योगिक नीति और सार्वजनिक निवेश का उपयोग करने वाले सक्रिय विकासशील राज्य की वकालत की।

विकासशील दुनिया में राज्य के हस्तक्षेप के निराशाजनक परिणाम, 1980 के दशक के ऋण संकट और समाजवादी अर्थव्यवस्थाओं के पतन ने बौद्धिक सहमति को एक बार फिर बाजारों की ओर मोड़ दिया। वॉशिंगटन सहमति ने इस अदृश्य हाथ पर विश्वास को मूर्त रूप दिया यानी उदारीकरण, निजीकरण, नियम-कानून कम करना और व्यापक आर्थिक अनुशासन बनाए रखना। लेकिन यह भी अधूरा साबित हुआ। ध्यान दीजिए कि इस बौद्धिक इतिहास से क्या गायब है: नेतृत्व।

यह आश्चर्यजनक है क्योंकि गरीब देशों का बड़ा हिस्सा ऐसे तंत्रों से संचालित होता है जो क्लेप्टोक्रेट्स (ऐसे शासक जो सत्ता में रहते हुए राज्य की संपत्ति और संसाधनों का दुरुपयोग करके उसे निजी लाभ के लिए लूटते हैं) और जड़ जमाए हुए अभिजात वर्ग को राज्य पर कब्जा करने की अनुमति देते हैं। आर्थिक सिद्धांत में कितना भी सुधार कर लिया जाए, उससे विकास नहीं हो सकता, जब राजनीतिक नेता तंत्र का फ़ायदा खुद उठाने पर ही आमादा हों। नेतृत्व लगभग हर संगठन (सामाजिक या कॉरपोरेट) में निर्णायक कारक होता है। तो फिर किसी देश के लिए यह अलग क्यों होना चाहिए? क्या कोई सोचता है कि जमशेदजी टाटा ने टाटा साम्राज्य बनाने में केंद्रीय भूमिका नहीं निभाई या कि टेस्ला और स्पेसएक्स उतना ही अच्छा करते यदि ईलॉन मस्क के अलावा कोई और उनका नेतृत्व करता?

क्या इसे आंकड़ों से तय किया जा सकता है? अर्थशास्त्रियों बेंजामिन जोन्स और बेंजामिन ओल्केन ने पद पर रहते हुए राष्ट्रीय नेताओं की आकस्मिक, बाहरी कारणों से होने वाली मौतों का विश्लेषण किया। किसी नेता की अप्रत्याशित मृत्यु से ठीक पहले और बाद में आर्थिक प्रदर्शन को मापकर उनके शोध ने पाया कि कार्यकारी नेतृत्व सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि दरों में भारी बदलाव लाता है।

विश्व बैंक के 2010 का एक शोध-पत्र 'नेतृत्व एवं वृद्धि' कुछ उपयोगी संकेत देता है। सिंगापुर के अनुभव और गोह चोक तोंग (जो 1990 से 2004 तक वहां के प्रधानमंत्री रहे) के विचारों पर आधारित यह अध्ययन तीन व्यापक सफलता कारकों की पहचान करता है: पहला, संसाधन (प्राकृतिक संपदा, विरासत में मिली संस्थाएं और संचय, दूसरा वृद्धि प्रतिमान (जैसे धन वितरण बनाम धन सृजन) और तीसरा, सही नीतियों का निर्माण और उनका प्रभावी क्रियान्वयन। अनुभवजन्य साक्ष्य दिखाते हैं कि तीसरा बिंदु बाकियों पर भारी पड़ सकता है। अब हम जानते हैं कि वृद्धि कारकों की पृष्ठभूमि मात्र से कहीं अधिक, कार्यकारी नेतृत्व ही दक्षिण कोरिया, ताइवान, सिंगापुर और चीन में विकास का मुख्य चालक रहा है।

भले ही किसी देश के पास प्राकृतिक संसाधन न हों (जैसे सिंगापुर) और वह किसी पूर्वनिर्धारित वृद्धि प्रतिमान या विरासत में मिली संस्थाओं से शुरुआत न करे, समझदार नेता सीखते हुए करने की प्रक्रिया से सीख सकते हैं, दिशा सुधार सकते हैं और अपने देशों को रूपांतरित कर सकते हैं। गोह इस बात पर जोर देते हैं कि सतत वृद्धि अक्सर नीतियों के लगातार सूक्ष्म सुधार का परिणाम होती है। यह समीक्षा प्रक्रिया, स्पष्ट रूप से परिभाषित मानकों के विरुद्ध ईमानदार आत्म-चिंतन के माध्यम से आवश्यक जवाबदेही प्रदान करती है। ऐसी नीतियों, उनके क्रियान्वयन और नीति समीक्षा को क्या निर्धारित करता है? वे तीन कारकों की पहचान करते हैं। मजबूत संस्थाएं, नेतृत्व और सामाजिक सहमति। ध्यान देने वाली बात है कि कमजोर नेतृत्व अन्य दो को उत्पन्न नहीं कर सकता।

यहां एक अहम सवाल पैदा होता है। एक अच्छे नेता के गुण क्या हैं? गोह कहते हैं कि नेताओं को दूरदर्शी और परिश्रमी होना चाहिए और उन्हें पार्टी या व्यक्तिगत हितों के बजाय निस्वार्थ भाव से राष्ट्रीय हितों के प्रति समर्पित होना चाहिए। विश्वसनीयता के लिए नेताओं में ईमानदारी होनी चाहिए और वे भ्रष्टाचार से अछूते हों।

स्पष्ट है कि किसी अर्थव्यवस्था को सतत उच्च वृद्धि के मार्ग पर ले जाने के लिए आक्रामक विकल्पों की आवश्यकता होती है: बेहतर से बेहतर मानव पूंजी का निर्माण, वैश्विक बाजारों में एकीकरण, लगातार तकनीक को आत्मसात करना और दक्षता को बढ़ावा देना ताकि अधोसंरचना लागत कम बनी रहे। लेकिन ये सब अपने आप नहीं हो सकता। यह नेतृत्व ही है (ईमानदार, बुद्धिमान, दूरदर्शी और दिशा सुधार के प्रति प्रतिबद्ध) जो यह सब संभव बनाता है।

अनुभवजन्य साक्ष्य यही कहते हैं। अब समय आ गया है कि वृद्धि सिद्धांत भी इस सच्चाई को स्वीकार करें।

(लेखक मनीलाइफ डॉट इन के सह-संस्थापक और मनीलाइफ फाउंडेशन के न्यासी हैं। ये उनके निजी विचार हैं)

आपका पक्ष

विदेशी पूंजी निवेश के बाद श्रम व उत्पादकता पर हो जोर

भारत को विकसित अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में सरकार लगातार ऐसे कदम उठा रही है, जिनसे देश में विदेशी पूंजी आए, निवेश का माहौल बेहतर हो और उद्योगों को वैश्विक प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार किया जा सके। हाल में लोक सभा में पारित कराधान एवं अन्य कानून (संशोधन) विधेयक, 2026 इसी दिशा का महत्त्वपूर्ण प्रयास है। इसमें विदेशी निवेश को आकर्षित करने, कर व्यवस्था को अधिक स्पष्ट बनाने, इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण को बढ़ावा देने और निवेश से जुड़े नियमों को आसान बनाने जैसे प्रावधान हैं। इसी क्रम में भारतीय रिजर्व बैंक की विदेशी मुद्रा जुटाने से संबंधित स्वैप सुविधा भी महत्त्वपूर्ण है। इसके माध्यम से बैंकों को एफसीएनआर (बी) जमा, बाहरी वाणिज्यिक उधार और विदेश से लिए गए विदेशी मुद्रा ऋण जैसे माध्यमों से संसाधन जुटाने में सुविधा मिल रही है। लेकिन केवल विदेशी पूंजी और

भारतीय उद्योगों को प्रतिस्पर्धा के लिए अपनी क्षमता बढ़ानी होगी

सरकारी नीतियां भारत को चीन जैसे विनिर्माण केंद्रों से आगे नहीं ले जा सकतीं। अब असली जिम्मेदारी उद्योग जगत, श्रमिकों और आम नागरिकों की है। विदेशी निवेशक तभी लंबे समय तक भारत में टिकेंगे, जब यहां उन्हें गुणवत्तापूर्ण उत्पाद, कुशल श्रम, समय पर आपूर्ति, भरोसेमंद बुनियादी ढांचा और प्रतिस्पर्धी लागत मिले। उद्योगों को प्रतिस्पर्धा के लिए अपनी क्षमता बढ़ानी होगी और नागरिकों को समय, श्रम तथा उत्पादकता महत्त्व को समझना होगा। अगर सरकार की नीतियों के साथ उद्योग की दक्षता और नागरिकों का परिश्रम जुड़ जाए, तो भारत केवल विदेशी निवेश का गंतव्य नहीं, बल्कि दुनिया का प्रमुख विनिर्माण और निर्यात केंद्र बन सकता है।

सुभाष बुड़ावन वाला, रतलाम

एनालॉग पनीर बनाम असली पनीर की पहचान

आजकल एनालॉग पनीर का प्रचलन बाजारों में बढ़ा है। पनीर के नाम पर यह धड़ल्ले से बिक रहा है। रक्षाबंधन जैसे त्योहारों के मौसम में जब मिठाइयों और पनीर की मांग बढ़ती है, तब 'एनालॉग पनीर' का बाजार में बढ़ना गंभीर खाद्य-सुरक्षा चिंता है। एनालॉग पनीर ऐसा उत्पाद है जिसमें दूध के स्थान पर या दूध के घटकों के स्थान पर वनस्पति वसा, प्रोटीन अथवा अन्य गैर-दुग्ध सामग्री का इस्तेमाल किया जा सकता है। एफएसएसएआई स्वयं डेरी एनालॉग को ऐसे उत्पादों के रूप में परिभाषित करता है जो पारंपरिक दुग्ध उत्पादों जैसे दिखते और उपयोग होते हैं, लेकिन उनमें गैर-दुग्ध घटक आंशिक या पूरी तरह इस्तेमाल किए जाते हैं। हालांकि एनालॉग उत्पाद 'जहर' या मिलावटी पदार्थ नहीं है। असली समस्या तब पैदा होती है जब उसे असली पनीर बताकर बेचा या परोसा जाए। एफएसएसएआई के मानकों में पनीर को दूध अथवा दूध के ठोस पदार्थों से बने उत्पाद के रूप में परिभाषित किया गया है। हाल में मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात आदि प्रदेशों में एनालॉग पनीर के खिलाफ कार्रवाई और प्रतिबंध की खबरों ने इस विषय को विशेष रूप से गंभीर बना दिया है। सस्ते होने के कारण इसका इस्तेमाल होटल, रेस्तरां, कैटरिंग और ढाबों में बढ़ा है। ग्राहक पनीर समझकर इसकी कीमत चुका रहे हैं। अगर उपभोक्ता पनीर खरीद रहा है तो उसे पनीर ही मिलना चाहिए 'पनीर जैसा कुछ' नहीं।

इशरत अली कादरी, भोपाल

पाठक अपनी राय हमें इस पते पर भेज सकते हैं : संपादक, बिज़नेस स्टैंडर्ड, 4, बहादुर शाह जफर मार्ग, नई दिल्ली 110002. आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं : lettershindi@bsmail.in
पत्र/ईमेल में अपना डाक पता और टेलीफोन नंबर अवश्य लिखें।

देश-दुनिया

फोटो - पीटीआई

विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सिंगापुर में बुधवार को नए 'चांसरी कॉम्प्लेक्स' (भारतीय उच्चायोग परिसर) की आधारशिला रखी। इस अवसर पर सिंगापुर के विदेश मंत्री विवियन बालाकृष्णन भी मौजूद थे। जयशंकर गुरुवार से होने वाली चौथी भारत-सिंगापुर मंत्रिस्तरीय गोलमेज (आईएसएमआर) बैठक के लिए सिंगापुर में हैं। सिंगापुर की 2020 की जनगणना के अनुसार, देश की 40.4 लाख की आबादी में भारतीय मूल के लोगों की हिस्सेदारी 9 प्रतिशत है।

उदारीकरण से बिजली क्षेत्र को मिला आगे बढ़ने का करंट

पी वी नरसिंह राव सरकार द्वारा बिजली क्षेत्र में सुधारों को आर्थिक उदारीकरण का अहम हिस्सा बनाने के बाद इस क्षेत्र में कई बदलाव आए

नंदिनी केशरी
नई दिल्ली, 19 अगस्त

भारत में 1980 के दशक के उत्तरार्द्ध में महज आधे से कुछ अधिक हिस्से में बिजली की सुविधा मयस्सर हुआ करती थी और बाकी हिस्सों में रात होते ही घुप्प अंधेरा पसर जाता था। देश के कुछ बड़े राज्य अनुमानित जरूरत या खपत की तुलना में 20 से 38 फीसदी तक बिजली की कमी से जूझ रहे थे।

उस समय असल में बिजली आपूर्ति अधिनियम, 1948 के अंतर्गत गठित राज्य बिजली बोर्ड (एसईबी) के दौर में कई तरह की समस्याएं थीं। बिजली की किल्लत 9-10 फीसदी तक रहती थी, आपूर्ति भरोसेमंद नहीं थी और दिन में 12 घंटे तक बिजली नदारद रहती थी। सर्वाधिक जरूरत (पीक लोड) के समय बिजली की भारी कमी रहती थी और इस क्षेत्र से जुड़ी परियोजनाएं चार से पांच वर्षों की देरी के साथ चलती थीं।

इसके अलावा, ताप बिजली संयंत्रों में क्षमता का इस्तेमाल औसतन 50 प्रतिशत था और आपूर्ति की औसत लागत (एसीएस) और वसूली की औसत दर या एआरआर (जिसे एसीएस-एआरआर अंतर भी कहा जाता है) के बीच फासला बढ़ रहा था। ऊर्जा अर्थशास्त्री शुभेश सी भट्टाचार्य की 'जर्नल ऑफ क्लीनर प्रोडक्शन' में वर्ष 2006 में छपे एक अध्ययन के अनुसार 1,000 किलोवॉट-घंटा के लिए यह अंतर वर्ष 1974-75 में 37.3 रुपये से बढ़कर वर्ष 1985-86 में 151.6 रुपये हो गया था।

35 साल उदारीकरण के

पी वी नरसिंह राव सरकार द्वारा बिजली क्षेत्र में सुधारों को आर्थिक उदारीकरण का अहम हिस्सा बनाने के बाद इस क्षेत्र में कई बदलाव आए। स्वतंत्र बिजली उत्पादकों (आईआईपी) को बिजली उत्पादन के कारोबार में आने की इजाजत दी गई और उन्हें आकर्षक प्रोत्साहन भी दिए गए। यानी बेहतर क्षमता इस्तेमाल के लिए बोनस, पांच वर्षों के लिए कर छूट, कम पूंजी की जरूरत और चुनिंदा काउंटर-गारंटी व्यवस्था आदि की पेशकश की गई।

इस अध्ययन के मुताबिक शुरू में तो जबरदस्त दिलचस्पी दिखी और वर्ष 1995 तक 100 अरब डॉलर से अधिक निवेश से 75 गीगावॉट से अधिक नई उत्पादन क्षमता के लिए 189 परियोजना प्रस्ताव मिले। हालांकि, यह उत्साह अधिक समय तक नहीं रहा क्योंकि असल में कुछ ही परियोजनाएं पूरी हो पाईं।

अब उन सुधारों के 35 वर्षों बाद बिजली क्षेत्र के तीन हिस्सों में से एक बिजली उत्पादन की कुल स्थापित क्षमता रिकॉर्ड 500 गीगावॉट (जीडब्ल्यू)से अधिक हो गई है जबकि तीन दशक पहले यह केवल 100 गीगावॉट थी। लगभग हर जगह बिजली की सुविधा मयस्सर हो गई है और बिजली जाने की समस्या लगभग खत्म हो गई है, बस बुनियादी ढांचे की दिक्कतों की वजह से कहीं-कहीं ऐसा होता है। साथ ही, नवीकरणीय ऊर्जा के उत्पादन में भी तेज तरक्की हो रही है।

बिजली मंत्रालय के पूर्व सचिव और पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के पूर्व विशेष सचिव अनिल राजदान कहते हैं, 'आज हालात पूरी तरह बदल गए हैं। जब मैं इस क्षेत्र से जुड़ा था तब बिजली कटने की बहुत अधिक समस्या होती थी। ऐसा उस समय बनी कुछ गलत नीतियों की वजह से था।' यह एक अलग बात है कि इस सेक्टर के बाकी दो हिस्सों पारेषण और वितरण को अभी भी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। भले ही भारत का पारेषण नेटवर्क दुनिया के सबसे बड़े तंत्रों में से एक है मगर नवीकरणीय ऊर्जा की क्षमता में तेजी से हो रही बढ़ोतरी ग्रिड पर दबाव डाल रही है। इससे ग्रिड के लिए अलग-अलग मात्रा में मिलने वाली बिजली को संभालने और संतुलन बनाए रखने में चुनौती पेश आ रही है।

मुश्किल शुरुआत

भारत में सुधारों की शुरुआत उतार-चढ़ाव भरी रही। जब अमेरिका की बड़ी ऊर्जा कंपनी एनरॉन ने महाराष्ट्र के दाभोल में एक बिजली परियोजना शुरू की तो बहुत उम्मीदें थीं। मगर जल्द ही तरलीकृत प्राकृतिक गैस (एलएनजी) पर चलने वाला यह संयंत्र लागत, राजनीतिक विरोध और महाराष्ट्र एसईबी के साथ भुगतान विवादों के कारण विवादों में घिर गया। आखिरकार, यह परियोजना लटक गई और बिजली सुधारों के पहले चरण में आने वाली बाधाओं का प्रतीक बन गई।

इसके अलावा, कुछ ढांचागत कमियों पर ध्यान नहीं दिया गया। बिजली खरीदने की लागत बढ़ गई क्योंकि आईपीपी से मिलने वाली बिजली एनटीपीसी या एसईबी की तुलना में 1.5 से 2 गुना महंगी थी। साथ ही, आईपीपी के बिजली खरीद समझौते (पीपीए) करने में दिलचस्पी केवल बेहतर प्रदर्शन करने वाले एसईबी तक ही सीमित थी। राज्यों की खराब आर्थिक स्थिति, केंद्र से कम रकम मिलने और बिजली उत्पादन में उम्मीद के मुताबिक निजी निवेश नहीं होने के कारण जरूरी पूंजी उपलब्ध नहीं हो पाई। वर्ष 1992 और 1997 के बीच 30 जीडब्ल्यू के लक्ष्य के मुकाबले केवल 16 जीडब्ल्यू क्षमता तैयार हुई और अगले पांच वर्षों में 40 जीडब्ल्यू के लक्ष्य के मुकाबले केवल 19 जीडब्ल्यू क्षमता और जोड़ी गई। हालांकि, राज्य स्तर पर सुधार लाने के लिए ठोस प्रयास हुए। इनमें उत्पादन और वितरण के निजीकरण पर जोर देना और ऋण देने वाली एजेंसियों व केंद्र सरकार के सहयोग से वित्तीय और संगठनात्मक पुनर्गठन के प्रयोग शामिल थे। इनमें सबसे अहम थी वर्ष 1993 में घोषित विश्व बैंक बैंक की बिजली क्षेत्र को ऋण देने वाली नीति। यह नीति राज्य-स्तरीय उद्योग को अलग-अलग हिस्सों में बांटने, स्वतंत्र नियमन और पारदर्शी सब्सिडी प्रणाली के साथ लागत-आधारित शुल्क को बढ़ावा देती थी। ओडिशा पहला राज्य था जिसने अपने एसईबी को अलग-अलग हिस्सों में बांटा। इसके तहत दो उत्पादन कंपनियां (एक जल विद्युत के लिए और दूसरी ताप के लिए), एक पारेषण कंपनी (ट्रांसको) और चार बिजली वितरण कंपनियां (डिस्कॉम) बनाई गईं। वर्ष 1999 तक इसने अपने ताप बिजली स्टेशनों और सभी डिस्कॉम का निजीकरण कर दिया।

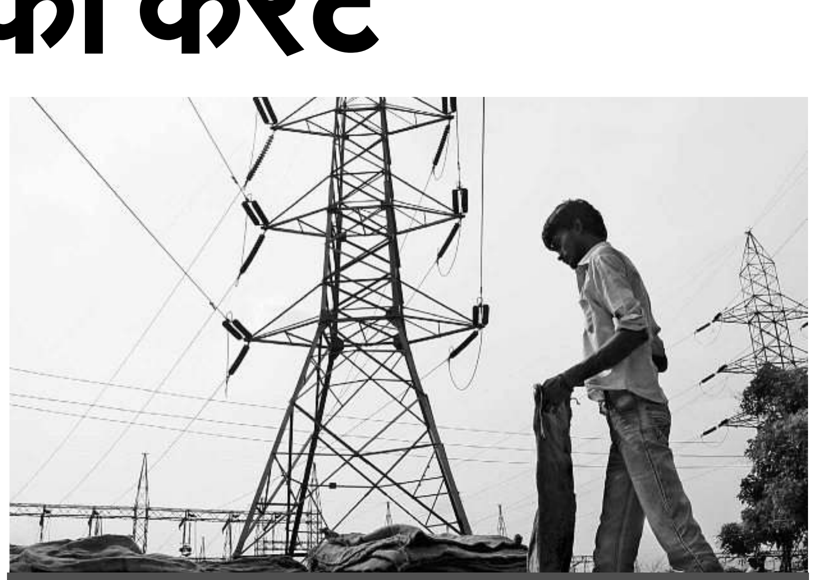

बिजली क्षेत्र में सुधार का सफर

- **1980 के दशक के अंत में: बिजली की सुविधा देश के आधे से कुछ अधिक हिस्सों में ही पहुंच पाई थी। कुछ बड़े राज्यों में अनुमानित जरूरत के मुकाबले 20 से 38 फीसदी बिजली की किल्लत थी।**
- **1991: स्वतंत्र बिजली उत्पादकों (आईआईपी) को बिजली उत्पादन कारोबार में आने की मिली इजाजत, उन्हें आकर्षक प्रोत्साहन दिए गए।**
- **1991 से 1995: 100 अरब डॉलर से अधिक निवेश के साथ 75 गीगावॉट (जीडब्ल्यू) से अधिक नई उत्पादन क्षमता के लिए 189 परियोजना प्रस्ताव मिले। मगर कुछ ही परियोजनाएं पूरी हो पाईं।**

इसके बावजूद डिस्कॉम दिवालिया ही रहीं और उनकी तकनीकी, व्यावसायिक या वित्तीय स्थिति में न के बराबर सुधार हुआ। दूसरी ओर ट्रांसको पर वितरण कारोबार के नुकसान का बोझ भी आ पड़ा और पूरी आपूर्ति व्यवस्था प्रभावित हुई। इसके अलावा, बिजली पहुंचाने के परियोजनाओं पर भी कम ध्यान दिया गया। भट्टाचार्य के अध्ययन के मुताबिक वर्ष1985 से वर्ष 1990 के बीच 1,00,000 गांवों में बिजली पहुंचाने की तुलना में वर्ष 1997 से वर्ष 2002 के दौरान बिजली से रूबरू होने वाले गांवों की संख्या घटकर 11,000 रह गई। उस समय के अधिकारियों ने इसे एक गंवाया हुआ मौका बताया। पूर्व बिजली सचिव (2002–07) एवं सलाहकार कंपनी एनर्जी इन्फ्राटेक के चेयरमैन आर वी शाही कहते हैं, 'बिजली आपूर्ति अधिनियम में संशोधन के जरिये किया गया छोटा सा बदलाव सुधार की एक आधी-अधूरी कोशिश थी। सरकार की तरफ से भुगतान गारंटी देने के वादे के बावजूद इसका कोई खास नतीजा नहीं निकला।'

अहम बदलाव

क्रिसिल इंटेलिजेंस के निदेशक सेहुल भट्ट कहते हैं, 'भारत के बिजली क्षेत्र को चार अहम कदमों से नया रूप दिया गया। इनमें बिजली अधिनियम, 2003 लागू किया जाना, खुली पहुंच, निजी (प्राइवेट) लाइसेंसिंग और एसईबी को अलग-अलग हिस्सों में बांटना शामिल थे।' इन कदमों से बिजली क्षेत्र से जुड़ी समस्याएं हल करने में आसानी हुई। इनके जरिये मौजूदा कानून एक साथ संगठित किए गए और एक नया ढांचा तैयार किया। इस अधिनियम के तहत खुली पहुंच ने योग्य ग्राहकों को अपनी स्थानीय बिजली वितरण कंपनियों के बजाय दूसरी कंपनियों से बिजली खरीदने की इजाजत मिल गई।

इसने नियामकीय ढांचे को आधुनिक बनाया, प्रतिस्पर्द्धा के लिए गुंजाइश बनाई और नियामक की भूमिकाएं स्पष्ट रूप से तय कर दीं। इसने कई वर्षों के लिए प्रोत्साहन शुल्क और पारदर्शी सब्सिडी प्रबंधन की भी अनुमति दी और साथ ही नियामकीय संस्थाओं के लिए स्पष्ट वित्तीय व्यवस्था का भी प्रावधान किया। इसके अलावा चोरी एवं भ्रष्टाचार रोकने के लिए कड़े दंड के प्रावधान हुए। अंत में लाइसेंस वाली गतिविधि के तौर पर बिजली कारोबार को बढ़ावा दिया गया और काम के बंटवारे और तंत्र तक पहुंच (नेटवर्क एक्सेस) के लिए आधार तैयार किया गया।

ऑल इंडिया डिस्कॉम्स एसोसिएशन के महानिदेशक एवं पूर्व बिजली सचिव (वर्ष 2021 से 2023) आलोक कुमार खुली पहुंच नीति (ओपन एक्सेस पॉलिसी) को सबसे बड़े सुधारों में से एक मानते हैं। वह कहते हैं, 'यह एक अहम बदलाव साबित हुआ क्योंकि इसने पारेषण और वितरण तंत्र तक बिना भेदभाव के पहुंच अनिवार्य बनाकर बिजली का एक प्रतिस्पर्द्धी बाजार तैयार किया।' कुमार कहते हैं कि इससे बिजली बनाने वाली कंपनियों को कई ग्राहकों और बाजारों तक पहुंचने का मौका मिला जिससे निजी निवेश की संभावना काफी बेहतर हुई। इसके बाद बिजली कारोबार शुरू हुआ और और एक्सचेंज भी अस्तित्व में आए। कुमार ने कहा, 'इसका नतीजा यह हुआ कि भारत की बिजली उत्पादन क्षमता का 50 फीसदी से अधिक हिस्सा अब निजी हाथों में है जिससे देश को वर्ष 1990 के दशक की शुरुआत में लगभग 20 फीसदी तक की किल्लत को पीछे छोड़कर अब लगभग शून्य यानी न के बराबर कमी तक का सफर पूरा करने में मदद मिली है।' इसके अलावा, एसईबी में विभाजन ने उत्पादन, पारेषण और वितरण को अलग-अलग संस्थाओं में बांटकर ढांचागत बदलाव को अंजाम दिया गया। इससे जवाबदेही बेहतर हुई और लागत, नुकसान और प्रदर्शन में सुधार साफ तौर पर दिखने लगा। हालांकि, अलग-अलग क्षेत्रों में इसका असर अलग-अलग रहा। भट्ट बताते हैं, 'उत्पादन और कारोबार में वितरण के मुकाबले तेजी से प्रगति हुई जबकि वितरण में सामाजिक बाधाएं, क्रॉस-सब्सिडी और सब्सिडी व भुगतान में देरी अभी भी पूरी तरह से खुदरा प्रतिस्पर्द्धा और वित्तीय सुधारों का पूरा लाभ नहीं लेने नहीं दे रही हैं।'

अधिशेष बिजली

वर्ष 2026 के आगाज तक भारत का बिजली क्षेत्र लगातार कमी झेलने की स्थिति से निकलकर बिजली अधिशेष की स्थिति में आ गया है। हालांकि, इस क्षेत्र की सबसे अहम बुनियाद बिजली वितरण अब भी इसकी सबसे कमजोर कड़ी बनी हुई है। कुमार कहते हैं, 'वर्ष 2013-14 और वर्ष 2020 के बीच बिजली क्षेत्र के दो मुख्य लक्ष्य थे बिजली उत्पादन की क्षमता बढ़ाना और सभी के लिए बिजली उपलब्ध कराना।'

कुमार कहते हैं कि हालांकि, इस मुद्दे पर अक्सर चर्चा हुई है मगर डिस्कॉम की वित्तीय स्थिरता पर उतना ध्यान नहीं दिया गया जितना दिया जाना चाहिए था। उन्होंने कहा, 'बिजली क्षेत्र में सुधार की प्रक्रिया उन लक्ष्यों को हासिल नहीं कर पाई है जिनकी उम्मीद थी मसलन कुल तकनीकी और व्यावसायिक (एटीऐंडसी) नुकसान कम कर 10 फीसदी से कम करना और एसीएस-एआरआर अंतर खत्म करना। हालांकि, काफी सुधार हुए हैं मगर हमें यह गति बनाए रखने और इसकी रफ्तार बढ़ाने की जरूरत है।' डिस्कॉम ने 3,300 करोड़ रुपये की पिछली बकाया रकम के साथ वित्त वर्ष 2025 में 15.04 फीसदी का एटीऐंडसी नुकसान और प्रति यूनिट 6 पैसे का एसीएस-एआरआर अंतर दर्ज किया। कुमार कहते हैं, 'सभी लोगों को बिजली उपलब्ध कराने का लक्ष्य काफी हद तक पूरा हो जाने और बिजली की कमी की समस्या भी काफी हद तक दूर होने के बाद अब ध्यान वितरण कंपनियों की वित्तीय स्थिति और कामकाज के तरीके बेहतर बनाने पर केंद्रित हो गया है।'

उन्होंने कहा कि पूर्व के कार्यक्रमों के विपरीत वर्ष 2021 में शुरू की गई 'पुनर्गठित वितरण क्षेत्र योजना' (आरडीएसएस) केंद्रीय अनुदान को आकलन करने योग्य सुधार के परिणामों से जोड़ती है। यह स्मार्ट मीटरिंग पर भी जोर देती है जिसका मकसद परिचालन क्षमता बेहतर बनाना, नुकसान कम करना और वित्तीय अनुशासन में सुधार करना है। केंद्र सरकार ने सुधार के लक्ष्यों को पूरा करने वाले राज्यों को उनके सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) का 0.5 फीसदी तक अतिरिक्त कर्ज लेने की इजाजत देकर सुधारों को बढ़ावा भी दिया है। कुमार कहते हैं, 'स्मार्ट मीटर के असरदार इस्तेमाल से, अगले तीन से चार वर्षों में एटीऐंडसी नुकसान एक अंक तक आ सकता है।'

नई चुनौतियां

ग्रिड पर नवीकरणीय ऊर्जा का दबदबा बढ़ने और आपूर्ति और मांग संतुलित करने के लिए बैट्री ऊर्जा भंडारण प्रणाली जैसी नई तकनीक अपनाए जाने के साथ नई चुनौतियां भी सामने आ रही हैं। राजदान कहते हैं, 'तकनीक बदल सकती है मगर ऊर्जा क्षेत्र के बुनियादी सिद्धांत वही रहते हैं। जो भी तकनीक अपनाई जाए, उसे पर्यावरण के लिहाज से अनुकूल एवं उत्तरदायी होना चाहिए और भरोसेमंद और लगातार आपूर्ति सुनिश्चित करनी चाहिए। नई तकनीक उपभोक्ताओं के लिए किफायती होनी चाहिए और सही व्यावसायिक सिद्धांतों पर काम करना चाहिए।'

बिजली क्षेत्र में सुधार के अगले चरण में सरकार को अपनी ऊर्जा की खपत की तीव्रता को कम करने के लिए ग्रिड में नवीकरणीय ऊर्जा का जुड़ाव बढ़ाना होगा। सौर और पवन ऊर्जा के अलावा पारंपरिक स्रोतों के साथ भी अपनी समस्याएं हैं। राजदान कहते हैं, 'नई चिंताएं सामने आ रही हैं। उदाहरण के लिए बारिश का बदलता प्रारूप एक चेतावनी का संकेत हैं। क्या सिंचाई और जलविद्युत स्टेशनों के लिए पर्याप्त पानी उपलब्ध होगा?' आने वाले समय में बिजली क्षेत्र की मजबूती वितरण दुरुस्त करने के साथ ग्रिड में लचीलापन बढ़ाने पर जोर देना होगा। हमें यह भी सुनिश्चित करना होगा कि ऊर्जा के नए स्रोतों की तरफ बढ़ाए जाने वाले कदम भरोसेमंद, किफायती और टिकाऊ हों।

शेयर बाजार

खबरों में

■ जैगल प्रीपेड ओशन सर्विसेज

Top gainer amongst A-group of companies

₹ 165.9 PREVIOUS CLOSE
₹ 186.0 CLOSE
▲ 12.1% UP

■ एसकेएफ इंडिया इंडस्ट्रियल

Trading volume surged 120 times over 2-week average on BSE

₹ 2,660.9 PREVIOUS CLOSE
₹ 2,800.1 CLOSE
▲ 5.2% UP

■ आरआर केबल

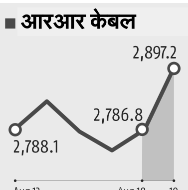

Hits new all time high on BSE at ₹2,919

₹ 2,786.8 PREVIOUS CLOSE
₹ 2,897.2 CLOSE
▲ 4.0% UP

*OVER PREVIOUS CLOSE

आज का अहम शेयर

■ वेलस्पन कॉर्प

Hits new all-time high at ₹1,984; Surged 152 per cent in last 6 months

निफ्टी 50

Company	Close (₹) 19 Aug '26	% Chg	Wt (%)	PE Con	PE Std	Company	Close (₹) 19 Aug '26	% Chg	Wt (%)	PE Con	PE Std
Adani Enter	2990.3	-0.4	0.9	157.2	121.7	JSW Steel	1285.8	1.4	1.5	32.1	41.7
Adani Ports	1681.9	0.0	1.1	29.2	140.3	Kotak Mah Bank	390.3	0.7	2.5	19.4	26.1
Apollo Hosp	8750.0	-0.8	0.8	59.8	79.6	L & T	4041.3	-0.6	4.8	31.2	41.4
Asian Paints	2630.8	0.1	1.0	51.7	53.2	Mah & Mah	3415.0	-0.2	3.0	22.1	26.0
Axis Bank	1235.0	-0.6	3.1	13.8	14.9	Maruti Suzuki	13690.0	0.0	1.5	30.0	30.7
Bajaj Auto	11645.0	0.3	1.2	27.1	29.8	Max Health	997.0	-1.7	0.6	64.8	132.8
Bajaj Fin	1080.2	-1.3	2.6	32.8	37.0	Nestle India	1465.0	0.2	0.9	76.2	75.2
Bajaj Finsrv	2012.0	0.0	1.2	31.0	145.3	NTPC	336.6	-0.2	1.4	11.8	13.8
Bharat Elctn	409.2	-0.7	1.3	48.7	48.8	ONGC	238.0	-0.6	1.1	6.8	7.1
Bharti Airtel	1922.0	-0.6	5.2	37.7	69.6	Power Grid	263.5	-1.7	1.0	15.4	15.6
Cipla	1422.0	-0.6	0.7	32.1	35.0	Reliance Ind	1311.0	-0.8	7.7	23.7	45.2
Coal India	400.0	-1.7	0.8	7.9	13.0	SBI	1048.6	-0.4	3.8	11.5	12.3
Dr Reddys	1170.0	-0.7	0.6	30.3	147.2	SBI Life Ins	1780.4	0.1	0.7	-	68.7
Eicher Motor	7990.5	-0.3	1.0	37.7	41.5	Shriram Finance	1106.0	-0.2	1.8	23.0	23.1
Eternal	320.0	1.3	2.7	711.1	117.2	Sun Pharma	1900.0	1.3	1.8	36.1	143.2
Grasim Ind	3270.0	-0.3	1.1	38.0	264.1	Tata Consumer P	1068.0	0.6	0.6	64.1	64.1
HCL Techno	1324.8	2.1	1.2	19.8	19.8	Tata Motors PV	321.3	-0.5	0.6	129.6	187.9
HDFC Bank	720.0	-0.4	9.6	14.0	14.7	Tata Steel	184.0	-0.8	1.3	19.4	12.8
HDFC Std Life	536.3	-0.4	0.5	59.0	59.0	TCS	2289.0	0.4	2.0	15.4	15.4
Hindalco	1039.0	-0.3	1.3	11.2	18.0	Tech Mahindra	1589.8	-0.1	0.9	29.3	39.0
HUL	2020.7	-0.7	1.6	43.1	43.9	Titan Company	5068.0	0.4	1.8	77.1	83.9
ICICI Bank	1402.0	-0.7	8.7	17.9	19.3	Trent	2953.0	0.4	0.9	86.1	75.1
Infosys	1119.8	0.4	3.4	14.6	14.6	UltraTech	11450.0	-0.4	1.2	39.1	44.1
InterGlobe Avia	5193.0	-0.5	1.0	-	-	Wipro	179.6	0.8	0.4	13.4	15.7
ITC	267.1	-1.1	2.9	16.9	17.5	Nifty 50	24078.3	↓-0.3	100.0	21.9	26.3
Jio Financial	243.2	-1.1	0.7	77.7	225.1						

एसऐंडपी बीएसई सेंसेक्स स्टॉक

Adani Ports	1679.5	-0.1	1.4	29.1	140.1	L & T	4030.1	-1.3	5.8	31.1	41.3
Asian Paints	2619.2	-0.4	1.3	51.5	53.0	Mah & Mah	3412.3	-0.1	3.7	22.0	26.0
Axis Bank	1232.4	-0.7	3.7	13.8	14.9	Maruti Suzuki	13688.2	-0.2	1.9	30.0	30.7
Bajaj Fin	1078.6	-1.3	3.2	32.8	36.9	NTPC	334.8	-0.7	1.7	11.7	13.7
Bajaj Finsrv	2010.0	0.0	1.4	30.9	145.1	Power Grid	262.5	-2.0	1.3	15.4	15.6
Bharat Elctn	408.7	-0.8	1.5	48.6	48.8	Reliance Ind	1307.5	-0.9	9.4	23.7	45.1
Bharti Airtel	1925.0	-0.5	6.3	37.7	69.7	SBI	1046.0	-0.7	4.6	11.5	12.3
Eternal	320.2	1.3	3.3	711.6	117.3	Sun Pharma	1898.0	1.2	2.2	36.0	143.0
HCL Techno	1322.5	1.7	1.5	19.8	19.7	Tata Steel	184.0	-0.6	1.6	19.4	12.8
HDFC Bank	720.2	-0.4	11.7	14.0	14.7	TCS	2287.0	0.3	2.5	15.4	15.4
HUL	2016.0	-1.0	1.9	43.0	43.8	Tech Mahindra	1582.2	-0.6	1.1	29.1	38.8
ICICI Bank	1401.8	-0.7	10.6	17.9	19.3	Titan Company	5064.0	0.3	2.2	77.0	83.8
Infosys	1117.1	0.2	4.2	14.5	14.6	Trent	2944.0	0.0	1.0	85.9	74.9
InterGlobe Avia	5175.0	-0.8	1.2	-	-	UltraTech	11460.0	-0.3	1.4	39.2	44.2
ITC	266.9	-1.2	3.5	16.9	17.5	BSE SENSEX	76909.7	↓-0.4	100.0	21.7	25.6
Kotak Mah Bank	392.1	1.2	3.0	19.5	26.3						

C = Consolidated; S = Standalone

वैश्विक सूचकांक

Indices	Close	% Chg*	Indices	Close	% Chg*
Americas (Aug 18,26)			**Asia/Pacific (Aug 19,26)**		
Dow Jones	53343.4	-0.2	Kuala Lumpur Comp	1731.3	-0.1
S&P/ TSX Composite	36367.9	-0.8	Straits Times	5694.2	-0.1
Nasdaq Composite	26289.7	-1.3	Stock Exchange of Thai	1609.8	-0.7
Europe/Africa (Aug 18,26)			Jakarta Composite	6394.1	-0.9
CAC 40	8532.7	0.3	Taiwan Taiex	44719.4	-1.3
DAX	26094.6	-0.1	Shanghai Se Comp	3894.4	-2.4
FTSE 100	10706.5	-0.2	Kospi	6471.2	-5.8
IBEX 35	19885.6	-0.3	**Volatility (Aug 18,26)**		
Asia/Pacific (Aug 19,26)			CBOE Dow Jones	13.6	2.5
Hang Seng	25495.1	0.1	CBOE S&P 500	15.9	0.1
Nikkei 225	65326.4	-3.2			

* Change over previous close

प्रमुख सूचकांक

	Previous Close	Open	High	Low	Close	Change	% chng
BSE Sensex	77,235.5	77,218.1	77,347.8	76,822.9	76,909.7	-325.8	-0.4
BSE Sensex 50	25,381.7	25,358.6	25,403.2	25,244.7	25,276.1	-105.6	-0.4
BSE-100	25,926.1	25,902.4	25,941.5	25,798.7	25,829.8	-96.3	-0.4
BSE-200	11,384.3	11,377.1	11,390.7	11,323.9	11,336.3	-48.0	-0.4
BSE-500	36,749.2	36,740.8	36,776.9	36,549.2	36,577.2	-172.1	-0.5
BSE IPO	18,159.0	18,200.4	18,262.3	18,101.9	18,238.1	79.1	0.4
Dollex-30	6,627.6	-	-	-	6,593.9	-33.6	-0.5
Nifty 50	24,154.9	24,152.1	24,172.9	24,025.7	24,078.3	-76.6	-0.3
Nifty Next50	74,308.9	74,264.6	74,280.1	73,752.1	73,900.7	-408.3	-0.5
Nifty 500	23,472.4	23,475.4	23,488.3	23,348.3	23,386.2	-86.2	-0.4
India VIX	11.4	11.4	11.7	10.1	11.3	-0.1	-0.6
Nifty CPSE	6,466.1	6,469.3	6,473.4	6,383.0	6,405.2	-60.9	-0.9

बढ़े/घटे

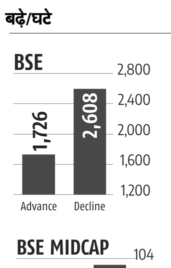

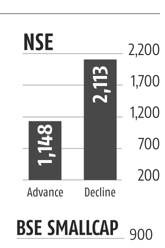

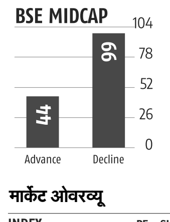

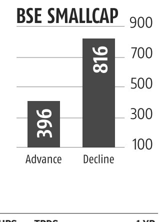

मार्केट ओवरव्यू

INDEX AGGREGATES	PE C/S	SHRS MN	TRDS '000	ADV	DEC	1 YR RETURN
SENSEX	21.7/25.6	10.1	254	8	22	-5.8
NIFTY 50	21.9/26.3	238.7	4121	16	34	-3.6

C = CONSOLIDATED; S = STANDALONE

TURNOVER	CASH BSE	CASH NSE	DERIVATIVES BSE	DERIVATIVES NSE
VALUE(IN ₹ CRORE)	9310	110068	16577321	7954870
SHARES(IN MN)	552.9	4283.5	351	14945.3
TRADES(000)	3766	34780	-	26449

MARKET-CAP (₹ CR)	TRADED	TOTAL
BSE	48,833,051	49,146,036
NSE	48,702,204	48,943,844
DERIVATIVES	34,172,312	34,172,312

कारोबारी गतिविधि

(₹ crore)	FIIs Equity Net	FIIs Debt Net	MF Equity Net	MF Debt Net
On 18 Aug	2926	-199	-	-
On 17 Aug	-339	95	-	-
On 14 Aug	4112	-728	-	-
On 13 Aug	351	-1523	4572	5954
On 12 Aug	-1006	-541	4792	-6975
Aug till date	21969	-277	30357	-35384
2026 till date	-226256	63320	344466	-566847

डेरिवेटिव में एफआईआई

(₹crore)	Index NET	Stock Net	Index Fut OI	Index Opt OI	Stock OI
On 18 Aug	-26192	-2894	0.2	2.4	7.8
On 17 Aug	7637	-282	0.2	3.0	7.7
On 14 Aug	4273	-706	0.2	2.8	7.7
On 13 Aug	-14108	-42	0.2	2.6	7.6
On 12 Aug	-4154	742	0.2	2.4	7.5
Aug till date	-44639	-8344	-	-	-
2026 till date	-726599	-80541	-	-	-

OI in number of contracts(million)

एसऐंडपी बीएसई सेक्टर सूचकांक

	Prev cls	Close	% Chng
Auto	64,560.9	64,440.5	-0.2
Bankex	64,884.3	64,793.5	-0.1
Cons. Durables	64,880.9	64,854.3	0.0
Cap. Goods	80,368.8	79,087.3	-1.6
FMCG	18,027.4	17,917.5	-0.6
Healthcare	50,813.8	50,591.5	-0.4
Infra	575.8	571.2	-0.8
IT	29,105.7	29,184.2	0.3
Metal	41,779.5	41,597.5	-0.4
Oil & Gas	26,238.4	26,122.4	-0.4
Power	7,599.8	7,471.7	-1.7
PSU	20,829.7	20,656.5	-0.8
Realty	7,003.4	6,964.4	-0.6

एफऐंडओ स्नैपशॉट

MOST BULLISH	Futures price	Cash price	Premium (%)	MOST BEARISH	Futures price	Cash price	Discount (%)
Manapp Finance	343.5	340.0	1.0	LIC Hsg Fin	489.4	497.0	-1.5
Page Inds	35525.0	35240.0	0.8	Ruchi Soya	347.3	351.0	-1.0
Varun Bever	435.0	431.9	0.7	Havells I	1274.8	1287.0	-0.9
SBI Card & Pay	628.2	623.7	0.7	Tube Inv of Ind	2935.9	2961.0	-0.8
IEX	123.9	123.0	0.7	Bajaj Holding	11291.0	11380.0	-0.8

	BSE Index	BSE Stock	NSE Index	NSE Stock
FUTURE				
Contracts	1310	4	79325	1544348
Open Int.(000)	3	0	20847	18451483
Shares(In Mn)	0	0	4.7	2913.8
Value(₹ crore)	203	0	12820	103968
OPTIONS				
Contracts	107269453	5	45135980	8898321
Open Int.(000)	4132	0	539652	10441392
Shares(In Mn)	35	0	2805.1	9221.8
Value(₹ crore)	16577117	0	7194949	643133

पुट कॉल रेशियो

(Open Interest in Mn)	Put	Call	PC Ratio
Market	4136.8	6844.3	0.6

Top 5	PC Ratio	Bottom 5	PC Ratio
Bajaj Auto	1.2	Page Inds	0.3
Bosch	1.1	Premier Energie	0.3
NIIT Techno	1.1	Vishal Mega	0.3
Hyundai Motor	1.0	ONGC	0.4
Samvardhana M	1.0	GAIL	0.4

एक्टिव कॉल

(In Million)	Expiry Date	Strike Price	Traded Qty	Open Interest	% Chg (OI)
Index					
Nifty	25/08/26	24100	160.1	9.9	410.5
Nifty	25/08/26	24200	113.3	11.2	61.1
Nifty	25/08/26	24050	82.3	3.2	2844.7
Nifty	25/08/26	24150	81.8	3.4	348.0
Nifty	25/08/26	24300	74.4	11.7	46.2
Stock					
Vodafone Idea	25/08/26	15	550.8	355.3	6.3
Vodafone Idea	25/08/26	14	371.5	319.7	-8.8
Vodafone Idea	25/08/26	16	147.0	110.6	4.2
YES Bank	25/08/26	23	102.2	80.8	-11.4
Vodafone Idea	29/09/26	15	78.1	151.5	14.9

एक्टिव पुट

(In Million)	Expiry Date	Strike Price	Traded Qty	Open Interest	% Chg (OI)
Index					
Nifty	25/08/26	24100	194.7	6.8	87.5
Nifty	25/08/26	24000	163.1	14.0	22.1
Nifty	25/08/26	24050	142.2	3.0	267.6
Nifty	25/08/26	24150	80.9	1.9	54.0
Nifty	25/08/26	24200	77.4	6.5	-4.1
Stock					
Vodafone Idea	25/08/26	14	190.3	221.2	2.2
Vodafone Idea	25/08/26	13	102.9	223.6	-0.5
YES Bank	25/08/26	23	44.6	63.5	-16.9
YES Bank	25/08/26	22	39.4	35.6	-6.4
Vodafone Idea	25/08/26	15	37.7	56.5	-18.1

वॉल्यूम में तेजी

Company	Days Volume	2-week Avg Volume	Change %	Close price	*Price %chg
Oriental Htl	50723223.0	287100.2	17567.4	139.2	14.6
Excel Ind	1089126.0	9949.8	10846.2	1129.3	15.0
Aster DM Health	79797775.0	1150735.2	6834.5	800.7	-2.1
H G Infra Engg	5080671.0	93145.6	5354.5	518.7	2.2
Kamanwl Hsg	528159.0	13954.2	3684.9	18.4	3.7
RailTel Corp	13008334.0	377908.6	3342.2	286.9	3.5
D-Link India	2645526.0	97987.5	2599.9	446.4	6.6
Nilkamal	1553860.0	64457.3	2310.7	2030.7	10.9
Laxmi Cotspin	357640.0	15659.6	2183.8	14.9	10.6
Mahickra Chemic	113250.0	5550.0	1940.5	259.6	-11.7

52 सप्ताहों का उच्चतम और निम्नतम

Company	Price	Company	Price	Company	Price	Company	Price
HIGH		Sundram Fast	1250.4	**LOW**		*Brainbees Solut	195.0
BS 200		Super Sales	1230.0	BS 200		Star Cement	193.6
*Bosch	49130.0	Action Const	1195.8	*HUL	2008.5	*Crizac Ltd	171.0
*Radico Khatn	4748.0	*Liquidadd	1140.9	*HDFC Bank	715.1	*Greenpanel Inds	160.0
PNB Hou Fin	1175.5	*Liquid ETF	1117.9	UPL	558.0	*Thirumala Ch	143.8
*HFCL	234.7	*Liquidbetf	1095.2	*Dabur India	398.1	*National Std	128.5
*Samvardhana Mot	173.3	*HDFC Liquid	1074.3	*ITC	265.9	RRECL	125.3
Others		*Kalyani Cast-Te	936.9	*IRFC	85.0	Kitex Garmnt	124.0
*Keltech Enrgy	14403.6	Sundaram Brk	908.0	Others		*Uravi Defence	100.8
*Craftsman Auto	10995.7	*SG Mart	817.0	*Proct & Gamb	8232.1	*SKCIL	98.0
Tasty Bite	10550.0	*Khazanchi Jewel	805.0	Astrazen Ph	7490.0	*Duroply In	97.0
GSK Pharma	3051.0	Ramkrshn Frg	772.4	*IndiaMART Int	1730.0	Ace Engitech	95.0
*R R Kabel	2919.0	Avadh Sugar	762.6	*Whirlpool	750.1	*AB Life Brand	86.8
*Happy Forgings	2330.0	*Exato Tech	711.0	*Aurionpro Sl	681.0	*Sai Silks	84.6
*Avalon Technol	2266.4	*M M Forgings	690.1	Medplus Health	648.1	*Adcounty Media	76.0
*Nilkamal	2105.0	Hind.Foods	678.1	*Symphony	600.3	*Xelpmoc Des	76.0
Zen Techno	2041.9	Coral Lab	665.2	Vesuvius	430.1	*10Ard	75.3
*Welspun Corp	1983.9	*J G Chemicals	660.0	*KEC Intl	422.1	*Himatsing S	69.5
*Rubicon Res	1827.5	*Axisol	654.7	*Shanthi Gear	386.0	Indo Thai Secur	66.1
*RPEL	1659.0	*Man Ind	651.0	CSB Bank	314.0	*Shalibhdra F	66.0
*Ador We	1644.0	*Lenskart	645.1	*KPI Green Energ	302.0	Vega Jeweller	62.0
*KRN Heat Exchan	1599.2	Dolphin Off.	644.0	*Nitin Castings	285.6	*First Custod	54.6
*Paras Defence	1577.7	Elgi Equip	640.5	*Innovision	266.0	*Artefct Prjt	49.7
*Senores Pharmac	1576.0	Uflex	634.8	*KP Green Engine	254.0	VTM	45.1
*Chennai Petr	1489.0	*Nitin Spn	617.0	*CMS Info System	240.5	NMS Resources	43.1
*Inv & Prec	1309.9	*Dhabriya Poly	593.3	*City Puls Mult	218.3	Paos Inds	42.4
*Creative N	1282.8	Apollo Pipes	588.5	*Suraj Ltd	202.0	Mangal Compusol	41.0

* Indicates that the market price of these companies reached two-year highs/lows.

दिन में सबसे ज्यादा चढ़े

Company	Day's high	Close	% chg*	3mth high	52 wk high
Kaynes T	3825.0	3811.0	4.4	3963.5	7705.0
Cyient	902.8	895.0	4.3	933.5	1282.4
PNB Hou Fin	1175.5	1175.5	3.0	1175.5	1175.5
Coforge	1822.0	1815.0	2.6	1835.5	1988.9
Dixon Tech	14544.7	14495.0	2.5	14680.0	18471.5
Sammaan Capita	158.5	153.7	2.5	192.4	192.9
PAYTM	1605.0	1585.2	2.5	1656.0	1656.0
Indraprst Gs	158.0	153.1	2.4	175.6	223.6
Nykaa	329.0	327.5	2.0	348.3	348.3
Dalmia Bharat	1875.0	1875.0	1.9	1887.6	2496.0
Policy Bazar	1798.6	1780.0	1.8	1844.9	1963.0
SBI Card & Pay	626.8	626.3	1.7	674.1	965.0
HCL Techno	1323.8	1322.5	1.7	1379.8	1770.0
UPL	570.1	568.7	1.5	661.3	812.0
Eternal	322.9	320.2	1.3	325.0	368.4

दिन में सबसे ज्यादा गिरे

Company	Day's low	Close	% chg*	3mth low	52 wk low
Netweb Technolo	5024.0	5062.2	-5.5	3672.6	2037.7
Hitachi Energy	33400.0	33550.0	-4.7	30416.9	16104.0
Himadri Sp Chem	702.0	750.3	-4.0	555.6	420.0
Adani Energy So	1537.6	1540.0	-3.8	1308.1	745.5
CG Power	860.2	862.9	-3.5	812.6	525.5
Tata Techno	801.1	809.9	-3.2	656.6	507.5
MTAR techno	6900.0	6916.5	-3.1	5183.1	1391.0
L&T Finan	312.9	315.0	-3.0	256.3	214.6
Page Inds	35370.0	35400.0	-3.0	35370.0	29800.0
Bharat Dyn	1347.0	1349.0	-2.9	1156.0	1090.0
Voltas	1217.7	1221.5	-2.5	1204.0	1187.5
Glenmark	2224.0	2255.0	-2.3	2109.0	1794.0
MCX	2960.6	2973.0	-2.1	2565.6	1461.0
Cummins (I)	5206.1	5240.0	-2.1	5171.0	3735.2
ABB India	7390.0	7400.0	-2.1	6264.6	4640.5

* Ranked on the basis of percentage gain/loss on previous close

सबसे ज्यादा कारोबार

	Value BSE+NSE (₹ crore)	Volume BSE+NSE (Mn shrs)
Aster DM Health	6177.3	79.8
Shiprocket	3386.9	241.1
Dhoot Transmiss	2666.2	19.4
Himadri Sp Chem	2522.2	34.2
Behari Lal Eng	2030.9	40.6
HDFC Bank	1629.9	22.7
BSE	1598.7	4.8
ICICI Bank	1503.8	10.8
Bharti Airtel	1275.9	6.6
Cupid Ltd	1078.4	38.0
Netweb Technolo	1076.8	2.1
Reliance Ind	1058.4	8.1
MCX	1011.0	3.4
Infosys	988.0	8.8
PAYTM	947.4	6.0
Eternal	941.4	29.4
Chennai Petr	887.5	6.1
SBI	830.9	7.9
TCS	809.1	3.6
Kaynes T	782.8	2.1
Zaggle	774.3	41.8
Molbio Diagnost	739.5	6.8
Dixon Tech	716.1	0.5
Oriental Htl	700.5	50.7
Hitachi Energy	666.7	0.2

प्रमुख एम-कैप

Rank	Company	Mcap (₹ cr)
1	Reliance Ind	1769379.6
2	Bharti Airtel	1201207.7
3	HDFC Bank	1109830.4
4	ICICI Bank	1005987.8
5	SBI	965520.8
6	TCS	827459.5
7	Bajaj Fin	671536.4
8	L & T	554481.3
9	LIC India	522445.0
10	HUL	473679.4
11↑	Sun Pharma	455387.1
12↓	Infosys	453305.6
13	Titan Company	449581.9
14	Maruti Suzuki	430357.0
15	Mah & Mah	424326.3
16	Adani Enter	403177.9
17	Adani Power	392829.3
18↑	Kotak Mah Bank	389987.8
19↓	Adani Ports	386948.4
20↓	Axis Bank	383605.9
21	HCL Techno	358880.2
22↑	UltraTech	337703.3
23↓	HAL	335058.8
24	ITC	334420.4
25	NTPC	324596.0
26	Bajaj Finsrv	322022.1
27	Bajaj Auto	321516.0
28	JSW Steel	313341.9
29	Eternal	309005.8
30	ONGC	299410.7

रुझान

Company	% change	Company	% change
BS200		Ovobel Foods	40.6
DOWN 7 DAYS		**DOWN 7 DAYS**	
Ambuja Cem	-5.8	Nitin Castings	-32.1
Maruti Suzuki	-2.9	Onix Solar	-30.1
Coal India	-2.7	City Puls Mult	-30.1
UP 3 DAYS		Surbhi Inds	-30.1
Torrent Phar	3.6	RSD Fin	-30.1
Uno Minda	2.8	National Std	-30.1
Petronet LNG	2.0	Indo Thai Secur	-30.0
Info Edge	2.0	**UP 3 DAYS**	
Federal Bank	1.8	Grovy India	35.2
Supreme Ind	1.7	Osiajee Texfab	34.3
HDFC AMC	1.5	Advance Techno	33.1
DOWN		11Qpr	32.9
Voltas	-7.8	Siel	32.9
Tata Techno	-6.6	TPI India	32.4
Hitachi Energy	-6.0	Mysore Petro	30.2
Mphasis	-5.8	**DOWN 3 DAYS**	
Colgate	-5.3	Utcrfs2Dgr	-27.1
LTM	-4.1	Star Delta Tran	-20.1
Adani Green En	-4.1	Centuple Global	-19.8
Others		Ahluwalia Co	-16.8
UP 7 DAYS		S&S Power Sw	-15.7
Recode Studi	45.1	Kotyark Inds	-14.3
Taaza Int	40.7	Covance	-14.3
Axisol	40.7		
Maxgrow	40.7		
LE Lavoir	40.6		
Kuber Udyog	40.6		

बोर्ड बैठक

Group Company Purpose

AUGUST 20

Abhinav Leas: Meeting of the Board of Directors of the Company

AJEL: Unaudited Standalone and Consolidated Financial Results

Arihant Cap: To consider and approve:- Appointment of Chief Financial Officer (Key Managerial Personnel) and Other incidental and ancillary matters

Bonlon Inds: For deciding Issue Price and other terms of the Rights Issue

Dalal Street: To consider and approve and announce the date of AGM and Annual Report related topics.

Expo Engineer: To consider and approve Conversion of warrants into the equity shares of the Company subject to depositing the balance outstanding amount for conversion of warrants into the equity shares of the Company

K&R Rail Eng: To consider and approve 1. Induction of New Directors in the Company 2. Any other business with the permission of the Chair.

Key Corp: Raising of funds by way of Rights issue of Equity Shares.

Kizi Apparels: To consider and approve Approval of Notice for Annual General Meeting Annual Report and Other Business Matters.

Manipal Health: To consider and approve the unaudited financial results (both Standalone and Consolidated) of the Company for the quarter ended June 30 2026.

Omega Intera: To consider and approve a proposal for raising funds of up to by way of issuance of equity shares

Raconteur Globa: Meeting of the Board of Directors of the Company

Ratnaveer: To consider and approve to fix the brief term of Rights Issue including Equity shares to be offered through the issue

Rubfila Int: To consider and approve :- i) convene the 33rd Annual General Meeting of the Company and to approve the Notice, Directors Report etc. ii) consider the Valuation Report on the wholly-owned subsidiary of the company, M/s.Premier Tissues India Ltd.

S.I.Capital: To consider seeking approval from the Shareholders of the Company for the issuance of Non-Convertible Debentures in the ensuing Annual General Meeting.

Spel Semi: To consider and approve unaudited standalone financial results of the Company for the Quarter ended Jun 30 2026.

Std.Surfact.: To consider and adopt Unaudited Quarter Results (Q1) of period ending 30.06.2026.

STEELMAN TEL: Meeting of the Board of Directors of the Company

Uma Exports: To consider issue of Warrants and Increase in Authorized Share Capital of the Company.

इंट्रा-डे

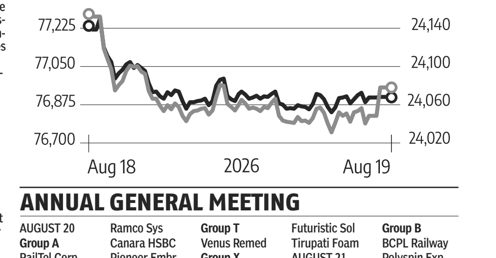

ANNUAL GENERAL MEETING

AUGUST 20
Group A
RailTel Corp
Ramco Cements
Restaurant Bran
Usha Martin
Eicher Motor
InterGlobe Avia
South Ind Bk
Prestige Est
Sagility
Welspun Ent
Varroc Eng
Group B
Ramco Sys
Canara HSBC
Pioneer Embr
Dhunseri Inv
Ramco Ind
Century Enka
Indus & Prud
Antony Waste
Sumedha Fisc
Group M
Khyati Global
Group MT
Cryogenic Ogs
Glen
Group T
Venus Remed
Group X
Integra Capital
E-Land App
Ditco
RDB Rasayans
Shivagrico
Link Pharma
Sovereign D
Kesar Enter
Golkunda Dmd
Metal Coat
Maris Spin
Futuristic Sol
Tirupati Foam
AUGUST 21
Group A
ICICI Bank
Federal Bank
Grasim Ind
VIP Ind
CSB Bank
Tourism Fin
SML Mahindra
Lloyds Engineer
Minda Corporati
KEC Intl
Group B
BCPL Railway
Polyspin Exp
Kanco Tea
Neogen Chem
Mangalam Cem
LG Electronics
Group M
Bondada
Group MT
Jonjua Overseas
Astonea Labs
Group T
Alkali Met

SPECIALITY RESTAURANTS LIMITED

Corporate Identification No. (CIN) – L55101WB1999PLC090672 **Registered Office:** "Uniworth House" 3 A, Gurusaday Road, Kolkata - 700019
Tel. No.: (91 33) 2283 7964 E-mail: corporate@speciality.co.in Website: www.speciality.co.in

NOTICE OF THE 27th ANNUAL GENERAL MEETING AND E-VOTING INFORMATION

Notice is hereby given that:

1. The 27th Annual General Meeting (**"AGM"**) of the Members of **Speciality Restaurants Limited** ("**Company**") will be held on **Friday, September 11, 2026 at 4.00 p.m.** (IST) through Video Conferencing (VC) or Other Audio Visual Means (OAVM) to transact the business, set out in the Notice convening the AGM in compliance with the applicable provisions of the Companies Act, 2013 (the "**Companies Act**") and the rules made thereunder, read with Ministry of Corporate Affairs (MCA) General Circular No. 14/2020 dated April 8, 2020, No. 17/2020 dated April 13, 2020, No. 20/2020 dated May 5, 2020, and subsequent circulars issued in this regard, the latest being 03/2025 dated September 22, 2025 (collectively referred to as MCA Circulars) has permitted the holding of the AGM through VC or OAVM without the physical presence of the Members at a common venue.

   The Company has sent the Notice of the AGM along with the link of the Annual Report for financial year 2025-26 through electronic mode only, to those Members whose e-mail addresses are registered with the Registrar/Share Transfer Agent of the Company, MUFG Intime India Private Limited and Depositories. Further, in accordance with Regulation 36(1)(b) of the **SEBI** (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (**"Listing Regulations"**), the Company has sent letters to the Members, whose e-mail address are not registered with the Company/Registrar and Share Transfer Agent/Depository Participants providing the weblink from where the Annual Report for the Financial Year 2025-26 can be accessed on the Company Website. The electronic dispatch of Annual Report to Members have been completed on August 18, 2026. The requirement of sending physical copies of the Annual Report has been dispensed with vide relevant circulars. However, the physical copies of the Annual Report for the Financial Year 2025-26 shall be sent to those Members who request the same at investor@speciality.co.in mentioning their Folio No. / DP ID and Client ID. The Annual Report of the Company, inter-alia containing the Notice of the AGM can be accessed and downloaded from the website of the Company at www.speciality.co.in and also on the website of National Securities Depository Limited (NSDL) at www.evoting.nsdl.com. A copy of the same is also available on the website of Stock Exchanges on which the securities of the Company are listed, i.e. BSE Limited and National Stock Exchange of India Limited at www.bseindia.com and www.nseindia.com, respectively. The venue of the Meeting shall be deemed to be Registered Office of the Company.

2. The Board of Directors at its meeting held on May 19, 2026, has recommended a dividend of Rs. 1.00 per equity share of Rs. 10/- each for the Financial Year ended March 31, 2026. The dividend, if declared at the ensuing AGM, will be paid, subject to deduction of tax at source ('TDS'), on or after Monday, September 14, 2026. The Company has fixed Friday, September 4, 2026, as the Record Date for determining entitlement of Members to dividend for FY 2025-26, if declared at the ensuing AGM. The dividend will be paid through various online transfer modes to the Members who have updated their bank account details.

   The Company, vide its email communication dated July 24, 2026, to all the Members, having their email ID's registered with the Company/Depositories, has explained the process of withholding tax from dividends paid to the shareholders at prescribed rates along with the necessary annexures. This communication is also available on the website of the Company at www.speciality.co.in.

   Members are requested to register e-mail address with their concerned DP's, in respect of shares held with Depositories and with RTA in respect of shares held in physical form, by submitting the Form ISR-1 duly filled and signed by the holders.

3. The Board of Directors has appointed M/s. T. Chatterjee & Associates, Practicing Company Secretaries firm (ICSI - Firm Unique Code No.: P2007WB067100) represented by Ms. Sumana Subhash Mitra – Practicing Company Secretary (C.P No. 22915), Partner of M/s. T. Chatterjee & Associates failing her, Mr. Tarun Chatterjee – Advocate (Enrolment No. WB 2068), (the "Scrutinizer") as a scrutinizer to scrutinize the e-voting and remote e-voting process in a fair and transparent manner.

4. Pursuant to Section 108 of the Companies Act read with rule 20 of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 as amended from time to time and Regulation 44 of the Listing Regulations, the Company is providing to its Members the facility of remote e-voting before the AGM and during the AGM in respect of the businesses to be transacted at the AGM and for this purpose, the Company has appointed National Securities Depository Limited (**"NSDL"**) for facilitating voting through electronic means. The detailed instructions for e-voting are given in the Notice of AGM. The Members are hereby notified that:

(i) The business set forth in the notice of the AGM may be transacted through voting by electronic means.

(ii) The remote e-voting shall commence on Tuesday, September 8, 2026 (09.00 a.m. IST).

(iii) The remote e-voting shall end on Thursday, September 10, 2026 (5.00 p.m. IST). The e-voting module shall be disabled by NSDL thereafter. Once the vote on a resolution is cast by the shareholder, the shareholder shall not be allowed to change it subsequently.

(iv) The cut-off date for determining the eligibility to vote is Friday, September 4, 2026. The voting rights of the Member shall be in proportion to their share of the paid-up equity share capital of the Company as on cut-off date.

(v) Persons who have acquired shares of the Company and become members of the Company after dispatch of the Notice and holding shares as of the cut-off date i.e. Friday, September 4, 2026, may cast their vote by remote e-voting or during the Meeting, by obtaining the login ID and password by sending a request at evoting@nsdl.co.in. However, if you are already registered with NSDL for remote e-voting then you can use existing user ID and password for casting your vote.

(vi) Members may also note that: (a) Remote e-voting shall not be allowed beyond 5.00 p.m. IST on Thursday, September 10, 2026; (b) Facility for e-voting shall also be made available during the AGM; (c) Members attending the meeting through VC or OAVM, who have not already cast their vote by remote e-voting, shall be able to exercise their right during the meeting; (d) Members who have cast their vote by remote e-voting may also attend the meeting, but shall not be allowed to vote again during the AGM; and (e) Any person whose name appears in the Register of Members of the Company / the register of beneficial owners maintained by the Depositories, as on the cut-off date i.e. Friday, September 4, 2026 only shall be entitled to vote.

(vii) Members holding shares in physical form are requested to register their email address with the Registrar of the Company by sending an email on investor.helpdesk@in.mpms.mufg.com by mentioning Folio No. and Name of shareholder. Members holding shares in demat form are requested to register their email address with their Depository Participant.

(viii) The Notice of AGM is available on the Company's website www.speciality.co.in and on the website of NSDL www.evoting.nsdl.com.

ix) A person who is not a Member as on the cut-off date should treat the Notice of the AGM for information purposes only.

(x) In case of any queries, you may refer the Frequently Asked Questions (FAQs) for Shareholders and e-voting user manual for Shareholders available at the download section of www.evoting.nsdl.com or call on 022 - 4886 7000 or send a request to Ms. Pallavi Mhatre, Deputy Vice President, NSDL at the designated e-mail id evoting@nsdl.co.in. The postal address of NSDL is 3rd Floor, Naman Chamber, Plot C-32, G-Block, Bandra Kurla Complex, Bandra East, Mumbai, Maharashtra – 400051.

(xi) The results of voting will be declared and published, along with consolidated Scrutinizer's Report, on the website of the Company www.speciality.co.in and on NSDL website www.evoting.nsdl.com and the same shall also be simultaneously communicated to the BSE Limited and the National Stock Exchange of India Limited within two working days of the conclusion of the AGM.

By order of the Board of Directors
For Speciality Restaurants Limited

Avinash Kinhikar
Company Secretary & Legal Head
(ICSI Membership No.: FCS 8364)

Place: Mumbai
Date: August 18, 2026

THIS IS A PUBLIC ANNOUNCEMENT FOR INFORMATION PURPOSES ONLY. THIS IS NOT A PROSPECTUS ANNOUNCEMENT AND DOES NOT CONSTITUTE AN INVITATION OR OFFER TO ACQUIRE, PURCHASE OR SUBSCRIBE FOR UNITS OR SECURITIES UNDER THE SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (ISSUE OF CAPITAL AND DISCLOSURE REQUIREMENTS) REGULATIONS, 2018, AS AMENDED ("SEBI ICDR REGULATIONS"). NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION, DIRECTLY OR INDIRECTLY OUTSIDE INDIA.

(Please scan this QR code to view Addendum)

GAURIK GROUP

GAURIK FASHIONS LIMITED

Our Company was originally incorporated as a private limited company under Companies Act, 2013 in the name and style of "Gaurik Fashions Private Limited" vide Certificate of Incorporation dated March 24, 2017, issued by Registrar of Companies, Central Registration Centre, bearing CIN U52609DL2017PTC315030. Further, our company converted from private limited to a public limited company pursuant to a special resolution passed by the members of our Company at the Extra-Ordinary General Meeting held on November 28, 2024 and name of our Company changed from "Gaurik Fashions Private Limited" to "Gaurik Fashions Limited" and Central Processing Centre, has issued a new certificate of incorporation consequent upon conversion dated December 23, 2024, bearing CIN U52609DL2017PLC315030. Further, pursuant to change in the object clause of the company, the Central Processing Centre has issued a new certificate of incorporation dated November 26, 2025, bearing CIN U46909DL2017PLC315030. For further details, see *"History and Certain Corporate Matters – Brief History of our Company"* on page 189 of the Draft Red Herring Prospectus.

Corporate Identity Number: U46909DL2017PLC315030
Registered Office: 1st Floor, Rear Portion, Block A, Centre for Indian Classical dance (CICD), Gulmohar Park, Hauz Khas, New Delhi, 110016, India
Corporate Office: 1867, Hennur 4th & 5th Floor, 5th Block, 1st Stage, HBR Layout, Bengaluru- 560043, Karnataka, India
Contact Person: Yogita, Company Secretary and Compliance Officer; **Tel:** 011-40113227; **E-mail:** cs@gaurikgroup.com; **Website:** www.gaurikgroup.com

NOTICE TO INVESTORS: ADDENDUM TO THE DRAFT RED HERRING PROSPECTUS DATED AUGUST 18, 2026 (THE "ADDENDUM")

OUR PROMOTERS: VISHNU PILLAI, RAJESH DUDI, SWATI SINHA, AND ISHA DUDI

INITIAL PUBLIC OFFER OF UP TO 70,00,000 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹10 EACH ("EQUITY SHARES") OF GAURIK FASHIONS LIMITED ("COMPANY" OR THE "ISSUER") FOR CASH AT A PRICE OF ₹[●] PER EQUITY SHARE (INCLUDING A SHARE PREMIUM OF ₹[●] PER EQUITY SHARE) ("OFFER PRICE") AGGREGATING UP TO ₹[●] MILLION COMPRISING A FRESH ISSUE OF UP TO 62,00,000 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹10 EACH AGGREGATING UP TO [●] MILLION BY OUR COMPANY ("FRESH ISSUE") AND AN OFFER FOR SALE OF UP TO 8,00,000 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹10 EACH AGGREGATING UP TO ₹[●] MILLION ("OFFERED SHARES") BY ARIES OPPORTUNITIES FUND LIMITED (THE "INVESTOR SELLING SHAREHOLDER"), AND SUCH EQUITY SHARES OFFERED BY THE INVESTOR SELLING SHAREHOLDER ("OFFER FOR SALE", AND TOGETHER WITH THE FRESH ISSUE, THE "OFFER"). THE OFFER WILL CONSTITUTE [●] % OF OUR POST-OFFER PAID-UP EQUITY SHARE CAPITAL.

This public announcement is being issued pursuant Addendum to the DRHP with respect to the cessation of Unistone Capital Private Limited as a Book Running Lead Manager to the Offer. Accordingly, Credora Partners Private Limited shall continue to act as the Sole Book Running Lead Manager to the Offer.

The above-mentioned changes are set out in the Addendum to the DRHP, are to be read in conjunction with the Draft Red Herring Prospectus and accordingly, the corresponding references in the Draft Red Herring Prospectus stand updated pursuant to the Addendum. The information in the Addendum supplements and updates the information in the Draft Red Herring Prospectus, as applicable. However, the Addendum does not reflect all the changes that have occurred between the date of filing of the Draft Red Herring Prospectus and the date hereof, and accordingly does not include all the changes and/or updates that will be included in the Red Herring Prospectus and the Prospectus. Please note that all other details / information included in the Draft Red Herring Prospectus will be suitably updated, including to the extent stated in the Addendum, along with other factual updates, as may be applicable, in the Red Herring Prospectus and the Prospectus, as and when filed with the RoC, SEBI, NSE and BSE. Investors should not rely on the Draft Red Herring Prospectus or the Addendum for any investment decision, and should read the Red Herring Prospectus, as and when it is filed with the RoC, SEBI, NSE and BSE before making an investment decision with respect to the Offer.

Our Company hereby invites the public to give their comments on the Addendum to the DRHP (read along with the DRHP) filed with SEBI and the Stock Exchanges, with respect to disclosures made in the Addendum to the DRHP (read along with the DRHP). The members of public are requested to send a copy of their comments to SEBI, to the Company Secretary and Compliance Officer of our Company and/or the BRLM at their respective addresses mentioned herein below. All comments must be received by SEBI and/or our Company and/or the BRLM and/or the Company Secretary and Compliance Officer of our Company at their respective addresses mentioned herein below in relation to the Offer on or before 5:00 p.m. on the 21st day from August 18, 2026, being the date of the Addendum, in accordance with the SEBI ICDR Regulations.

The Addendum to the DRHP will be available on the website of SEBI i.e., www.sebi.gov.in, the websites of BSE i.e., www.bseindia.com, the website of the NSE i.e., https://www.nseindia.com/, the website of our Company i.e., https://gaurikgroup.com/, and the website of the BRLM, i.e., https://credorapartners.com/

All capitalized terms used in the Addendum shall, unless the context otherwise requires, have the meaning ascribed to them in the Draft Red Herring Prospectus.

BOOK RUNNING LEAD MANAGER	REGISTRAR TO THE OFFER
CREDORA PARTNERS ALLIANCE OF TRUST	MASS
Credora Partners Private Limited 6th Floor, B Wing, GSC Tower, Sector 30, Gurugram – 122001, Haryana, India **Telephone:** +91-124-4293471; **Email:** info@credorapartners.com **Contact Person:** Pankaj Kumar Pasi; **Website:** www.credorapartners.com **Investor Grievance ID:** investors@credorapartners.com **SEBI Registration Number:** INM000013411	**Mas Services Limited** T-34 Floor, 2nd Floor, Okhla Industrial Area, Phase-II New Delhi- 110020 **Telephone Number:** 011-26387281-83, 011-41320335; **Fax:** 011-26387384 **Email:** info@masserv.com and investor@masserv.com **Contact Person:** N.C. Pal; **Website:** www.masserv.com **SEBI Registration Number:** INR000000049

Gaurik Fashions Limited
On behalf of the Board of Directors
Sd/-
Yogita
Company Secretary and Compliance Officer

Date : August 19, 2026
Place : Delhi

GAURIK FASHIONS LIMITED is proposing, subject to applicable statutory and regulatory requirements, receipt of requisite approvals, market conditions and other considerations, to undertake an initial public offer of its Equity Shares and has filed the DRHP dated May 10, 2026 with SEBI and the Stock Exchanges on May 10, 2026. The DRHP shall be available on the website of SEBI at www.sebi.gov.in, on the websites of the Stock Exchanges, i.e., BSE at www.bseindia.com, NSE at www.nseindia.com, on the websites of the BRLM, i.e., Credora Partners Private Limited at www.credorapartners.com and on the website of our Company at www.gaurikgroup.com. Potential investors should note that investment in equity shares involves a high degree of risk and for details relating to such risks, see the section titled *"Risk Factors"* on page 29 of the DRHP. Potential investors should not rely on the DRHP filed with SEBI and the Stock Exchanges for making any investment decision.

This announcement does not constitute an offer of the Equity Shares for sale in any jurisdiction, including the United States, and the Equity Shares may not be offered or sold in the United States absent registration under the US Securities Act of 1933 or an exemption from registration. Any public offering of the Equity Shares to be made in the United States will be made by means of a prospectus that may be obtained from the Company and that will contain detailed information about the Company and management, as well as financial statements. However, the Equity Shares are not being offered or sold in the United States.

KIRIN

When industry giants speak, everyone listens.

In-depth **Q&As** with market mavens — *every Monday* in Business Standard.

To book your copy, SMS **reachbs** to **57575** or email **order@bsmail.in**

Business Standard
Insight Out

THIS IS A PUBLIC ANNOUNCEMENT FOR INFORMATION PURPOSES ONLY AND IS NOT A PROSPECTUS ANNOUNCEMENT. THIS DOES NOT CONSTITUTE AN INVITATION OR OFFER TO ACQUIRE, PURCHASE OR SUBSCRIBE TO SECURITIES. THIS PUBLIC ANNOUNCEMENT IS NOT INTENDED FOR PUBLICATION OR DISTRIBUTION, DIRECTLY OR INDIRECTLY OUTSIDE INDIA.

C3 LOGISTICS

(Scan this QR to view the Prospectus)

CREDENT CONNECT N CARE LIMITED

THE EQUITY SHARES OF THE COMPANY WILL GET LISTED ON THE SME PLATFORM OF THE NATIONAL STOCK EXCHANGE OF INDIA LIMITED ("NSE EMERGE")

Our Company was originally incorporated as a Private Limited Company under the name of **"Credent Cold Chain Logistics Private Limited"** on June 25, 2015 under the provisions of the Companies Act, 2013 with the Registrar of Companies, Delhi bearing **CIN: U63000DL2015PTC281994.** Further in order to align the name of our Company with the objects of the Company and, pursuant to Special Resolution passed by the shareholders at the Extra Ordinary General Meeting held on January 12, 2024, the name of our Company was changed from **"Credent Cold Chain Logistics Private Limited"** to **"Credent Connect N Care Private Limited"** and a fresh certificate of incorporation consequent upon Change of Name was issued by the Registrar of Companies, CPC vide certificate dated May 10, 2024 bearing **CIN: U63000DL2015PTC281994.** Further, pursuant to a special resolution passed by the shareholder at extra Ordinary General Meeting held on September 15, 2025, company has converted from Private Limited to public limited and name of the company was changed from **"Credent Connect N Care Private Limited"** to **"Credent Connect N Care Limited"** and a fresh certificate of incorporation consequent upon conversion into public limited was issued by the Registrar of Companies, CPC vide certificate dated October 28, 2025 bearing **CIN: U63000DL2015PLC281994.**

Registered Office: B-3, Second Floor, Nimri Commercial Complex, Ashok Vihar, Phase-4, New Delhi – 110 052, Delhi, India.
Tel.: +91-9971777199 ; **E-mail:** cs@c3logistics.co.in ; **Website:** https://c3logistics.co.in/
Contact Person: Arpita Abhilasha, Company Secretary & Compliance Officer

OUR PROMOTERS: ASHOK KUMAR SHARMA, KARAN SHARMA, TARUN SHARMA, DIMPLE SHARMA AND TANVEEN

Our Company has filed the Prospectus dated August 18, 2026 with ROC and Equity Shares are proposed to be listed on SME Platform of The National Stock Exchange of India Limited **("NSE EMERGE")** on Thursday, August 20, 2026.

"THE ISSUE IS BEING MADE IN ACCORDANCE WITH CHAPTER IX OF THE SEBI ICDR REGULATIONS (IPO OF SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES) AND THE EQUITY SHARES ARE PROPOSED TO BE LISTED ON SME PLATFORM OF THE NATIONAL STOCK EXCHANGE OF INDIA LIMITED ("NSE EMERGE")."

BRIEF DESCRIPTION OF THE BUSINESS OF THE COMPANY

Our company is a healthcare services provider engaged in delivering integrated logistics, workforce solutions, and technology-enabled support to healthcare institutions across India. We provide comprehensive operational and logistics services to diagnostic laboratories, In Vitro Diagnostics (IVD) companies, pharmaceutical companies, clinics, and other healthcare enterprises through end-to-end solutions. Our offerings majorly include home sample collection through trained phlebotomists; Operations & Supply Chain Services through stationed phlebotomy teams at laboratories and hospitals; deployment of skilled laboratory technicians and paramedical staff for internal operations; and specialized inter-state and intra-state logistics services. Our logistics solutions ensure temperature-controlled and Turnaround time (TAT) sensitive movement of blood samples and other healthcare products.

BASIS OF ALLOTMENT

INITIAL PUBLIC ISSUE OF UPTO 49,68,000 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹ 10/- EACH (THE "EQUITY SHARES") OF CREDENT CONNECT N CARE LIMITED (FORMERLY KNOWN AS CREDENT COLD CHAIN LOGISTICS PRIVATE LIMITED) ("OUR COMPANY" OR "CREDENT" OR "THE ISSUER") AT AN ISSUE PRICE OF ₹ 189 PER EQUITY SHARE (INCLUDING SHARE PREMIUM OF ₹179 PER EQUITY SHARE) FOR CASH, AGGREGATING UP TO ₹ 9,389.52 LAKHS ("PUBLIC ISSUE") OUT OF WHICH 2,52,000 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹ 10 EACH, AT AN ISSUE PRICE OF ₹ 189 PER EQUITY SHARE FOR CASH, AGGREGATING ₹ 476.28 LAKHS WILL BE RESERVED FOR SUBSCRIPTION BY THE MARKET MAKER TO THE ISSUE (THE "MARKET MAKER RESERVATION PORTION"). THE PUBLIC ISSUE LESS MARKET MAKER RESERVATION PORTION I.E. ISSUE OF 47,16,000 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹ 10 EACH, AT AN ISSUE PRICE OF ₹ 189 PER EQUITY SHARE FOR CASH, AGGREGATING UPTO ₹ 8,913.24 LAKHS IS HEREIN AFTER REFERRED TO AS THE "NET ISSUE". THE PUBLIC ISSUE AND NET ISSUE WILL CONSTITUTE 26.44% AND 25.10% RESPECTIVELY OF THE POST- ISSUE PAID-UP EQUITY SHARE CAPITAL OF OUR COMPANY.

THE FACE VALUE OF THE EQUITY SHARE IS ₹10 AND ISSUE PRICE IS ₹189 EACH. THE ISSUE PRICE IS 18.90 TIMES THE FACE VALUE OF THE EQUITY SHARE.
ANCHOR INVESTOR ISSUE PRICE: ₹189 EQUITY SHARE.
THE ISSUE PRICE IS 18.90 TIMES THE FACE VALUE

BID/ ISSUE PERIOD

ANCHOR INVESTOR BIDDING DATE: WEDNESDAY, AUGUST 12, 2026
BID/ ISSUE OPENED ON: THURSDAY, AUGUST 13, 2026
BID/ ISSUE CLOSED ON: MONDAY, AUGUST 17, 2026

RISKS TO INVESTORS:

a) *We derive a significant portion of our revenue from operations from our top 10 customers with which we do not have any firm commitments. The loss of any one or more of our major customers would have a material adverse effect on our business, cash flows, results of operations and financial condition.*
b) *Our business is dependent on diagnostic and healthcare companies, and any reduction in their testing volumes, outsourcing requirements, or adverse sector developments could materially and adversely affect our business, financial condition, and results of operations.*
c) *We are exposed to risks relating to loss, damage, contamination or delay in transportation of diagnostic samples, which could result in client claims, financial liabilities and reputational harm.*
d) *Our business depends on service-level contracts with clients that are subject to renewal, renegotiation and termination, and our inability to maintain or renew such contracts on favourable terms could materially and adversely affect our business.*
e) *Our business is working capital intensive and trade receivables constitute a significant portion of our current assets. Any delay or failure in realisation of trade receivables could adversely affect our cash flows, liquidity and financial condition.*
f) *Our business is highly dependent on the availability and performance of a large, skilled and geographically dispersed workforce, and our inability to effectively manage, train and retain such personnel could adversely affect our operations.*
g) *Our operations depend on the continuous availability of specialised packaging materials and consumables, and any disruption in their supply or increase in their cost could adversely affect our service delivery and profitability.*
h) *Misconduct, fraud, negligence or theft by our field personnel could adversely affect our business, reputation and financial condition.*
i) *Our subsidiary companies has incurred losses and had a negative net worth in the past, and any future losses may adversely affect its financial condition and our consolidated results.*
j) *We rely on financing from banks or financial institutions to carry on our business operations, and inability to obtain additional financing on terms favorable to us or at all could have an adverse impact on our financial condition. If we are unable to raise additional capital, our business and future financial performance could be adversely affected.*
k) *The BRLM associated with the Issue has handled 64 Public Issues in the past three years, out of which 4 issues were closed below the Issue/Offer Price on listing date:*

Name of BRLM	Total Issue		Issue closed below IPO Price on listing date
	Mainboard	SME	
Hem Securities Limited	2	62	4 (SME)

l) Average cost of acquisition of Equity Shares held by the Promoters is

Sr. No.	Name of the Promoters	No. of Shares held	Average cost of Acquisition (in ₹)
1.	Ashok Kumar Sharma	36,58,950	-
2.	Karan Sharma	22,47,825	0.31
3.	Tarun Sharma	20,23,550	-
4.	Dimple Sharma	1,32,550	-
5.	Tanveen	35,38,125	-

m) The Price/ Earnings ratio based on Diluted EPS for Fiscal 2026 for the company at the upper end (₹189) of the Price Band is 13.55
n) Weighted Average Return on Net worth for Fiscals 2026, 2025 and 2024 is 29.03%.
o) The Weighted average cost of acquisition of all Equity Shares transacted in the last one year, 18 months and three years from the date of Prospectus is as given below:

Period	Weighted Average Cost of Acquisition (in ₹)	Cap Price (₹189) is 'X' times the Weighted Average Cost of Acquisition	Range of acquisition price: Lowest Price – Highest Price (in ₹)
Last 1-year preceding date of Prospectus	15.23	12.41	0-1576
Last 18 months preceding date of Prospectus	15.60	12.12	0-1576
Last 3-years preceding date of Prospectus	15.60	12.12	0-1576

p) The Weighted average cost of acquisition compared to Floor Price and Cap Price.

Types of transactions	Weighted average cost of acquisition (₹ per Equity Shares)	Floor price (i.e., ₹179)	Cap price (i.e., ₹189)
Weighted average cost of acquisition of primary/new issue.	1576*	0.11	0.12
Weighted average cost of acquisition for secondary sale/ acquisition.	187	0.96	1.01
Weighted average cost of acquisition of primary issuances / secondary transactions.	NIL	NIL	NIL

**Price adjusted after bonus issue is ₹30.90 per share.*

LISTING DATE: THURSDAY, AUGUST 20, 2026

The Issue was made through the Book Building Process, in terms of Rule 19(2)(b)(i) of the Securities Contracts (Regulation) Rules, 1957, as amended ("SCRR") read with Regulation 253 of the SEBI ICDR Regulations, as amended, wherein not more than 50% of the Net Issue was made available on a proportionate basis to Qualified Institutional Buyers ("QIBs", the "QIB Portion"), provided that our Company may, in consultation with the Book Running Lead Managers, allocated 60% of the QIB Portion to Anchor Investors on a discretionary basis in accordance with the SEBI ICDR Regulations **("Anchor Investor Portion")**, of which 40% of such Anchor Investor Portion was reserved for, (i) 33.33% was made available for allocation to domestic Mutual Funds, and (ii) 6.67% for life insurance companies and pension funds, subject to valid Bids have being received from domestic Mutual Funds, life insurance companies and pension funds at or above the Anchor Investor Allocation Price. In the event of under-subscription in (ii) above, the allocation was made to domestic Mutual Funds in accordance with the SEBI ICDR Regulations. Further, 5% of the Net QIB Portion was made available for allocation on a proportionate basis only to Mutual Funds, and the remainder of the Net QIB Portion was made available for allocation on a proportionate basis to all QIBs, including Mutual Funds, subject to valid Bids being received at or above the Issue Price. However, if the aggregate demand from Mutual Funds is less than 5% of the Net QIB Portion, the balance Equity Shares available for allocation in the Mutual Fund Portion was added to the remaining Net QIB Portion for proportionate allocation to QIBs. Further, not less than 15% of the Net Issue was made available for allocation on a proportionate basis to Non-Institutional Bidders (of which one third of the Non-Institutional Portion was reserved for Bidders with an application size of more than two lots and up to such lots equivalent to not more than ₹10 lakhs and two-thirds of the Non Institutional Portion was reserved for Bidders with an application size exceeding ₹ 10 lakhs) and undersubscription in either of these two sub-categories of Non-Institutional Portion was allocated to Bidders in the other subcategory of Non-Institutional Portion, subject to valid Bids have being received at or above the Issue Price and not less than 35% of the Net Issue was available for allocation to Individual Bidders in accordance with the SEBI ICDR Regulations, subject to valid Bids have being received at or above the Issue Price. All potential Bidders (except Anchor Investors) were required to mandatorily utilize the Application Supported by Blocked Amount ("ASBA") process providing details of their respective ASBA accounts, and UPI ID in case of Individual Bidders using the UPI Mechanism, if applicable, in which the corresponding Bid Amounts was blocked by the SCSBs or by the Sponsor Bank under the UPI Mechanism, as the case may be, to the extent of respective Bid Amounts. Anchor Investors were not permitted to participate in the Anchor Investor Portion of the Issue through the ASBA process. For details, see ***"Issue Procedure"*** beginning on page 271 of the Prospectus.

The investors are advised to refer to the Prospectus for the full text of the Disclaimer clause pertaining to NSE. For the purpose of this Issue, the designated Stock Exchange will be the NSE Limited. The trading will commence on Thursday, August 20, 2026.

SUBSCRIPTION DETAILS

The bidding for Anchor Investors opened and closed on Wednesday, August 12, 2026. The Company received 10 Anchor Investors applications for 16,68,000 Equity Shares. The Anchor Investor Allocation price was finalized at ₹189 per Equity Share. A total of 14,04,000 Equity Shares were allotted under the Anchor Investors portion aggregating to ₹26,53,56,000.

The Issue (excluding Anchor Investors Portion) received 231,176 Applications for 509,128,200 Equity Shares (after considering invalid bids, Other than RC10 Transaction declined by Investors, RC10 Mandate not accepted by Investors and Withdrawal/ Cancelled Bids reported by SCSB and all rejections) resulting 142.85 times subscription (including reserved portion of market maker, and excluding anchor investor portion). The details of the Applications received in the Issue from various categories are as under *(before rejections):*

Detail of the Applications Received (excluding Anchor Investors Portion):

Sr. No.	Category	Number of Applications	No. of Equity Shares applied	Equity Shares Reserved as per Prospectus	No. of times Subscribed	Amount (₹)
1	Individual Investors	192,394	230,886,600	1,656,000	139.42	43,633,233,600.00
2	Non-Institutional Investors (More than ₹300,000/- to ₹1,000,000/-)	16,844	33,165,000	237,600	139.58	6,266,763,600.00
3	Non-Institutional Investors (More than ₹1,000,000/-)	21,843	121,724,400	470,400	258.77	23,005,797,600.00
4	Qualified Institutional Bidders (excluding Anchors Investors)	94	123,100,200	948,000	129.85	23,265,937,800.00
5	Market Maker	1	252,000	252,000	1.00	47,628,000.00
	Total	**231,176**	**509,128,200**	**3,564,000**	**142.85**	**96,219,360,600.00**

Final Demand:

A summary of the final demand as per NSE as on the Bid/ Issue Closing Date at different Bid prices is as under:

Sr. No.	Bid Price	No. of Equity Shares	% to Total	Cumulative Share Total	Cumulative % of Total
1	179	489,000	0.09	489,000	0.09
2	180	103,800	0.02	592,800	0.11
3	181	22,200	0.00	615,000	0.11
4	182	24,600	0.00	639,600	0.12
5	183	11,400	0.00	651,000	0.12
6	184	30,000	0.01	681,000	0.12
7	185	100,800	0.02	781,800	0.14
8	186	25,200	0.00	807,000	0.15
9	187	112,800	0.02	919,800	0.17
10	188	197,400	0.04	1,117,200	0.20
11	189	548,244,600	99.80	549,361,800	100.00
	CUTOFF		0.00		
	Total	**549,361,800**	**100.00**		

The Basis of Allotment was finalized in consultation with the designated Stock Exchange, being National Stock Exchange of India Limited ***("NSE Emerge")*** on August 18, 2026.

1) Allotment to Individual Investors *(after rejections):*

The Basis of Allotment to the Individual Investors, who have Bid at or above the Issue Price of ₹189 per equity share, was finalized in consultation with NSE. The category has been subscribed to the extent of 136.72391 times i.e., for 226,414,800 equity shares, the total number of equity shares allotted in this category is 1,656,000 equity share to 1,380 successful applicants. The details of the Basis of Allotment of the said category are as under:

Sr. No.	Number of shares applied for Category Wise	Number of Applications Received	% of Total	Total No. of shares Applied	% of Total	Number of Shares Allotted to Applicant	Ratio	Total Number of shares Allocated/ Allotted
1	1,200	188,679	100.00	226,414,800	100.00	1,200	29 : 3965	1,656,000
	TOTAL	**188,679**	**100.00**	**226,414,800**	**100.00**			**1,656,000**

2) Allotment to Non-Institutional Investors (More than 2 lots and up to ₹ 10,00,000) *(after rejections):*

The Basis of Allotment to the Non-Institutional Investors, who have bid at the Issue Price of ₹189 or above per equity share was finalized in consultation with NSE. The category has been subscribed to the extent of 137.52020 times i.e., for 32,674,800 equity shares, the total number of equity shares allotted in this category is 237,600 equity shares to 132 successful applicants. The details of the Basis of Allotment of the said category are as under:

Sr. No.	Number of shares applied for Category Wise	Number of Applications Received	% of Total	Total No. of shares Applied	% of Total	Number of Shares Allotted to Applicant	Ratio	Total Number of shares Allocated/ Allotted
1	1800	13,902	83.75	25,023,600	76.58	1800	110 : 13902	198,000
2	2400	1,872	11.28	4,492,800	13.75	1800	15 : 1872	27,000
3	3000	273	1.64	819,000	2.51	1800	2 : 273	3,600
4	3600	217	1.31	781,200	2.39	1800	2 : 217	3,600
5	4200	83	0.50	348,600	1.07	1800	1 : 83	1,800
6	4800	252	1.52	1,209,600	3.70	1800	2 : 252	3,600
	Total	**16,599**	**100**	**32,674,800**	**100**			**237,600**

Continued on next page

Continued from previous page

3) Allotment to Non-Institutional Investors (More than ₹ 10,00,000) ***(after rejections):***

The Basis of Allotment to the Non-Institutional Investors, who have bid at the Issue Price of ₹189 or above per equity share was finalized in consultation with NSE. The category has been subscribed to the extent of 257.39796 times i.e., for 121,080,000 equity shares, the total number of equity shares allotted in this category is 470,400 equity shares to 261 successful applicants. The details of the Basis of Allotment on sample basis of the said category are as under (sample basis)

Sr. No.	Number of shares applied for Category Wise	Number of Applications Received	% of Total	Total No. of shares Applied	% of Total	Number of Shares Allotted to Applicant	Ratio	Total Number of shares Allocated/ Allotted
1	5400	20,822	95.83	112,438,800	92.86	1,800	125 : 10411	450,000
2	6000	456	2.10	2,736,000	2.26	1,800	5 : 456	9,000
3	6600	173	0.80	1,141,800	0.94	1,800	2 : 173	3,600
4	7200	39	0.18	280,800	0.23	1,800	0 : 39	-
5	7800	37	0.17	288,600	0.24	1,800	0 : 37	-
6	8400	24	0.11	201,600	0.17	1,800	0 : 24	-
7	9000	25	0.12	225,000	0.19	1,800	0 : 25	-
8	9600	11	0.05	105,600	0.09	1,800	0 : 11	-
9	10200	4	0.02	40,800	0.03	1,800	0 : 4	-
10	10800	39	0.18	421,200	0.35	1,800	0 : 39	-
11	11400	6	0.03	68,400	0.06	1,800	0 : 6	-
12	12000	19	0.09	228,000	0.19	1,800	0 : 19	-
13	12600	2	0.01	25,200	0.02	1,800	0 : 2	-
40	54000	5	0.02	270,000	0.22	1,800	0 : 5	-
41	58200	1	0.00	58,200	0.05	1,800	0 : 1	-
42	58800	1	0.00	58,800	0.05	1,800	0 : 1	-
43	60000	3	0.01	180,000	0.15	1,800	0 : 3	-
44	63600	1	0.00	63,600	0.05	1,800	0 : 1	-
45	64200	1	0.00	64,200	0.05	1,800	0 : 1	-
46	64800	1	0.00	64,800	0.05	1,800	0 : 1	-
47	72000	1	0.00	72,000	0.06	1,800	0 : 1	-
48	84600	1	0.00	84,600	0.07	1,800	0 : 1	-
49	105600	1	0.00	105,600	0.09	1,800	0 : 1	-
50	150000	1	0.00	150,000	0.12	1,800	0 : 1	-
51	216000	1	0.00	216,000	0.18	1,800	0 : 1	-
	Non Allottees	-	0.00	-	-	1,800	4 : 278	7,200
	All Allottees	-	0.00	-	-	600	1 : 261	600
	TOTAL	**21,729**	**100.00**	**121,080,000**	**100.00**			**470,400**

Please Note : 1 (One) lot of 1800 shares have been allocated to all the 278 Non Allottees Applicants in Categories with ZERO/NO Allotment in the ratio of 4:278

Please Note : 1 (One) lot of 600 shares have been allocated to all the 261 Successful Applicants from all the Categories in the ratio of 1 : 261

4) Allotment to Market Maker: The Basis of Allotment to Market Maker who have bid at Issue Price of ₹189 per equity shares or above, was finalized in consultation with NSE. The category was subscribed by 1.00 times i.e., or 252,000 equity shares, the total number of shares allotted in this category is 252,000 equity shares to 1 successful applicant. The category wise details of the Basis of Allotment are as under:

S. No.	No. of Shares Applied for (Category wise)	No. of Applications received	% to total	Total No. of Equity Shares applied in this Category	% of total	No. of Equity Shares allocated/ allotted per Applicant	Ratio	Total No. of shares allocated/allotted
1	252,000	1	100.00	252,000	100.00	252,000	1:1	252,000

5) Allotment to QIBs excluding Anchor Investors ***(after rejections):***

The Basis of Allotment to QIBs, who have bid at Issue Price of ₹189 per Equity Shares or above, was finalized in consultation with NSE. The category was subscribed by 129.85253 times i.e., 123,052,800 equity shares. As per the SEBI Regulations, 5% of Net QIB portion was reserved for mutual funds i.e., 47,400 equity shares and other QIBs and unsatisfied demand of Mutual Funds were allotted the remaining available equity shares i.e., 900,600 equity shares on a proportionate basis. The total number of shares allotted in this category is 948,000 equity shares to 91 successful applicants. The category wise details of the Basis of Allotment are as under:

Category	FI'S/BANK'S	MF'S	IC'S	NBFC'S	AIF	FPC/FII	Others	Total
QIB	123,600	67,200	4,800	-	-	134,400	618,000	**948,000**

6) Allotment to Anchor Investors ***(after rejections):***

The Company in consultation with the BRLM has allocated 1,404,000 Equity Shares to 10 Anchor Investors at the Anchor Investor Issue Price of ₹189 per equity shares in accordance with the SEBI (ICDR) Regulations. This represents upto 60% of the QIB Category.

Number of shares applied for Category Wise	FIS/BANKS	MF'S	IC'S	NBFC'S	AIF	FPI/FPC	VC'S	TOTAL
ANCHOR	-	-	-	318,600	661,800	423,600	-	**1,404,000**

The Board of Directors of our Company at its meeting held on August 18, 2026 has taken on record the basis of allotment of equity shares approved by the designated Stock Exchange, being NSE and has allotted the equity shares to various successful applicants. The Allotment Advice Cum Refund Intimation have been dispatched to the address of the investors as registered with the depositories. Further, instructions to the SCSBs have been dispatched/ mailed for unblocking of funds and transfer to the Public Issue Account on August 18, 2026. In case the same is not received within ten days, investors may contact the Registrar to the Issue at the address given below. The Equity Shares allotted to the successful allottees shall be uploaded on August 19, 2026 for credit into the respective beneficiary accounts subject to validation of the account details with the depositories concerned. The Company has filed Listing Application to NSE on August 19, 2026. The Company has received the listing and trading approval from NSE, and trading will commence on August 20, 2026.

Note: *All capitalized terms used and not defined herein shall have the respective meanings assigned to them in the Prospectus.*

INVESTORS, PLEASE NOTE

The details of the allotment made was hosted on the website of the Registrar to the Issue, Kfin Technologies Limited.

All future correspondence in this regard may kindly be addressed to the Registrar to the Issue quoting full name of the First/ Sole Bidder Serial number of the ASBA form, number of Equity Shares bid for, Bidder DP ID, Client ID, PAN, date of submission of the Bid cum Application Form, address of the Bidder, the name and address of the Designated Intermediary where the Bid cum Application Form was submitted by the Bidder and copy of the Acknowledgment Slip received from the Designated Intermediary and payment details at the address given below:

KFINTECH
EXPERIENCE TRANSFORMATION

KFIN TECHNOLOGIES LIMITED
Reg. Office: 301, The Centrium, 3rd Floor, 57, Lal Bahadur Shastri Road, Nav Pada, Kurla (West), Mumbai – 400070, Maharashtra
Corp. Office: Selenium Tower-B, Plot 31 & 32, Gachibowli, Financial District, Nanakramguda, Serilingampally, Hyderabad – 500 032, Telangana
Telephone: +91 40-6716 2222 ; **Email:** credentconnect.ipo@kfintech.com;
Investor Grievance Email: einward.ris@kfintech.com ; **Website:** www.kfintech.com
Contact Person: M. Murali Krishna; **SEBI Regn. No.:** INR000000221

On behalf of Board of Directors
Credent Connect N Care Limited
Sd/-
Arpita Abhilasha
Company Secretary and Compliance Officer

Place: Delhi
Date: August 19, 2026

THE LEVEL OF SUBSCRIPTION SHOULD NOT BE TAKEN TO BE INDICATIVE OF EITHER THE MARKET PRICE OF THE EQUITY SHARES ON LISTING OR THE BUSINESS PROSPECTS OF CREDENT CONNECT N CARE LIMITED

Disclaimer: *Credent Connect N Care Limited has filed the Prospectus with the RoC on August 18, 2026 and thereafter with SEBI and the Stock Exchange. The Prospectus is available on the website of the BRLM, Hem Securities Limited at www.hemsecurities.com and the Company at https://c3logistics.co.in/ and shall also be available on the website of the NSE and SEBI. Investors should note that investment in Equity Shares involves a high degree of risk and for details relating to the same, please see* ***"Risk Factors"*** *beginning on page 20 of the Prospectus.*

The Equity Shares have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the ***"Securities Act"****) or any state securities laws in the United States, and unless so registered, and may not be issued or sold within the United States, except pursuant to an exemption from, or in a transaction not subject to, the registration requirements of the Securities Act and in accordance with any applicable U.S. state securities laws. The Equity Shares are being Issued and sold outside the United States in 'offshore transactions' in reliance on Regulation under the Securities Act and the applicable laws of each jurisdiction where such Issues and sales are made. There will be no public Issuing in the United States.*

SHAKUN

When industry giants speak, everyone listens.

In-depth **Q&As** with market mavens — *every Monday* in Business Standard.

To book your copy, SMS **reachbs** to **57575** or email **order@bsmail.in**

Business Standard
Insight Out

THIS IS A PUBLIC ANNOUNCEMENT FOR INFORMATION PURPOSES ONLY. THIS IS NOT A PROSPECTUS ANNOUNCEMENT AND DOES NOT CONSTITUTE AN INVITATION OR OFFER TO ACQUIRE, PURCHASE OR SUBSCRIBE TO SECURITIES. NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION, DIRECTLY OR INDIRECTLY OUTSIDE INDIA. INITIAL PUBLIC OFFERING OF EQUITY SHARES ON THE MAIN BOARD OF THE STOCK EXCHANGES IN COMPLIANCE WITH CHAPTER II OF THE SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (ISSUE OF CAPITAL AND DISCLOSURE REQUIREMENTS) REGULATIONS 2018, AS AMENDED.

PUBLIC ANNOUNCEMENT

(Please scan this QR code to view the Corrigendum)

H-T ®

HY-TECH ENGINEERS LIMITED

(TO BE LISTED ON THE MAIN BOARD OF BSE AND NSE)

Our Company was incorporated as '*Hy-Tech Engineers Private Limited*' as a private limited company under the provisions of the Companies Act, 1956, pursuant to a certificate of incorporation dated December 18, 1978, issued by Registrar of Companies, Maharashtra at Mumbai. Subsequently, our Company was converted into a public limited company and the name of our Company was changed to '*Hy-Tech Engineers Limited*' pursuant to a resolution passed by our Board on February 18, 2022, a special resolution passed by our Shareholders dated February 24, 2022 and a fresh certificate of incorporation dated March 23, 2022 was issued by the Registrar of Companies, Maharashtra at Mumbai. For details in relation to the changes in our Registered Office, see "*History and Certain Corporate Matters*" beginning on page 195 of the RHP.

Registered and Corporate Office: Plot No. A-160, Main Road, Wagle Industrial Estate, Thane - 400604, Maharashtra.**Contact Person**: Sai Yashwant Ranadive, Company Secretary and Compliance Officer; **Tel. No.**: +91 22 4097 1916;
E-mail: hytechcs@hy-techengineers.com; **Website**: www.hy-techengineers.com; **Corporate Identity Number**: U99999MH1978PLC020853

NOTICE TO INVESTORS
CORRIGENDUM TO THE RED HERRING PROSPECTUS DATED AUGUST 17, 2026 (THE "CORRIGENDUM")
OUR PROMOTERS ARE HEMANT TUKARAM MONDKAR, SUREKHA HEMANT MONDKAR AND ASHWIN HEMANT MONDKAR

INITIAL PUBLIC OFFER OF UP TO [●] EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹5 EACH ("EQUITY SHARES") OF HY-TECH ENGINEERS LIMITED ("COMPANY") FOR CASH AT A PRICE OF ₹ [●] PER EQUITY SHARE (INCLUDING A SHARE PREMIUM OF ₹ [●] PER EQUITY SHARE) (THE "OFFER PRICE") AGGREGATING UP TO ₹ [●] MILLION ("THE OFFER") COMPRISING A FRESH ISSUE OF UP TO [●] EQUITY SHARES AGGREGATING UP TO ₹ 600.00 MILLION BY OUR COMPANY (THE "FRESH ISSUE") AND AN OFFER FOR SALE OF UP TO 14,289,450 EQUITY SHARES CONSISTING OF UP TO 8,980,961 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹5 EACH AGGREGATING UP TO ₹[●] MILLION BY HEMANT TUKARAM MONDKAR AND UP TO 5,308,489 EQUITY SHARES OF FACE VALUE OF ₹ 5 EACH BY SUREKHA HEMANT MONDKAR JOINTLY WITH HEMANT TUKARAM MONDKAR AGGREGATING UP TO ₹[●] MILLION (COLLECTIVELY REFERRED TO AS THE "PROMOTER SELLING SHAREHOLDERS" AND SUCH EQUITY SHARES OFFERED BY THE PROMOTER SELLING SHAREHOLDERS, "OFFERED SHARES"). THE OFFER SHALL CONSTITUTE UP TO [●]% OF THE POST-OFFER PAID-UP EQUITY SHARE CAPITAL OF OUR COMPANY.

This Corrigendum is in reference to the Red Herring Prospectus dated August 17, 2026 filed with the Registrar of Companies, Mumbai-II at Navi Mumbai ("**RoC**") and thereafter with the Securities and Exchange Board of India ("**SEBI**"), BSE Limited ("**BSE**") and the National Stock Exchange of India Limited ("**NSE**", together with BSE, the "**Stock Exchanges**") on August 18, 2026.

In this regard, potential Bidders should note the following modification to the disclosures in the RHP:

1. The details in the row titled "*Maximum Bid*" in the table setting out of the details of the offer structure in "*Offer Structure*" on page on page 340 of the RHP, should be read as:

Particulars	QIBs	Non-Institutional Bidders	Retail Individual Bidders
Maximum Bid	Such number of Equity Shares in multiples of [●] Equity Shares of face value of ₹5 each not exceeding the size of the Offer (excluding the Anchor portion) subject to applicable limits	Such number of Equity Shares in multiples of [●] Equity Shares of face value of ₹5 each not exceeding the size of the Offer (excluding the QIB portion) subject to applicable limits	Such number of Equity Shares in multiples of [●] Equity Shares of face value of ₹5 each so that the Bid Amount does not exceed ₹0.20 million

The information in this Corrigendum modifies and updates the information (as applicable) in the RHP solely to the extent set out above. The RHP accordingly stands amended to the extent stated hereinabove and the above changes are to be read in conjunction with the RHP. However, this Corrigendum does not purport to, nor does it, reflect any change that has occurred from the date of filing of the RHP and accordingly does not include the changes and/or updates that will be included in the Prospectus. Please note that the information included in the RHP will be suitably updated, including to the extent updated by way of this Corrigendum, as may be applicable, in the Prospectus as and when filed with the RoC, and subsequently submitted with the SEBI and the Stock Exchanges. Investors should not rely on the Draft Red Herring Prospectus for any investment decision and should read the RHP along with this Corrigendum before making an investment decision with respect to the Offer.

This Corrigendum shall be available on the website of SEBI at www.sebi.gov.in, the websites of Stock Exchanges at www.nseindia.com and www.bseindia.com, the website of our Company at www.hy-techengineers.com and the websites of the Book Running Lead Manager, namely New Berry Capitals Private Limited at www.newberry.in. All capitalized terms used in this Corrigendum shall, unless the context otherwise requires, have the meanings ascribed to them in the RHP.

BOOK RUNNING LEAD MANAGER	REGISTRAR TO THE OFFER
New Berry CAPITALS MERCHANT BANKING | PCG EQUITY BROKING | PMS **New Berry Capitals Private Limited** A-201, Marathon NextGen Innova, Level 2, Ganpatrao Kadam Marg, Lower Parel, Mumbai, Maharashtra, India, 400013 **Contact No.:** +91 22 48818440 **Email:** ipo@newberry.in **Investor grievance email:** grievances@newberry.in **Contact Person:** Satish Mangutkar / Ankur Sharma **Website:** www.newberry.in **SEBI Registration Number:** INM000012999 **CIN:** U67190MH2007PTC174445	**Bigshare Services Private Limited** Office No. S6-2, 6th Floor, Pinnacle Business Park, Mahakali Caves Road, next to Ahura Centre, Andheri East, Mumbai-400093. **Contact No.:** +91 22 6263 8200 **Email:** ipo@bigshareonline.com **Investor grievance email:** investor@bigshareonline.com **Contact Person:** Babu Raphael **Website:** www.bigshareonline.com **SEBI Registration Number:** INR000001385 **CIN:** U99999MH1994PTC076534

For **HY-TECH ENGINEERS LIMITED**
On behalf of the Board of Directors
Sd/-
Sai Yashwant Ranadive
Company Secretary and Compliance Officer

Place: Mumbai
Date: August 19, 2026

Hy-Tech Engineers Limited is proposing, subject to applicable statutory and regulatory requirements, receipt of requisite approvals, market conditions and other considerations, to make an initial public offering of its Equity Shares and has filed the RHP with SEBI and the Stock Exchanges on August 18, 2026. The RHP shall be available on the website of SEBI at www.sebi.gov.in, and is available on the websites of the Stock Exchanges i.e. BSE and NSE at www.bseindia.com and www.nseindia.com, respectively, on the website of the Company at www.hy-techengineers.com and the website of the BRLM, i.e., New Berry Capitals Private Limited at www.newberry.in. Any potential investors should note that investment in equity shares involves a high degree of risk and for details relating to such risk, see "*Risk Factors*" beginning on page 17 of the RHP. Potential investors should not rely on the DRHP filed with SEBI and the Stock Exchanges, and should instead rely on their own examination of our Company and the Offer, including the risks involved, for making any investment decision.

The Equity Shares offered in the Issue have not been and will not be registered under the U.S. Securities Act or any other applicable law of the United States. Accordingly, the Equity Shares are being offered and sold outside of the United States in offshore transactions as defined in and in compliance with Regulation S under the U.S. Securities Act and the applicable laws of the jurisdiction where such offers and sales are made. The Equity Shares have not been and will not be registered, listed or otherwise qualified in any other jurisdiction outside India and may not be offered or sold, and Bids may not be made by persons in any such jurisdiction, except in compliance with the applicable laws of such jurisdiction.

Adfactors 309/26

एनटीए में सुधार के लिए क्या किया?

उच्चतम न्यायालय ने केंद्र सरकार से एनटीए में ठोस सुधारों का खाका पेश करने को कहा, अगली सुनवाई 3 हफ्ते बाद

भाविनी मिश्रा

उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को केंद्र सरकार से राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (एनटीए) में ठोस सुधारों का खाका पेश करने के लिए कहा। शीर्ष अदालत ने कहा कि नीट, जेईई जैसी बड़ी प्रवेश परीक्षाएं आयोजित कराने वाली एजेंसी को स्थायी और प्रौद्योगिकी-संचालित संस्था के रूप में मजबूत किया जाए। प्रवेश परीक्षाओं की सुरक्षा केवल अधिकारियों या मौजूदा प्रक्रियाओं के भरोसे नहीं छोड़ी जा सकती।

न्यायमूर्ति पी.एस. नरसिम्हा और न्यायमूर्ति आलोक आर्धे के पीठ ने कहा कि प्रश्न पत्र लीक होने की घटनाएं रोकने एवं प्रतियोगी परीक्षाओं की विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के लिए एनटीए को ठोस एवं विशिष्ट विशेषज्ञता वाले उन्नत बुनियादी ढांचे की आवश्यकता है। पीठ ने कहा, 'हमारा कर्तव्य यह सुनिश्चित करना है कि एक व्यवहारिक केंद्रीय संस्था विकसित हो, जिस पर देश के लोग गर्व कर सकें।' पीठ ने इस बात पर भी जोर दिया कि अनुभवी कर्मियों का बार-बार स्थानांतरण करने से एजेंसी के कामों में बाधा आ सकती है।

अदालत ने केंद्र सरकार को एक हलफनामा दाखिल कर यह बताने का निर्देश दिया कि इसरो के पूर्व अध्यक्ष के. राधाकृष्णन की अध्यक्षता वाली उच्च-स्तरीय समिति की सिफारिशों पर कितना अमल किया गया। यह भी बताया जाए कि क्या इस समिति के काम और सिफारिशों को नवगठित नंदन नीलेकणि समिति ने संशोधित किया है। इस मामले की सुनवाई अब तीन सप्ताह बाद होगी।

राधाकृष्णन समिति का गठन 2024 में नीट-यूजी परीक्षा से जुड़े विवाद के बाद किया गया था। इसने परीक्षा प्रणाली को मजबूत करने के लिए कई सुझाव दिए थे। इस साल गठित नीलेकणि समिति ने आर्टिफिशल इंटेलिजेंस और कंप्यूटर आधारित परीक्षा कराने की संभावना सहित तमाम प्रौद्योगिकी-आधारित सुधारों की जांच-परख की है। पीठ ने कहा कि सरकार को परीक्षा सुरक्षा, साइबर सुरक्षा, परीक्षा केंद्रों, गोपनीयता, अनुसंधान और विकास सहित अन्य कार्यों के लिए बनाए गए स्थायी बुनियादी ढांचे के बारे में विस्तार से बताना चाहिए। इसने परीक्षाओं में नकल या अन्य गड़बड़ी रोकने के लिए नियुक्त वरिष्ठ अधिकारियों और अन्य उपायों का पूरा विवरण तलब किया है।

न्यायाधीशों ने कहा कि परीक्षा से जुड़ी प्रौद्योगिकी लगातार विकसित होती रहेगी, इसलिए एनटीए को अपने बुनियादी ढांचे, डेटाबेस और अनुसंधान और विकास क्षमताओं को मजबूत करना होगा। केंद्र और एनटीए की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत को बताया कि सुरक्षित रूप से परीक्षाएं आयोजित कराने के लिए कई स्तरों पर कड़ी चौकसी पहले से ही बरती जा रही है।

उन्होंने बताया कि प्रश्नपत्र तैयार करने की प्रक्रिया को कई स्तरों का सुरक्षा चक्र से गुजरना पड़ता है। अंतिम प्रश्नपत्र सबसे आखिर में तैयार होते हैं। प्रश्नपत्रों को फिर सीसीटीवी और सुरक्षा निगरानी में सरकार द्वारा नामित प्रिंटिंग प्रेस में मुद्रित किया जाता है। उन्होंने कहा कि छपाई सुविधाओं को उस परीक्षा के बारे में सूचित नहीं किया जाता, जिसके लिए प्रश्नपत्र तैयार किए जा रहे हैं।

मेहता के अनुसार, सील किए गए प्रश्नपत्रों को जीपीएस लगे वाहनों के जरिये सुरक्षित बक्सों में भंडार तक ले जाया जाता है और परीक्षा आयोजित होने तक कड़ी सुरक्षा में रखा जाता है। प्रश्नपत्र केवल एनटीए के निर्देशों पर ही परीक्षा केंद्रों को जारी किए जाते हैं और इस पूरी प्रक्रिया की भी वीडियोग्राफी कराई जाती है। सर्वोच्च न्यायालय में यह कानूनी कार्यवाही नीट से जुड़ी अनियमितताओं और प्रश्नपत्र लीक के आरोपों के बाद उठे विवादों के बीच शुरू हुई है। अदालत ने 2024 की घटना में बड़े पैमाने पर लीक के कोई सबूत नहीं मिलने पर नई परीक्षा का आदेश देने से इनकार कर दिया था, जबकि परीक्षा प्रणाली में सुधार का निर्देश दिया था। दोबारा इसी तरह का विवाद उठने के बाद एनटीए में संरचनात्मक बदलावों की मांग करने वाली कई याचिकाएं सर्वोच्च अदालत में दाखिल की गई हैं।

ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन (आईएमए) के महासंघ द्वारा दायर याचिका में एजेंसी के पुनर्गठन, प्रश्नपत्रों की डिजिटल लॉकिंग, कंप्यूटर-आधारित जांच करने और केंद्र-वार परिणाम प्रकाशित करने की मांग की गई है। अन्य याचिकाओं में स्वतंत्र वैधानिक परीक्षा प्राधिकरण बनाने का अनुरोध अदालत से किया गया है।

फाइल फोटो

नीट पुन:परीक्षा पर याचिका वापस लेने की अनुमति

एक अन्य मामले में दिल्ली उच्च न्यायालय ने बुधवार को नीट-यूजी 2026 पुनः परीक्षा से संबंधित याचिका वापस लेने की अनुमति दे दी है। मुख्य न्यायाधीश डीके उपाध्याय और न्यायमूर्ति तेजस के. करिया के पीठ दो छात्रों की याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें स्कोरकार्ड में सुधार की मांग की गई थी। इसमें एक छोड़े गए प्रश्न के अंक और कथित गणना त्रुटियों में सुधार किए जाने की मांग शामिल है। उन्होंने एक विशेषज्ञ समिति के गठन और एनटीए को भविष्य की सरकारी परीक्षाएं आयोजित करने से रोकने का आदेश देने की भी मांग की है। अदालत ने कहा कि याचिका में प्रार्थनाओं का मिश्रित समूह था और याचियों से मांगी गई राहतों के बारे में स्पष्ट होने के लिए कहा। याचिका को अलग-अलग कार्यवाही दायर करने की स्वतंत्रता के साथ वापस ले लिया गया।

मुफ्त कोचिंग के लिए बन रहा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म

अहोना मुखर्जी

केंद्र सरकार ने छात्रों को मुफ्त कोचिंग प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय ऑनलाइन मंच विकसित करने का काम शुरू कर दिया है। इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए जरूरी पढाई की सामग्री, विशेषज्ञ मार्गदर्शन जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए मुफ्त ऑनलाइन कोचिंग देने की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लालकिले से अपने भाषण के दौरान की थी। उन्होंने कहा था कि इस कदम का उद्देश्य उन छात्रों की मदद करना है, जो महंगी कोचिंग का खर्च वहन नहीं कर सकते।

केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रह्लाद जोशी ने बुधवार को उच्च शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर इस पहल को आगे बढ़ाने के लिए किए जा रहे कामों की समीक्षा की। मंत्री ने 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, 'छात्रों के लिए एक केंद्रीय प्लेटफॉर्म बनाया जा रहा है, जो देश भर के इच्छुक छात्रों को उच्च-गुणवत्ता वाली शिक्षण सामग्री, विशेषज्ञ मार्गदर्शन देकर परीक्षाओं की सुव्यवस्थित तैयारी कराएगा।'

प्रह्लाद जोशी, शिक्षा मंत्री

सरकार पहले से ही शिक्षा मंत्रालय द्वारा आईआईटी कानपुर के सहयोग से विकसित एक मुफ्त शिक्षण मंच 'साथी' का संचालन करती है। यह मंच इंजीनियरिंग के लिए संयुक्त प्रवेश परीक्षा (जेईई), मेडिकल के लिए राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा (नीट) और सामान्य विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा (सीयूईटी) सहित कई परीक्षाओं की तैयारी के लिए सामग्री और मार्गदर्शन प्रदान करता है। प्रस्तावित राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म भी 'साथी' जैसा ही हो सकता है।

केंद्र सरकार ने यह कदम ऐसे समय उठाया है जब देश में प्रमुख प्रवेश परीक्षाओं में गड़बड़ी के आरोप लग रहे हैं। इन विवादों ने सरकार का ध्यान देश के कोचिंग पारिस्थितिकी तंत्र की ओर खींचा है। एक ओर, नीट के प्रश्नपत्र लीक होने में कई कोचिंग केंद्रों की भूमिका भी सवालों के घेरे में है। दूसरी ओर, लगातार महंगी होती निजी कोचिंग के कारण छात्रों, अभिभावकों और सरकार की चिंताएं बढ़ी हैं। विशेषज्ञों और शिक्षाविदों ने भी प्रवेश परीक्षाओं के लिए कड़ी प्रतिस्पर्धा के बीच कोचिंग केंद्रों के बढ़ते प्रभुत्व को उजागर किया है। इसमें कोचिंग केंद्रों द्वारा कदाचार की आशंका बढ़ रही है।

pib insurance brokers
PROTECT YOUR BUSINESS WITH CONFIDENCE
Comprehensive insurance solution for SMEs, corporates and property
LIABILITY & FINANCIAL LINES INSURANCE
ENGINEERING & INDUSTRIAL RISK INSURANCE
PROPERTY & FIRE INSURANCE
MARINE & LOGISTICS INSURANCE
EMPLOYEE BENEFITS & GROUP INSURANCE
GMC - Group Medical Cover
GPA - Group Personal Accident
GTL - Group Term Life Insurance
MOTOR & FLEET INSURANCE
MISCELLANEOUS INSURANCE SOLUTIONS
WHY CHOOSE US
Customized Solutions
Competitive Premiums
Dedicated Risk Advisory
Expert Claim Support
CONTACT US
info@pibinsurance.in
9820006729
www.pibinsurance.in

जम्मू-कश्मीर यात्रा परामर्श की समीक्षा करेगा अमेरिका

भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने बुधवार को कहा कि अमेरिका जम्मू-कश्मीर के लिए जारी यात्रा परामर्श की समीक्षा करेगा, क्योंकि केंद्र सरकार और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने क्षेत्र को अधिक सुरक्षित बनाने के लिए कदम उठाए हैं। गोर जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के दो दिवसीय दौरे पर बुधवार को श्रीनगर पहुंचे।

उन्होंने उमर के साथ एक संयुक्त प्रेस वार्ता में कहा कि जम्मू-कश्मीर भारत का अहम हिस्सा और एक बेहद खूबसूरत जगह है। गोर ने कहा, 'अमेरिका यात्रा से जुड़ी चेतावनियां जारी करता है और हम समय-समय पर इनकी समीक्षा भी करते हैं। मैं आज यहां कोई बड़ी घोषणा तो नहीं कर सकता, लेकिन हम इस मुद्दे पर विचार जरूर करेंगे।' उन्होंने कहा, 'हमारा मानना है कि नई दिल्ली, यहां के मुख्यमंत्री और यहां के प्रशासन ने इस क्षेत्र को और अधिक सुरक्षित बनाने के लिए कुछ बेहतरीन कदम उठाए हैं।'

गोर ने कहा, 'इसलिए हम इस बात पर विचार करेंगे कि क्या अमेरिका की ओर से जारी यात्रा चेतावनी के स्तर को कम किया जाना चाहिए, क्योंकि जैसा कि मैंने पहले कहा, यह एक खूबसूरत जगह है। मुझे लगता है कि बहुत से अमेरिकी जम्मू-कश्मीर आकर इसकी खूबसूरती का दीदार करना और यहां मौजूद अवसरों के बारे में जानना पसंद करेंगे।'

सर्जियो गोर और उमर अब्दुल्ला

उमर ने कहा कि उन्होंने गोर के साथ भारत और अमेरिका के बीच संबंधों पर चर्चा की, जिसमें जम्मू-कश्मीर पर खासतौर पर ध्यान दिया गया। उन्होंने कहा, 'यह एक बहुत अच्छी बैठक थी। हमें दोनों देशों के बीच संबंधों पर चर्चा करने का मौका मिला, जिसमें खासतौर पर इस बात पर ध्यान दिया गया कि अमेरिका जम्मू-कश्मीर के मामले में क्या कर सकता है।' उमर ने कहा कि उन्हें पूरी उम्मीद है कि आने वाले वर्षों में अमेरिका और जम्मू-कश्मीर के बीच संबंध 'और अधिक व्यापक तथा मजबूत' होंगे। **भाषा**

पेपर लीक मुद्दा गांव-गांव ले जाएगी कांग्रेस

एजेंसियां

कांग्रेस ने आरोप लगाया कि जिस समय चीन अरुणाचल प्रदेश में घुसपैठ कर रहा है, सरकार मूकदर्शक बनी है। वह आत्मसमर्पण की नीति अपना रही है। कांग्रेस कार्यसमिति की बुधवार को आयोजित बैठक में पेपर लीक, शिक्षा प्रणाली और अयोध्या के राम मंदिर में 'चढ़ावा चोरी' जैसे मुद्दों पर सरकार को जमीनी स्तर पर घेरने का संकल्प लिया गया।

नई दिल्ली स्थित इंदिरा भवन में संपन्न कांग्रेस कार्य समिति की बैठक की अध्यक्षता खरगे ने की। बैठक में पार्टी की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी, पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा, जयराम रमेश और केसी वेणुगोपाल सहित शीर्ष स्तर के 88 नेताओं ने भाग लिया और 33 नेताओं ने अपने विचार रखे।

बैठक के बाद संवाददाता सम्मेलन में वरिष्ठ नेता वेणुगोपाल ने कहा कि हम तीन-चार मुद्दों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। पहला मुद्दा पेपर लीक का है। बैठक में पेपर लीक के खिलाफ युवाओं के आंदोलन और उससे निपटने के सरकार के तरीके पर विस्तृत चर्चा हुई। इस बैठक में हुई विस्तृत चर्चा में संसद के मॉनसून सत्र को विपक्ष के लिए बेहद सफल बताया गया और कहा कि पूरे सत्र के दौरान सरकार बैकफुट पर रही। वेणुगोपाल ने कहा कि राहुल गांधी का 'छात्रों की गूंज' कार्यक्रम देश के 800 शहरों में आयोजित किया जाएगा। इनमें कई कार्यक्रमों में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष शामिल होंगे।

कांग्रेस अध्यक्ष खरगे ने पार्टी के मुख्यमंत्रियों से शिक्षा और परीक्षा प्रणाली में सुधार के लिए व्यापक रोडमैप तैयार करने के लिए शिक्षा विशेषज्ञों के साथ काम करने एवं उन्हें अपनी रिपोर्ट सौंपने को कहा है।

वेणुगोपाल ने कहा, 'राम मंदिर के चढ़ावे की चोरी देशवासियों के लिए बेहद चिंता का विषय है। यह लोगों की भावनाओं से जुड़ा मुद्दा है। जिन नेताओं ने देश के लोगों का ध्रुवीकरण करने के लिए राम मंदिर का इस्तेमाल किया, वे अब बेनकाब हो गए हैं।'

उन्होंने कहा, 'इस मुद्दे को जमीनी स्तर पर मजबूती से उठाने के लिए प्रदेश कांग्रेस समितियों को निर्देश दिया गया है, ताकि वे गांवों और पंचायतों तक लोगों को जागरूक करें।' बैठक में अगले साल की शुरुआत में होने वाले विधान सभा चुनावों की तैयारियों पर भी विचार-विमर्श हुआ। पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में अगले साल के शुरू में विधान सभा चुनाव होने हैं।

वेणुगोपाल ने कहा कि अरुणाचल में चीनी घुसपैठ के मुद्दे पर भी बैठक में चर्चा हुई। उन्होंने दोहराया कि लोक सभा की वर्तमान 543 सीटों की संख्या के आधार पर ही महिला आरक्षण लागू किया जाए। संवाददाता सम्मेलन में मौजूद जयराम रमेश ने खरगे के उत्तराखंड दौरे के बाद वहां हुए शुद्धिकरण कार्यक्रम पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से देश से माफी मांगने की मांग उठाई।

कांग्रेस कार्य समिति की इस बैठक में अंबिका सोनी, मुकुल वासनिक और पी. चिदंबरम जैसे वरिष्ठ नेता भी शामिल हुए। इनके अलावा कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी (तेलंगाना), वीडी सतीशन (केरल), सुखविंदर सिंह सुक्खू (हिमाचल प्रदेश) और डीके शिवकुमार (कर्नाटक) भी मौजूद थे।

सीडब्ल्यूसी अध्यक्ष सोनिया गांधी और पूर्व सांसद अंबिका सोनी

वंदेमातरम पर गांधी, नेहरू के फैसले का पालन होगा

कांग्रेस ने बैठक में वंदेमातरम को लेकर 1937 में महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभभाई पटेल और उस समय के अन्य प्रमुख नेताओं द्वारा किए गए फैसले का पूरी तरह पालन करने की बात कही। पार्टी ने कहा कि उस समय के शीर्ष नेताओं के फैसले के अनुरूप पार्टी कार्यकर्ता राष्ट्रगीत के सिर्फ दो अंतरे ही गाएंगे।

The questions shaping India.
Beyond the surface.
Towards perspective.

Macro Matters, Business Standard's fortnightly podcast, brings together Editorial Director A.K. Bhattacharya and Senior Editor Ankur Bhardwaj to decode the economic, policy and geopolitical shifts shaping India, and what they mean for business, markets and institutions.

Watch Now

कोलकाता: होटल में आग से 9 की मौत

मध्य कोलकाता की मिर्जा गालिब स्ट्रीट में स्थित एक जर्जर पांच मंजिला इमारत में मंगलवार देर रात भीषण आग लगने से चार वर्षीय बच्चे और दो महिलाओं समेत कम से कम 9 लोगों की मौत हो गई और 6 अन्य झुलस गए। पुलिस ने बताया कि इस इमारत में कई होटल संचालित हो रहे थे।

एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि, आग रात करीब 1 बज कर 45 मिनट पर लगी। आग बुझाने के लिए दमकल की 5 गाड़ियों को मौके पर भेजा गया। घटनास्थल पर पुलिस, दमकल और आपदा प्रबंधन विभाग के कर्मचारियों का बचाव अभियान जारी है। एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार, इस पांच मंजिला इमारत से 80 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। एक पुलिस अधिकारी ने बताया, 'घने धुएं के कारण दमकलकर्मियों के लिए सीढ़ियां चढ़ना और ऊपरी मंजिलों तक पहुंचना मुश्किल हो रहा था। 9 लोगों की मौत हो चुकी है और 6 झुलस गए हैं।'

मारे गए 9 लोगों में 5 बांग्लादेशी

होटल में लगी आग में मरने वाले 9 लोगों में 5 बांग्लादेशी नागरिक थे। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि स्थानीय पुलिस ने मृतकों में से 5 की पहचान बांग्लादेशी नागरिकों के रूप में की है। मंत्रालय ने बताया कि इन 5 बांग्लादेशी मृतकों में से 4 एक ही परिवार के थे। मारे गए लोगों में एक पत्रकार और उनके परिवार के 3 सदस्य शामिल थे। बयान के अनुसार, 6 अन्य बांग्लादेशी नागरिक आग में घायल हो गए थे और प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। कोलकाता स्थित बांग्लादेश उप उच्चायोग ने मृतकों के परिवारों से संपर्क किया है और घटना से प्रभावित बांग्लादेशी नागरिकों को आवश्यक सहायता मुहैया कराने के लिए अस्पतालों और स्थानीय पुलिस के संपर्क में है। **भाषा**

बैंक ऑफ़ इंडिया Bank of India BOI
स्टार हाउस, प्लॉट: सी-5, "जी" ब्लॉक, बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा (पूर्व), मुंबई 400 051
फोन: 022 66684645/5629,
ई-मेल आईडी: HeadOffice.AFD@bankofindia.bank.in
जेम पोर्टल के माध्यम से स्वर्ण शुद्धता परीक्षण मशीन की खरीद
बैंक ऑफ़ इंडिया ने जेम पोर्टल के माध्यम से स्वर्ण शुद्धता परीक्षण मशीन की खरीद के लिए बोलियां आमंत्रित की हैं। अधिक जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट https://bankofindia.bank.in या जेम पोर्टल https://gem.gov.in को देखें। यदि इसमें कोई बदलाव होता है, तो इसे बैंक की वेबसाइट और जेम पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा।
उप महाप्रबंधक
कृषि वित्त विभाग